चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

17 नवंबर–23 नवंबर 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

मोदी के लिए नई चुनौती

जनता परिवार

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

देश में एक बार फिर जनता परिवार के एकजुट होने के प्रयासों की चर्चा जोरों पर है. भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के उभार और कांग्रेस में लगातार बढ़ती उदासीनता के चलते यह प्रासंगिक और ज़रूरी भी है. वजह यह है कि आज देश एक सशक्त विपक्ष का अभाव झेलने को विवश है. और, सशक्त विपक्ष का अभाव हमेशा निरंकुशता को ही बढ़ावा देता है. जनता परिवार क्या चाहता है, उसकी क्या प्राथमिकताएं हैं, यही बता रही है इस बार की आमुख कथा.

संतोष भारतीय

बीता 6 नवंबर गुरु पर्व का दिन था और इसी दिन समाजवादी नेता, उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने अपने घर पर अपने परिवार के लोगों की बैठक बुलाई. मुलायम सिंह के परिवार का मतलब जनता परिवार से है. एक समय जनता परिवार ने देश में राज किया. चार प्रधानमंत्री दिए, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री चंद्रशेखर, श्री एचडी देवेगौड़ा और श्री इंद्र कुमार गुजराल. कई राज्यों में सालों साल जनता परिवार के लोगों की सरकार रही, लेकिन एक रोग घुन की तरह जनता परिवार में लग गया. आपस में विचारों को सामने रख, विचारों की ढाल बना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का एक ऐसा घुन, जिसने आपस में सबको तोड़ दिया. टूटते-टूटते अब सब अंतिम रूप में टूटने का ख़तरा देखने लगे. लगभग तीन घंटे चली बैठक में, जिसमें स्वयं श्री मुलायम सिंह यादव, देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा, बिहार के दो भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं श्री लालू प्रसाद यादव, श्री राम गोपाल यादव, श्री शिवपाल यादव, हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पौत्र एवं सांसद दुष्यंत चौटाला तथा केंद्र में मंत्री रहे और समाजवादी जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री कमल मोरारका शामिल थे. इस बैठक में जनता दल (यू) के अध्यक्ष श्री शरद यादव एवं महामंत्री श्री केसी त्यागी भी शामिल थे. तीन घंटे चली बातचीत में बिना किसी बहस के सबने लगभग एक ही दृष्टिकोण से बातें रखीं और वे बातें थीं कि हमें एकता की दिशा में बढ़ना चाहिए.

इस बैठक में किसने क्या कहा और क्यों कहा, इसके बारे में जानने से पहले यह जानते हैं कि आख़िर यह बात शुरू कहां से हुई. दरअसल, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तब दो लोगों के दिमाग में एक साथ यह बात आई. इनमें पहले बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे समाजवादी जनता पार्टी के अध्यक्ष कमल मोरारका थे. इन दोनों ने अलग-अलग जनता परिवार के एक होने की संभावनाएं तलाशनी शुरू कीं. बहुत जल्दी दोनों को यह पता चल गया कि दोनों एक ही दिशा में बात कर रहे हैं. नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान इस बात के लिए लालायित थे कि नवीन पटनायक एवं ममता बनर्जी के साथ मिलकर एक व्यापक मोर्चा बनाया जाए, लेकिन उस समय नवीन पटनायक एवं ममता बनर्जी व्यापक मोर्चे पर अनुकूल उत्तर देने से चूक गए और तब नीतीश कुमार को लगा कि सबसे पहले जनता परिवार को इकट्ठा करना चाहिए और जनता परिवार इकट्ठा हो जाता है, तो हम लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का अच्छी तरह मुक़ाबला कर सकते हैं. उस सारी प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस अपनी बुद्धिमानी की पराकाष्ठा पर थी और वह अपने वक्तव्यों, अपने प्रचार के तरीके और उम्मीदवारों के ग़लत चुनाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी या मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से वॉक ओवर देती चली आ रही थी. नीतीश कुमार चाहते थे कि उनकी बात मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव से हो, ताकि जनता परिवार को एक करने की मुहिम आगे बढ़ाई जा सके, पर सभी अपने-अपने राज्यों में बुरी तरह से व्यस्त थे. भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री एचडी देवेगौड़ा उस समय चाहते थे कि सभी मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन एक मोर्चे का गठन नहीं हो पाया और उसका परिणाम लगभग सभी ने देख लिया. मुलायम सिंह चार पर सिमट गए, लालू यादव भी चार पर सिमट गए, नीतीश कुमार को दो सीटें मिलीं, देवेगौड़ा जी को भी दो सीटें मिलीं और तब इन सबके समझ में आने लगा कि अगर हम एक नहीं होते हैं, तो हमें एक-एक करके नरेंद्र मोदी का भोजन बनना पड़ेगा.

शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव को सारे राजनीतिक अंतर्विरोधों को समझाया और मुलायम सिंह यादव अपने घर पर सबको आमंत्रित कर बैठक के लिए तैयार हो गए. स्वयं मुलायम सिंह यादव के कहने पर शिवपाल यादव ने सबको फोन भी किया और लिखित आमंत्रण भी भेजा. एक-दूसरे के संपर्क में ये सारे नेता थे, लेकिन कोई भी आपस में खुली बातचीत नहीं कर रहा था.

हरियाणा का चुनाव सामने था. ओम प्रकाश चौटाला ने पहल कर 14 सितंबर को अपने घर पर एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव,

(शेष पृष्ठ 2 पर)

मोदी का आदर्श ग्राम

पेज-03

अब्दुल्लाह परिवार का पतन शुरू हो गया है !

पेज-05

विकास के साथ राजनीति का जरिया बना फ्लाईओवर

पेज-06

साई की महिमा

पेज-12

मोदी के लिए नई चुनौती जनता परिवार

पृष्ठ एक का शेष

शरद यादव, नीतीश कुमार, केसी त्यागी, एचडी देवेगौड़ा और कमल मोरारका को आमंत्रित किया. ये सब लोग ओम प्रकाश चौटाला के घर पर मिले. जहां ओम प्रकाश चौटाला और उनके पुत्र अभय चौटाला मौजूद थे. इस बैठक में यह तय हुआ कि हमें एक होने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की मदद करनी चाहिए. इस फ़ैसले के परिणामस्वरूप नीतीश कुमार, मुलायम सिंह के भाई शिवपाल यादव, केसी त्यागी और शरद यादव चुनाव प्रचार में सभाएं करने के लिए तैयार हो गए. ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव के बीच में ही अदालत के आदेश पर जेल वापस जाना पड़ा. हरियाणा का चुनाव ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी बुरी तरह हारी और जब उस हार का विश्लेषण सब लोगों ने किया, तब उन्हें समझ में आया कि अगर वे सब ईमानदारी से एक नहीं होते हैं, तो सभी को हरियाणा की गति को प्राप्त होना पड़ सकता है.

लालू यादव के हृदय का ऑपरेशन मुंबई में हुआ था और वह स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे. स्वास्थ्य लाभ के बाद वह दिल्ली लौट आए. नीतीश कुमार लगातार इस बात की कोशिश कर रहे थे कि जनता परिवार के सभी लोगों को जल्दी से जल्दी बैठना चाहिए और इसमें उनका साथ एचडी देवेगौड़ा पूरी तरह से दे रहे थे. पहले यह तय हुआ कि 6 नवंबर को यानी गुरु पर्व के दिन दोपहर के भोजन पर सभी लोग दिल्ली में लालू यादव के घर पर मिलें. लालू यादव के घर पर इसलिए, क्योंकि उनके हृदय का ऑपरेशन हुआ था, वह स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे और कहीं जा नहीं सकते थे. नीतीश कुमार के इस प्रस्ताव के ऊपर लालू यादव ने एक दूरगामी फ़ैसला लिया और उनकी सलाह के आधार पर श्री मुलायम सिंह यादव के दिल्ली स्थित घर में इस बैठक का होना निश्चित हुआ.

इस सारे आयोजन में सबसे मुख्य भूमिका शिवपाल यादव की थी और दूसरी भूमिका केसी त्यागी की थी. शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव को सारे राजनीतिक अंतर्विरोधों को समझाया और मुलायम सिंह यादव अपने घर पर सबको आमंत्रित कर बैठक के लिए तैयार हो गए. स्वयं मुलायम सिंह यादव के कहने पर शिवपाल यादव ने सबको फोन भी किया और लिखित आमंत्रण भी भेजा. एक–दूसरे के संपर्क में ये सारे नेता थे, लेकिन कोई भी आपस में खुली बातचीत नहीं कर रहा था. इसमें लालू यादव का यह कहना था कि हमें तत्काल बैठकर क्या–क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए, इस पर खुले मन से बात करनी चाहिए.

जब 6 नवंबर को बैठक शुरू हुई, तो सबसे पहले मुलायम सिंह यादव ने नीतीश कुमार से कहा कि वह बताएं कि उनके दिमाग में क्या है. नीतीश कुमार ने बहुत साफ़ अंदाज में कहा कि क्या हमारे पास एक होने के अलावा कोई रास्ता बचता है. नीतीश कुमार का कहना था कि हमें एक पार्टी की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और जब हम एक पार्टी बनाएंगे, तभी देश को संदेश दे पाएंगे. नीतीश कुमार का यह भी कहना था कि कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का रोल भूल चुकी है और अपने लिए कोई भूमिका तय नहीं कर पा रही है. दूसरी तरफ़ वैचारिक विरोध के अभाव में नरेंद्र मोदी सारे देश में एक भ्रम का वातावरण पैदा कर लोगों को मुख्य मुद्दों से भटकाते जा रहे हैं. नीतीश कुमार के पहले भाषण में यह स्पष्ट था कि अगर सब एक नहीं होंगे, तो सभी अपने यहां सिमट जाएंगे. नीतीश कुमार की इस बात ने बैठक का एजेंडा तय कर दिया.

इसके बाद बैठक में लालू यादव, देवेगौड़ा, शरद यादव, दुष्यंत चौटाला और कमल मोरारका बोले. सभी ने एक स्वर से मुलायम सिंह यादव से आग्रह किया कि वह आगे बढ़ें और सब लोगों को आपस में इकट्ठा करने में सबसे वरिष्ठ नेता होने के नाते अपना ऐतिहासिक रोल निभाएं. श्री देवेगौड़ा का भाषण बहुत ही तार्किक और राजनीतिक सच्चाइयों को लिए हुए था. यह फ़ैसला हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा में सब एक–दूसरे से मिलकर मुद्दे उठाएंगे और एक साथ एकता दिखाकर

देवेगौड़ा जी का मानना है कि जब हम एक हो जाएंगे, तो ममता बनर्जी, जयललिता और नवीन पटनायक के सांसदों को मिलाकर हम लोग सौ के आसपास हो जाते हैं. यानी जनता परिवार की अगुवाई में बनने वाले एक नए फ्रंट में लगभग सौ सांसदों का ग्रुप जनता के सवालों को उठाने की कोशिश कर सकता है.

फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

सरकार को आईना भी दिखाएंगे. सवाल चाहे काले धन का हो, सवाल चाहे किसानों की ज़मीन के अधिग्रहण का हो, सवाल चाहे बेरोज़गारी का हो या सवाल महंगाई और भ्रष्टाचार का हो, सब पर सब लोग लगातार संपर्क में रहेंगे और लोकसभा एवं राज्यसभा में एक सख्त आवाज़ बुलंद करेंगे. सबने यह माना कि उनके चालीस से ज़्यादा सांसद राज्यसभा एवं लोकसभा में हो जाते हैं और अगर वे चालीस सांसद एक साथ लोकसभा एवं राज्यसभा में बहस करते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पैदा की गई भ्रामक तस्वीर का मुकाबला किया जा सकता है.

इस बैठक की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि किसी ने किसी का विरोध नहीं किया और बैठक के बाद बाहर आने के बाद भी सभी ने एक स्वर से एक बात कही. जिस जनता परिवार में पहले मैं बड़ा या तू बड़ा की बहस चलती थी और यह बीमारी तोड़ देती थी, वहां सबने एक स्वर से मुलायम सिंह यादव के सिर पर यह ज़िम्मेदारी सौंप दी कि वह सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ें. पहले यह तय हुआ कि प्रेस को केसी त्यागी ब्रीफ करेंगे, पर शरद यादव ने कहा, नहीं, नीतीश कुमार को प्रेस को ब्रीफ करना चाहिए. नीतीश कुमार ने प्रेस को ब्रीफ करते हुए साफ़ कहा कि आज हम पहली बार मिले, लेकिन हम एक पार्टी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. नीतीश कुमार ने बैठक की मुख्य बातों की जानकारी पत्रकारों को दी. इसने कम से कम यह बताया और शायद पिछले बीस सालों में पहली बार बताया कि जनता परिवार के पुराने लोग आपस में ईमानदारी से बातचीत करने का फ़ैसला कर चुके हैं.

इस बैठक में जनता परिवार के दो लोग शामिल नहीं थे. पहले अजित सिंह और दूसरे मुफ्ती मोहम्मद सईद. दरअसल, इन दोनों को इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि राजनीतिक भ्रम पैदा होते रहते हैं. हो सकता है कि अगली बैठक में अगर सब कुछ ठीक चलता रहा और मुलायम सिंह यादव के हाथ में इनिशिएटिव रहा, तो इन दोनों लोगों से भी बातचीत करके इनके शामिल होने का कोई रास्ता संभवत: निकल पाए.

देवेगौड़ा जी का मानना है कि जब हम एक हो जाएंगे, तो ममता बनर्जी, जयललिता और नवीन पटनायक के सांसदों को मिलाकर हम लोग सौ के आसपास हो जाते हैं. यानी जनता परिवार की अगुवाई में बनने वाले एक नए फ्रंट में लगभग सौ सांसदों का ग्रुप जनता के सवालों को उठाने की कोशिश कर सकता है. इन लोगों का यह भी मानना था कि लगभग 31 प्रतिशत वोट पर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है और लगभग 70 प्रतिशत वोट उसके पक्ष में नहीं है. इन्हें यह भी लगा कि नरेंद्र मोदी धीरे–धीरे मुद्दों को बदल रहे हैं, पर यह राजनीतिक विश्लेषण का विषय हो सकता है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु दूसरा है. वह बिंदु है, देश में विपक्ष के खाली स्थान को भरने का दृढ़ संकल्प.

लोकतंत्र में हमेशा विपक्ष का उतना ही महत्व रहा है, जितना सत्ता पक्ष का. और, यह कई मौक़ों पर देखा गया है कि अगर विपक्ष अपना सही रोल अदा करे, लोगों के मुद्दे उठाए, तो सरकारों को सही फ़ैसले लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है. अगर विपक्ष रहे ही नहीं, तो सरकार निरंकुश तरीके से अतार्किक फ़ैसले ले सकती है. इसलिए जनता परिवार की एकजुटता को सूक्ष्म निगाहों से देखें, तो यह देश की जनता को संगठित करने की ईमानदार कोशिश हो सकती है. दरअसल, पिछले दस सालों में लोगों की तकलीफों का मजाक उड़ा और जिस तरह से गांव–गांव में भ्रष्टाचार फैल गया, उसने जनता को कांग्रेस के ख़िलाफ़ विद्रोह करने पर मजबूर किया. जनता के हित के लिए बनी योजनाओं, जिनमें मनरेगा जैसी योजनाएं शामिल हैं, ने पंचायतों को भ्रष्टाचार के भाईचारे में शामिल कर दिया. भ्रष्टाचार के इस भाईचारे के खेल में ग्राम पंचायत के ख़िलाफ़ गांव का विद्रोह हो गया और किसी भी विकल्प के अभाव में लोगों ने एक पार्टी को नहीं, बल्कि एक व्यक्ति को वोट दे दिया और उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी था. नरेंद्र मोदी की भाषा, प्रचार, देश भर में घूमना और यह कहना कि मैं सारी परेशानियों से मुक्ति दिला दूंगा, लोगों को भा गया. और, शायद यही जनता परिवार को लगा होगा कि अगर हम एकजुट होते और सारे देश में चुनाव लड़ते, तो जनता हमें भी समर्थन दे सकती थी, क्योंकि इस परिवार में भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं. लालू यादव हैं, जिन्होंने अपने शुरू के पहले पांच सालों में हिंदुस्तान के ग़रीबों को सम्मान के साथ खड़े होने को राजनीतिक सवाल बनाया. इसमें मुलायम सिंह यादव हैं, जिनकी समाजवादी निष्ठा पर कभी कोई संदेह नहीं रहा. अगर उन पर कोई आरोप लग रहे हैं, तो वे उसी तरह के आरोप हैं, जो इस देश में राजनीति के लगभग हर नेता पर लग रहे हैं. हालांकि, वैसे आरोप भी नहीं लगने चाहिए. उन्हें अपनी छवि दूसरों से अलग दिखानी चाहिए.

यह माना जा सकता है कि मुलायम सिंह के घर पर हुई जनता परिवार की बैठक से देश में एक नई राजनीति की शुरुआत हो सकती है. अगर मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, देवेगौड़ा एवं ओम प्रकाश चौटाला ईमानदारी से एक पार्टी की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो वह पार्टी देश के परंपरागत राजनीतिक दलों, जिनमें भाजपा और कांग्रेस दोनों शामिल हैं, के लिए नई चुनौतियां पेश कर सकती हैं. अगले दो महीने देखने लायक हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए कुछ टिप्पणीकार मानते हैं कि यह यात्रा बहुत दूर तक साथ–साथ नहीं चलेगी, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि यह यात्रा बहुत लंबी चलेगी और इस बार वे अंतर्विरोध शामिल नहीं होंगे, जिन्होंने समाजवादी या कहें लोक नायक जयप्रकाश और डॉ. राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को धूमिल कर दिया था. हो सकता है, देश में एक बार फिर वैचारिक बहस की शुरुआत हो और जिसका सेहरा मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार के सिर पर बंधे. ■

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 06 अंक 37
दिल्ली, 17 नवंबर–23 नवंबर 2014
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060
+91–8451050786
+91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

अ-मित्रवत माहौल

हाल में जब केरल के नवनियुक्त राज्यपाल पी सथाशिवम दिल्ली आए, तो प्रोटोकॉल के अनुरूप उन्हें रिसीव करने न तो राज्य के रेजिडेंट कमिश्नर गणेश कुमार पहुंचे और न डिप्टी कमिश्नर बिस्वनाथ सिन्हा. सूत्रों का कहना है कि सथाशिवम राज्यपाल बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे थे और वह इस बात को लेकर नाराज़ थे कि उन्हें रिसीव करने सबसे वरिष्ठ अधिकारी की बजाय प्रोटोकॉल अधिकारी एवं एक जनसंपर्क अधिकारी आए. यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है कि उक्त अधिकारियों ने राज्यपाल की झुंझलाहट शांत करने के लिए अपनी अनुपस्थिति का कारण बताया या नहीं. पर्यवेक्षक इसी तरह की एक अन्य घटना याद करते हुए बताते हैं कि राज्य के महानिदेशक (अभियोजन) टी आसफ अली को केरल हाउस में लंच देने से मना कर दिया गया था, क्योंकि रेजिडेंट कमिश्नर का आदेश था कि केवल केरल हाउस में ठहरे मेहमानों को ही लंच दिया जाए. लेकिन, अंतत: कुछ फोन कॉल्स करने के बाद महानिदेशक ने वहीं पर अपने भोजन का प्रबंध कर लिया. ■

राजस्थान को बढ़त

मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय एवं बड़े मंत्रालयों के सर्वोच्च पदों पर केरल और दक्षिण भारत के अधिकारियों का बोलबाला था. मोदी सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय में मुख्य अधिकारी गुजरात कैडर के हैं, खासकर वे हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया था. लेकिन, अब ऐसा लग रहा है कि केंद्र में राजस्थान क्लब उभार पर है, क्योंकि राज्य के पूर्व मुख्य सचिव राजीव महिर्षी को हाल में वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है. सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में राजस्थान कैडर के 9 आईएएस अधिकारी मोदी सरकार में सचिव स्तर पर कार्यरत हैं, जिनमें दो राजस्थान के हैं. पहले महिर्षी और दूसरे 1980 बैच के आईएएस अधिकारी जी एस संधू, जो वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवाओं को देख रहे हैं. केंद्र में सेवाएं दे रहे राजस्थान के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों में अरविंद मायाराम, कृषि सचिव आशीष बहुगुणा, संगीता गिरोला (रक्षा विभाग), सुधीर भार्गव (सामाजिक न्याय) और ललित कुमार पंवार (अल्पसंख्यक मामले) शामिल हैं. फिलहाल लग रहा है कि मोदी सरकार में राजस्थान क्लब को बढ़त हासिल है. ■

विदेशी पद–स्थापना पर पाबंदी

जो वरिष्ठ नौकरशाह लंबे समय से विदेश में पदस्थ हैं और कई बार सेवा विस्तार करा चुके हैं, वे अब ऐसा नहीं कर पाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमओ को एक नई नीति बनाने का निर्देश दिया है, जिसमें 55 वर्ष से अधिक उम्र के नौकरशाहों की विदेश में प्रतिनियुक्ति नहीं हो सकेगी. सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने नौकरशाहों के केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने के लिए एक कट–ऑफ उम्र की घोषणा की है. सूत्रों का कहना है कि नई प्रस्तावित नीति दस सालों से विदेश में पदस्थ एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सेवा विस्तार के लिए दिए गए आवेदन का परिणाम है. जाहिर है, सरकार के लिए यह दु:खद विषय इसलिए है, क्योंकि कई नौकरशाह विदेश में कार्यकाल ख़त्म होने के बाद वापस भारत नहीं लौटते और उसी देश में बस जाते हैं, जहां उन्होंने सेवा दी. आईएएस अधिकारी नमिता दत्ता वाशिंगटन में विश्व बैंक में काम करने के बाद देश नहीं लौटीं. इसी तरह वरिष्ठ अधिकारी अतुल बगाई, राहुल आनंद, एलवी नीलेश भी भारत वापस नहीं लौटे. आशा है कि नई प्रस्तावित नीति आने के बाद इस चलन पर रोक लगेगी. ■

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

अजय और केवल अतिरिक्त सचिव बने

1984 बैच एवं हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी अजय त्यागी को आर्थिक मामलों के विभाग का अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है. वह इससे पहले पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे. वह वित्त मंत्रालय में 1983 बैच एवं कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी केपी कृष्णन का स्थान लेंगे. इसी तरह 1983 बैच एवं यूटी कैडर के आईएएस अधिकारी केवल कुमार शर्मा को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है. वह एबी जोशी की जगह लेंगे.

सत्पथी अंतरराज्यीय काउंसिल के सलाहकार

1980 बैच एवं इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेस के अधिकारी बीएन सत्पथी को अंतरराज्यीय काउंसिल सचिवालय का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है. यह पद अतिरिक्त सचिव के समकक्ष है.

संधू ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक नियुक्त

1984 बैच एवं पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी करनबीर सिंह संधू को जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइफेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है. वह अशोक कुमार अनगुराना का स्थान लेंगे. वह इससे पहले आवास एवं शहरी ग़रीबी उपशमन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

आम आदमी पार्टी ने अपना आधार बढ़ाने के लिए मिशन विस्तार जैसे कार्यक्रम भी चलाए. जेजे क्लस्टर, निम्न–मध्य वर्ग, रेहड़ी–पटरी, छोटे दुकानदार, ऑटो वालों ने दिसंबर 2013 के चुनाव में इस पार्टी को भरपूर समर्थन दिया था और यह तबका अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ है. लेकिन, पार्टी की सबसे बड़ी चिंता है दिल्ली का मध्य वर्ग. दिसंबर 2013 में इस वर्ग की एक बड़ी संख्या ने आम आदमी पार्टी को खुलकर समर्थन दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में यह वर्ग इसके हाथ से खिसक कर भाजपा की ओर चला गया. नतीजतन, दिल्ली की सात लोकसभा सीटों में से एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिली.

मोदी का आदर्श ग्राम

मनीष कुमार

दिल्ली हो या गुजरात हो या फिर बनारस का एक गांव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी बोलते हैं, उन्हें पूरा देश सुनता है. बनारस के जयापुर गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें आदर्श ग्राम को लेकर कहीं, उनसे आदर्श ग्राम की योजना को लेकर जनता में कन्फ्यूजन फैल गया. मोदी के भाषण की जिन बातों को मीडिया में हाइलाइट किया गया, उससे लोग और भी ज़्यादा भ्रमित हैं. मोदी ने कहा कि आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव में सरकारी पैसा नहीं आएगा. अब लोगों को लग रहा है कि अगर पैसे नहीं आएंगे, तो बुनियादी ढांचे का निर्माण कैसे होगा. क्या गांव वाले अपने पैसे से स्कूल–अस्पताल बनावाएंगे. दूसरी बात यह कि आदर्श ग्राम योजना के तहत लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी. अब यह कैसे होगा, इस पर उन्होंने खुलकर नहीं बताया. जबकि जो लोग गांव एवं पंचायती व्यवस्था से वाकिफ हैं, उन्हें पता है कि विभिन्न योजनाओं के नाम पर दिया जाने वाला पैसा पंचायत के अधिकारी और अन्य सरकारी अधिकारी मिल–बांट कर चट कर जाते हैं. यह भी लोगों को पता चल चुका है कि लोकल–सेल्फ गवर्नेंस के नाम पर लोगों के अधिकारों की जगह भ्रष्टाचार समाज के निचले स्तर तक पहुंच चुका है.

जयापुर में अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने आदर्श ग्राम को लेकर किसी रणनीति के बारे बात न करके लोगों का भ्रम बढ़ा दिया है. प्रधानमंत्री ने यह कहकर भी सबको चौंका दिया कि अब लोगों को हर काम के लिए सरकार पर आश्रित रहने की आदत ख़त्म कर देनी चाहिए. कहने का मतलब यह कि हर काम सरकार करे, इसकी अपेक्षा अब देश के लोगों को नहीं करनी चाहिए. उनके इस वाक्य से और ज़्यादा भ्रम फैला है, क्योंकि तब तो लोग यह जानना चाहेंगे कि अगर सब कुछ जनता को ही करना है, तो सरकार क्या करेगी. प्रधानमंत्री ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने, अभिभावकों को स्कूल जाकर व्यवस्था देखने, हर गांव का अपना गीत, गांव का जन्मदिन, बड़े पेड़ की पहचान और बुजुर्गों से संवाद जैसे बिंदुओं पर बातें कीं. प्रधानमंत्री आदर्श गांव के निर्माण की रणनीति, आदर्श ग्राम का प्रारूप, संस्थागत परिवर्तन और उसमें लोगों की भूमिका के बारे में साफ़गोई से बताने में चूक गए. यह कन्फ्यूजन न सिर्फ़ आम लोगों में है, बल्कि कई सारे सांसदों में भी है, जिन्हें अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि आदर्श ग्राम योजना को वे किस तरह से अपने क्षेत्र में लागू करें.

हक़ीक़त यह है कि देश में गांवों की हालत ठीक नहीं है. वहां ज़िंदगी बसर करना मुश्किल होता जा रहा है. समस्याओं की एक लंबी फेहरिस्त है. आज गांवों में पीने के लिए साफ़ पानी तक नहीं है, बिजली नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है. पिछड़ेपन का असर सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर साफ़ दिखाई देने लगा है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्रामीण जीवन का ताना–बाना चरमरा गया है. लोग गांव से पलायन कर रहे हैं. किसान खेती छोड़कर शहर में मज़दूरी करने लगे हैं. खेती में अब फ़ायदा नहीं होता. गांव का आर्थिक विकास रुक गया है. शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, इसलिए गांव में नौजवानों के कौशल का विकास नहीं हो पाता. वे शहरों–महानगरों में अप्रशिक्षित मज़दूरों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं. गांव वालों की ज़िंदगी एक अजीबोग़रीब कुचक्र में फंस जाती है, जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है. इसका सीधा असर न सिर्फ़ आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक तौर पर होता है, बल्कि यही अपराध को भी जन्म देता है. मोदी को गांव की समस्याएं मालूम हैं. यही वजह है कि पिछले 67 सालों में पहली बार केंद्र सरकार की नीतियों में गांव को इतनी प्रमुखता दी गई है.

लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की. इस योजना के तहत लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद एक गांव चुनेंगे और उसका विकास करेंगे. आदर्श ग्राम योजना महात्मा गांधी के विजन और विचारों को साथ रखकर तैयार की गई है. विकास, रोज़गार एवं बुनियादी ढांचे के निर्माण के अलावा गांव में नैतिकता के साथ आधुनिकता का पाठ भी पढ़ाया जाएगा. समाज के सभी वर्गों की भागीदारी, विशेष कर निर्णय लेने में सुनिश्चित की जाएगी. आपसी सहयोग, स्व–सहायता, आत्मनिर्भरता और गांव के विभिन्न समुदायों के बीच आपसी सौहार्द्र बढ़ाने पर बल दिया जाएगा. सार्वजनिक जीवन में भी पारदर्शिता और जवाबदेही तय होगी. गांव में सभी ग़रीबों को भोजन उपलब्ध कराने के साथ–साथ लैंगिक समानता और महिलाओं के लिए सम्मान सुनिश्चित करना प्राथमिकता में होगा. आदर्श ग्राम का चुनाव सांसद करेंगे और अगर सांसद नहीं पाते हैं, तो यह काम ज़िला प्रशासन का होगा.

इस योजना के तहत ग्राम पंचायत बुनियादी इकाई होगी. मैदानी इलाकों में जहां गांव की जनसंख्या तीन से पांच हज़ार और पहाड़ी इलाकों में एक से तीन हज़ार होगी. 2024 तक सभी गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इन गांवों में स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय, व्यायाम एवं खेल के लिए मैदान जैसी सुविधाएं होंगी. लोगों को ई–साक्षर किया जाएगा. गांव को हिंसा और अपराध मुक्त बनाया जाएगा. गांव दिवस मनाने के साथ ही हर घर में और सभी सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय का निर्माण कराया जाएगा. आदर्श ग्राम योजना का मतलब मजबूत और जवाबदेह ग्राम पंचायतों एवं ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र की स्थापना है. सभी के पास यूआईडी कार्ड, ई–शासन, समयबद्ध सेवा, स्थानीय भाषा में दीवारों पर योजना एवं उसके निस्तारण की तिथि का अंकन आदि बिंदु इसमें शामिल हैं. किस मद में कितनी धनराशि का बजट है, कितना खर्च हुआ है, यह भी दीवारों पर अंकित करना होगा. शिकायत निवारण केंद्र बनाया जाएगा. शिकायत मिलने पर उसका निवारण लिखित उत्तर के साथ तीन सप्ताह के भीतर किया जाएगा. गांवों में रोज़गार एवं आर्थिक विकास के लिए पशुधन, बागवानी सहित विविध प्रकार की कृषि और संबद्ध आजीविका को बढ़ावा दिया जाएगा. जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पर्यावरण विकास, सड़क के किनारे पौधारोपण और बिजली की व्यवस्था की जाएगी. सभी पात्र परिवारों को पेंशन मिलेगी, जिसमें वृद्धावस्था, विकलांगता एवं विधवा पेंशन भी शामिल होगी. स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और अनाज के लिए पीडीएस की सुविधा होगी. इस योजना में कहीं से कोई कमी नहीं है, लेकिन 67 सालों का अनुभव सिर्फ़ एक ही सवाल को जन्म देता है और वह है कि क्या इस बेहतरीन योजना का सफल कार्यान्वयन हो सकेगा या नहीं. वैसे उम्मीद करनी चाहिए कि यह अच्छे ढंग से लागू हो.

किल्लत की ज़िंदगी से जूझ रहे भोले–भाले ग्रामीणों की ज़रूरतें ज़्यादा नहीं हैं. ग्रामीण जीवन को वापस पटरी पर लाने के लिए वे सिर्फ़ कृषि क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन चाहते हैं, ताकि कृषि में किसानों का फ़ायदा बढ़े. किसानों के उत्पाद को बाज़ार से जोड़ना ज़रूरी है, उद्योग से जोड़ना ज़रूरी है, ताकि गांव के लोगों की आय में वृद्धि हो सके. नौज़वानों को शिक्षा मिले. ऐसी शिक्षा, जो कौशल विकास से जुड़ी हो और जिससे उन्हें रोज़गार मिल सके. गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये दो उपाय सबसे ज़्यादा अनिवार्य हैं. इसके बाद ही गांव को आदर्श गांव में तब्दील करने वाली कोई भी योजना कारगर और सफल हो सकेगी. ■

manishbph244@gmail.com

दिल्ली

चुनौती सबके लिए है...

शशि शेखर

दिल्ली का चुनाव तीनों प्रमुख पार्टियों के लिए इम्तिहान की घड़ी है. आम आदमी पार्टी के लिए जहां यह चुनाव जीने–मरने का सवाल है, वहीं कांग्रेस के लिए अपने अस्तित्व में फिर से जान फूंकने का मौक़ा है. भाजपा के लिए यह चुनाव सिर्फ़ इतना भर है कि उसे अपना प्रदर्शन बरकरार रखना है. हालांकि, दिल्ली देश की राजधानी है और इसका राजनीति में प्रतीकात्मक महत्व भी है. इस लिहाज से भाजपा दिल्ली चुनाव को हल्के में नहीं ले सकती.

बहरहाल, अब यह तय हो गया है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है. संभवत: यह झारखंड एवं जम्मू–कश्मीर चुनाव के बाद हो, लेकिन चुनावी सरगर्मी अभी से तेज हो गई है. पोस्टर वार शुरू हो चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी सबसे आगे नज़र आ रही है. चूंकि आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह की पोस्टरबाजी संभव नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में पोस्टरों के जरिये चुनावी शंखनाद कर दिया है. कांग्रेस और भाजपा अभी कमर कस ही रही हैं.

आम आदमी पार्टी अगर इस चुनाव को लेकर अभी से इतनी मुखर दिख रही है, तो यह जायज भी है, क्योंकि दिल्ली में यही ऐसी पार्टी है, जिसका भविष्य इस चुनाव से जुड़ा हुआ है. दिसंबर 2013 में किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि इसे 28 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ और फिर इसने कांग्रेस के समर्थन से सरकार भी बनाई. अचानक इस पार्टी का राजनीतिक ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा. समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं की संख्या में तेजी से इजाफ़ा हुआ. लेकिन, 49 दिनों के बाद जैसे ही अरविंद केजरीवल ने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद से और खासकर लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद इस पार्टी के अच्छे दिन ख़त्म होने लगे. समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं की संख्या में भी कमी आने लगी.

आम आदमी पार्टी ने अपना आधार बढ़ाने के लिए मिशन विस्तार जैसे कार्यक्रम भी चलाए. जेजे क्लस्टर, निम्न–मध्य वर्ग, रेहड़ी–पटरी, छोटे दुकानदार, ऑटो वालों ने दिसंबर 2013 के चुनाव में इस पार्टी को भरपूर समर्थन दिया था और यह तबका अभी भी आम आदमी पार्टी के साथ है. लेकिन, पार्टी की सबसे बड़ी चिंता है दिल्ली का मध्य वर्ग. दिसंबर 2013 में इस वर्ग की एक बड़ी संख्या ने आम आदमी पार्टी को खुलकर समर्थन दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में यह वर्ग इसके हाथ से खिसक कर भाजपा की ओर चला गया. नतीजतन, दिल्ली की सात लोकसभा सीटों में से एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिली.

लोकसभा चुनाव के बाद से ही दिल्ली का मध्य वर्ग इस पार्टी से अलग है. आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में फिर से सत्ता पाना चाहती है, तो इसे इस वर्ग विशेष को अपने साथ लाना ही होगा. आम आदमी पार्टी की ताकत की बात करें, तो इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल की स्वच्छ छवि ही है. 49 दिनों की सरकार के दौरान किए गए इनके कामों से भी दिल्ली का एक तबका खुश दिखता है, लेकिन सामान्य तौर पर लोगों की सबसे बड़ी शिकायत सरकार द्वारा इस्तीफ़ा देने को लेकर है. अब अरविंद केजरीवाल कैसे यह शिकायत दूर कर पाते हैं, कैसे मध्य वर्ग को अपनी ओर खींच पाते हैं, कैसे अपने मतदाताओं को एकजुट रख पाते हैं और कैसे भाजपा को कड़ी चुनौती पेश कर पाते हैं, इन्हीं सबके आधार पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की किस्मत का फ़ैसला होगा.

दूसरी तरफ़ भाजपा है, जो लोकसभा चुनाव के बाद लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है. उसकी चुनौती सिर्फ़ इतनी है कि वह दिल्ली में सत्ता हासिल कर ले. पिछले विधानसभा चुनाव में भी 32 सीटों के साथ वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. लोकसभा चुनाव के दौरान उसे दिल्ली में 41 फ़ीसद मत मिले थे और क़रीब 60 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल हुई थी. ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश है और जीतने का भरोसा भी. फिलहाल, दिल्ली में उसके पास एक भी ऐसा चेहरा नहीं है, जिसे आगे करके

आम आदमी पार्टी अगर इस चुनाव को लेकर अभी से इतनी मुखर दिख रही है, तो यह जायज भी है, क्योंकि दिल्ली में यही ऐसी पार्टी है, जिसका भविष्य इस चुनाव से जुड़ा हुआ है. दिसंबर 2013 में किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि इसे 28 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ और फिर इसने कांग्रेस के समर्थन से सरकार भी बनाई.

वह चुनाव लड़े. हर्षवर्धन के केंद्र में मंत्री बनने के बाद दिल्ली भाजपा में कोई सर्वमान्य चेहरा अभी नज़र नहीं आता. कभी–कभार जगदीश मुखी का नाम ज़रूर सामने आता है, जो अपेक्षाकृत एक स्वच्छ छवि के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन फिर भी भाजपा ने अपने किसी नेता की घोषणा नहीं की है. यह तय है कि भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव भी नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व के सहारे और केंद्र सरकार के पिछले 6 महीनों के कामकाज को आधार बनाते हुए लड़ेगी. हालांकि, इसी मुद्दे को अरविंद केजरीवाल उछालेंगे और कहेंगे कि दिल्ली भाजपा के पास कोई नेता तक नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री को विधानसभा चुनाव में आगे किया जा रहा है. लेकिन यह राजनीति है, जहां आदर्श वाक्यों से ज़्यादा महत्व हार और जीत का है. यह बात भाजपा अच्छी तरह जानती है. महाराष्ट्र एवं हरियाणा में नरेंद्र मोदी के सहारे जीत हासिल करने वाली भाजपा दिल्ली में भी जीतना चाहती है.

बात अगर कांग्रेस की करें, तो उसके पास दिल्ली में खुद को स्थापित करने के लिए शायद यह अंतिम मौक़ा है. इस बार अगर कांग्रेस अपनी स्थिति ठीक नहीं कर पाती है, तो शायद अगले दो–तीन दशकों तक दिल्ली से वह उसी तरह गायब रहेगी, जैसे अभी बिहार और उत्तर प्रदेश से गायब है. दरअसल, कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती है, अपना वह मतदाता वर्ग आम आदमी पार्टी से खींच कर अपनी तरफ़ वापस लाना, जो पिछले विधानसभा चुनाव में उससे अलग हो गया था. लोकसभा चुनाव से मुस्लिम मतदाता भी कांग्रेस से अलग हुआ है. बदली परिस्थितियों में कांग्रेस को सत्ता मिलना नामुमकिन है, लेकिन उसके लिए अपनी मौजूदा सीटें बचाते हुए उन्हें और बढ़ाना ही सबसे बड़ी सफलता होगी. कांग्रेस की दिक्कत है नेता का अभाव. अभी तक शीला दीक्षित ने यह साफ़ नहीं किया है कि वह इस विधानसभा चुनाव में भाग लेंगी या नहीं. अरविंदर सिंह लवली लोकप्रिय नेता तो हैं, लेकिन वह ऐसा चेहरा नहीं हैं, जो अकेले दम पर दिल्ली विधानसभा चुनाव की नैय्या पार लगवा सके. ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

दरअसल, आजम ने सारी नौटंकी अमर सिंह की सपा में वापसी रोकने के लिए की. इसमें प्रो. राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव ने उनका साथ दिया और पुरस्कार में वह अपनी पत्नी के लिए राज्यसभा का टिकट पा गए. इसके बावजूद यह कोशिश हुई कि सपा के अतिरिक्त वोटों के समर्थन से अमर सिंह को राज्यसभा में जगह मिल जाए, लेकिन इस पर भी पानी फेरते हुए कांग्रेस प्रत्याशी पीएल पुनिया को समर्थन दे दिया गया. राज्यसभा को लेकर राहुल गांधी का पुनिया–प्रयोग कांग्रेस में भीषण विरोध और अंतर्कलह का कारण बन गया है.

जेलों में अल्पसंख्यक कैदियों की संख्या घटी

ए. यू. आसिफ

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की विभिन्न जेलों में अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम एवं ईसाई कैदियों की संख्या में गिरावट आई है. बीते 29 अक्टूबर को प्रिजन स्टैटिक्स इंडिया रिपोर्ट–2013 शीर्षक से जारी अपनी इस रिपोर्ट में एनसीआरबी ने बताया है कि 31 दिसंबर, 2013 तक देश की कुल 1391 जेलों में 4 लाख 11 हज़ार 992 लोग कैद थे, जबकि उनकी क्षमता मात्र 3 लाख 47 हज़ार 859 बंदियों की है. कुल बंदियों में विचाराधीन 67.6 प्रतिशत, सजायाफ्ता 31.5 प्रतिशत एवं सिविल मामलों में हिरासत में लिए गए 0.9 प्रतिशत थे.

विशेष बात यह कि 2013 में बंदियों की कुल संख्या में मुसलमान 19.7 प्रतिशत थे, जबकि 2009 में वे 30 प्रतिशत थे. ग़ौरतलब है कि 29 अक्टूबर, 2006 को अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार सीमा चिश्ती की एक विशेष रिपोर्ट में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अप्रकाशित भाग के हवाले से बताया गया था कि महाराष्ट्र (10.6 प्रतिशत मुस्लिम आबादी) में मुस्लिम बंदी 32.4 प्रतिशत, गुजरात (मुस्लिम आबादी 9.06 प्रतिशत) में मुस्लिम बंदी 25 प्रतिशत से अधिक, असम (मुस्लिम आबादी 30.9 प्रतिशत) में मुस्लिम बंदी 28.1 प्रतिशत एवं कर्नाटक (मुस्लिम आबादी 12.23 प्रतिशत) में मुस्लिम बंदी 17.5 प्रतिशत थे. उस समय देश की विभिन्न जेलों में बंदियों की कुल संख्या एक लाख दो हज़ार 652 थी. मतलब यह है कि 2006 और 2009 की तुलना में 2013 में मुस्लिम बंदियों की संख्या 10 प्रतिशत से अधिक घटी है. एनसीआरबी की इस रिपोर्ट के अनुसार, 31 दिसंबर, 2013 को देश में हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या 3113 थी, जिनमें 613 (19.7 प्रतिशत) मुसलमान थे, जबकि 2009 में हिरासत में लिए गए कुल लोगों में 676 (30.3 प्रतिशत) मुसलमान थे.

आइए देखते हैं कि 2009 से लेकर 2013 तक धार्मिक समूह के लिहाज से स्थिति क्या थी. 2009 में कुल 2232 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें हिंदू 1246 (55.80 प्रतिशत), मुस्लिम 676 (30.3 प्रतिशत) एवं ईसाई 281 (12.6 प्रतिशत) थे. इसी तरह 2010 में कुल 2325 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें हिंदू 1345 (57.84 प्रतिशत), मुस्लिम 717 (30.83 प्रतिशत) एवं ईसाई 243 (10.4 प्रतिशत) थे. 2011 में कुल 2450 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें हिंदू 1485 (60.6 प्रतिशत), मुस्लिम 650 (26.5 प्रतिशत) एवं ईसाई 254 (10.4 प्रतिशत) थे. 2012 में कुल 1922 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें हिंदू 1203 (62.6 प्रतिशत), मुस्लिम 543 (28.2 प्रतिशत) एवं ईसाई 116 (06 प्रतिशत) थे. 2013 में कुल 3113 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें हिंदू 2144 (68.9 प्रतिशत), मुस्लिम 613 (19.7 प्रतिशत) एवं ईसाई 248 (7.9 प्रतिशत) थे.

यही स्थिति कमोबेश विचाराधीन एवं सजायाफ्ता कैदियों के मामले में है. वर्ष 2009 में देश की विभिन्न जेलों में विचाराधीन कैदियों की कुल संख्या 2 लाख 50 हज़ार 204 थी, जिनमें हिंदू एक लाख 73 हज़ार 732 (69.4 प्रतिशत) एवं मुस्लिम 56 हज़ार 229 (22.5 प्रतिशत) थे. जबकि 2013 में यह संख्या 2 लाख 78 हज़ार 503 थी, जिनमें हिंदू एक लाख 92 हज़ार 202 (69 प्रतिशत) एवं मुस्लिम 57 हज़ार 936 (21 प्रतिशत) थे. वर्ष 2009 में जेलों में सजायाफ्ता कैदियों की कुल संख्या एक लाख 23 हज़ार 941 थी, जिनमें हिंदू 90 हज़ार 57 (72.7 प्रतिशत) एवं मुस्लिम 22 हज़ार 946 (18.5 प्रतिशत) थे. वर्ष 2013 में सजायाफ्ता कैदियों की कुल संख्या एक लाख 29 हज़ार 608 थी, जिनमें हिंदू 93 हज़ार 273 (72 प्रतिशत) एवं मुस्लिम 22 हज़ार 145 (17.1 प्रतिशत) थे. यहां भी मुस्लिम 1.4 प्रतिशत कम हो गए यानी 2009 में 22,946 की तुलना में कम होकर वे 2013 में 22,145 पर आ गए.

अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार सीमा चिश्ती की एक विशेष रिपोर्ट में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अप्रकाशित भाग के हवाले से बताया गया था कि महाराष्ट्र (10.6 प्रतिशत मुस्लिम आबादी) में मुस्लिम बंदी 32.4 प्रतिशत, गुजरात (मुस्लिम आबादी 9.06 प्रतिशत) में मुस्लिम बंदी 25 प्रतिशत से अधिक, असम (मुस्लिम आबादी 30.9 प्रतिशत) में मुस्लिम बंदी 28.1 प्रतिशत एवं कर्नाटक (मुस्लिम आबादी 12.23 प्रतिशत) में मुस्लिम बंदी 17.5 प्रतिशत थे.

ईसाई, जो देश की कुल आबादी में 2.3 प्रतिशत हैं, हिरासत में लिए गए लोगों में उनकी संख्या 2009 में 12.6 प्रतिशत थी, जबकि 2013 में यह आंकड़ा 7.9 प्रतिशत आ पहुंचा. ग़ौरतलब है कि हिरासत में लिए गए लोगों में हिंदुओं की संख्या में इजाफा हुआ है. 2009 में यह संख्या 55.8 प्रतिशत थी, जबकि 2013 में 68.9 हो गई. वहीं विचाराधीन एवं सजायाफ्ता कैदियों के मामले में उनकी संख्या में कमी आई है. 2009 में यह संख्या 69.4 प्रतिशत थी, जो 2013 में घटकर 69 प्रतिशत हो गई.

इन तमाम बातों से निष्कर्ष यह निकलता है कि अल्पसंख्यकों यानी मुस्लिम एवं ईसाई कैदियों की संख्या, चाहे वह हिरासत का मामला हो, विचाराधीन का हो एवं फिर सजायाफ्ता यानी तीनों ही मामलों में घटी है. हिंदुओं की संख्या भी विचाराधीन एवं सजायाफ्ता मामले में घटी है, जबकि हिरासत में लिए गए लोगों में इनकी संख्या बढ़ी है. हिरासत में लिए गए लोगों में हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों एवं ईसाइयों की संख्या में 2009 या उससे पहले बढ़ोत्तरी की वजह 2001 में 9/11 के हमले के बाद बने पोटा कानून के तहत हुई अंधाधुंध गिरफ्तारियां हैं. जब अदालत को ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सुबूत नहीं मिले, तो उन्हें रिहा कर दिया गया. नतीजा यह हुआ कि हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या घटती चली गई.

इस स्थिति में ऐसा महसूस होता है कि अदालत की निष्पक्ष भूमिका के कारण जेलों में अल्पसंख्यकों की संख्या कम होती जा रही है. उम्मीद है कि कमी का यह रुझान और बढ़ेगा, जो अल्पसंख्यकों के लिए निश्चय ही एक शुभ संकेत है. अगर वास्तव में ऐसा होता है, तो पहले टाडा और बाद में पोटा लागू होने के बाद ऐसे लोगों की संख्या में जो बढ़ोत्तरी हुई थी, उसमें निश्चय ही गिरावट आएगी. टाडा के तहत 55 हज़ार लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें 80 प्रतिशत मुसलमान थे. बहरहाल, देश की न्यायपालिका बधाई की पात्र है, जिसके कारण जेलों में अल्पसंख्यकों की संख्या घट रही है. यह स्थिति न्यायपालिका में उनके विश्वास को बढ़ाने वाली है. ■

feedback@chauthiduniya.com

राज्यसभा चुनाव

सस्ती नौटंकी, सड़क छाप ड्रामा

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश का राज्यसभा चुनाव विवाद, अंतर्द्वंद्व एवं अमर्यादित राजनीति का उत्पाद साबित हुआ. सबसे अधिक सीटें जीतने में सक्षम समाजवादी पार्टी में पीठ में छुरा भोंक कर पद पाने की मंशा का वर्चस्व रहा, तो महज दो सीटें जीतने की हैसियत रखने वाली बहुजन समाज पार्टी में एक–दूसरे पर कीचड़ फेंकने का ऐसा उपक्रम चला, जिसे चलताऊ बोलचाल की भाषा में थुक्कम–फजीहत कहते हैं. एक सीट जीतने वाली भाजपा चुप्पी साधे किनारे पड़ी रही, यहां तक कि आख़िर तक वह अपना प्रत्याशी भी तय नहीं कर पा रही थी. कांग्रेस तो माशा अल्लाह! राहुल गांधी की जी–हुजूरी और सपा की चापलूसी का समानांतर कार्यक्रम चलाते रहने वाले, लोकसभा चुनाव हारने वाले पीएल पुनिया राज्यसभा पहुंच गए, बाकी नेता मुंह ताकते रह गए.

समाजवादी पार्टी ने अपने प्रतिबद्ध नेताओं से ही बेजा राजनीति की. तुष्टिकरण और चाटुकारिता की राजनीति को अहमियत दी गई. ग़ौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में लखनऊ का प्रत्याशी घोषित होने के बाद पुरजोर प्रचार अभियान चलाने वाले साफ़ छवि के नेता डॉ. अशोक वाजपेयी को अचानक आख़िरी दौर में ड्रॉप कर दिया गया और उनकी जगह अभिषेक मिश्रा को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा गया था. भेद खुला कि राजनाथ सिंह का रास्ता साफ़ करने के लिए सपा ने ताकतवर प्रत्याशी डॉ. वाजपेयी को मैदान से हटाया था. डॉ. वाजपेयी जैसे प्रतिबद्ध नेता को राज्यसभा के लिए मौक़ा न दिया जाना खुद सपाइयों की समझ में नहीं आ रहा है. एक सपा नेता ने कहा कि कुछ नेताओं ने पूरी पार्टी अपनी जेब में रख ली है. लोकसभा चुनाव हारने वाले कुंअर रेवती रमण सिंह को राज्यसभा में मौक़ा न दिया जाना सपा नेतृत्व का आश्चर्यजनक और आत्मघाती फ़ैसला है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रेवती रमण के पुत्र उज्ज्वल रमण सिंह से मंत्री पद छीनकर पहले ही भूमिहार समुदाय को झटका दे चुके थे. रेवती रमण को राज्यसभा का टिकट न देने को भूमिहार समुदाय अपमानजनक कार्रवाई मान रहा है.

आजम–तुष्टिकरण में आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा को राज्यसभा का टिकट दिया जाना पार्टी के जेबी संस्था होने का संदेश देने वाला साबित हुआ. मुस्लिम समुदाय के लोग ही कहते हैं कि पार्टी के आजम की चाटुकारिता में लगे रहने से हमारा कोई भला नहीं हो रहा.

सपा कुछ खास कारणों से एक खास परिवार को फ़ायदा पहुंचा रही है. आजम ना–ना करते रहे और सपा के शीर्ष नेता उनकी पत्नी को राज्यसभा पहुंचाने के लिए आजम की मक्खनबाजी करते रहे. सपा की यह विचित्र राजनीति किसी को समझ में नहीं आई कि आख़िर आजम की इतनी खुशामद क्यों? तंजीम फातिमा को टिकट दिए जाने के बाद आजम ने उनसे बाकायदा पत्र लिखाकर मीडिया में जारी कराया कि वह राज्यसभा का टिकट वापस लौटा रही हैं, लेकिन आजम ने फिर पलटी मारी और जब पर्चा दाखिल करने का समय आया, तो तंजीम भी पर्चा भरने पहुंच गईं. पर्चा दाखिल करते समय आजम उनके साथ मौजूद नहीं थे. आजम खां के इस रवैये की कई नेता और राज्य सरकार के मंत्री चर्चा करते नज़र आए कि आजम का ड्रामा भी बहुत सुनियोजित होता है. पहले टिकट लौटाने का ड्रामा किया, अब नामांकन के समय मौजूद न रहकर भी ड्रामा कर रहे हैं.

दरअसल, आजम ने सारी नौटंकी अमर सिंह की सपा में वापसी रोकने के लिए की. इसमें प्रो. राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव ने उनका साथ दिया और पुरस्कार में वह अपनी पत्नी के लिए राज्यसभा का टिकट पा गए. इसके बावजूद यह कोशिश हुई कि सपा के अतिरिक्त वोटों के समर्थन से अमर सिंह को राज्यसभा में जगह मिल जाए, लेकिन इस पर भी पानी फेरते हुए कांग्रेस प्रत्याशी पीएल पुनिया को समर्थन दे दिया गया. राज्यसभा को लेकर राहुल गांधी का पुनिया–प्रयोग कांग्रेस में भीषण विरोध और अंतर्कलह का कारण बन गया है. पार्टी के कई विधायक एवं नेता राहुल गांधी के निर्णय को तुगलकी फरमान बताकर इसे पार्टी को कमज़ोर करने का क़दम बता रहे हैं. पुनिया को पहले भी अनुसूचित जाति–जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया जा चुका है. इसके बावजूद वह अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे. अब उन्हें राज्यसभा की सीट दिए जाने को कतार में खड़े पार्टी के अन्य प्रतिबद्ध नेताओं की स्पष्ट उपेक्षा माना जा रहा है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री के लिए यह झटका देने वाला फ़ैसला साबित हुआ. कांग्रेस सरकार में इस्पात मंत्री रहे बेनी प्रसाद वर्मा भी इस फ़ैसले से नाखुश हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव हारने के बाद वह भी राज्यसभा की आस लगाए बैठे थे.

दूसरी तरफ़ बहुजन समाज पार्टी भी राज्यसभा के टिकट बंटवारे को लेकर नुक्कड़ छाप साबित हुई. अपने मुख्यमंत्रित्व काल में भ्रष्टाचार और आतंक का साम्राज्य स्थापित करने वाली मायावती के डर से डॉ. अखिलेश दास बसपा में शामिल हो गए थे. डॉ. दास को उत्तर प्रदेश में फैला अपना व्यापार–साम्राज्य बचाने की चिंता थी. लिहाजा वह कांग्रेस में अपना प्रभावशाली स्थान छोड़कर बसपा में शामिल हुए और तब मायावती ने उनका खूब फ़ायदा उठाया. वही मायावती खुद को दूध की धुली दिखाने की कोशिश करते हुए डॉ. अखिलेश दास द्वारा राज्यसभा टिकट के लिए सौ करोड़ रुपये का ऑफर दिए जाने को ठुकराने की बात करने लगीं. जबकि डॉ. दास पार्टी के पद और सदस्यता से इस्तीफ़ा देकर चुप बैठ गए थे. लेकिन, मायावती को इस्तीफ़ा पसंद नहीं, उन्हें केवल निष्कासन पसंद है. लिहाजा अगले ही दिन वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गईं और डॉ. अखिलेश दास के ख़िलाफ़ मर्यादा के बाहर जाकर बयान देने लगीं. इसके बाद ही डॉ. दास ने टिकट के एवज में मायावती द्वारा रिश्वत लेने की बात कही. उन्होंने कहा कि बसपा प्रमुख बिना पैसा लिए किसी को टिकट नहीं देती हैं. वह विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के एवज में एक करोड़ रुपये लेती हैं. डॉ. दास ने कहा कि डेढ़ महीने पहले मायावती ने बसपा के सभी सांसदों एवं विधायकों से दस–दस लाख रुपये लिए थे. मायावती को नमस्ते करने से लेकर उनसे टिकट पाने तक पैसे लगते हैं. बहरहाल, डॉ. अखिलेश दास और ब्रजेश पाठक को राज्यसभा का टिकट न दिया जाना बसपा के लिए नुक़सानदेह साबित होने वाला है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मायावती और दास पर एफआईआर की मांग

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती और राज्यसभा सदस्य डॉ. अखिलेश दास द्वारा लगाए गए आरोप-प्रत्यारोप की शिकायत अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है. सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को इस संबंध में ईमेल द्वारा शिकायत भेजकर इन आरोपों की जांच और तदनुसार कठोर विधिक कार्रवाई करने का निवेदन किया है. नूतन ठाकुर ने कहा कि आईएनसी बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल वेलफेयर सहित तमाम निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आयोग को किसी राजनीतिक दल द्वारा देश के स्थापित क़ानून को तोड़ने की दशा में उसे अपंजीकृत करने का अधिकार और दायित्व है, जैसा कि ताजा मामले में बसपा पर डॉ. दास ने आरोपित किया है. यह आरोप-प्रत्यारोप आईपीसी की धारा 171-ई (रिश्वत-एक साल की सजा) और 17-एफ (निर्वाचन में असम्यक असर डालना-एक साल की सजा) के तहत अपराध है. लिहाजा, नूतन ठाकुर ने इस मामले में मायावती एवं डॉ. दास से पूछताछ करके बसपा और उक्त दोनों नेताओं को दोषी पाए जाने की स्थिति तक उनके ख़िलाफ़ आपराधिक तथा निर्वाचन विधि के तहत कार्रवाई की मांग की है. ■

सीपी सिंह को रांची विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है. भाजपा ने पांच महिलाओं और ईसाई समुदाय के दो उम्मीदवारों को भी चुनाव मैदान में उतारा है. 18 सीटों पर अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है. गठबंधन होने की स्थिति में आजसू को इनमें से सीटें दी जा सकती हैं.

जम्मू–कश्मीर

अब्दुल्लाह परिवार का पतन शुरू हो गया है !

मोहम्मद हारून रेशी

क्या जम्मू–कश्मीर की जनता के दिलों पर लगभग छह दशकों तक राज करने वाले अब्दुल्लाह परिवार का पतन शुरू हो गया है? यह सवाल इन दिनों यहां के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उमर अब्दुल्लाह ने गांदरबल क्षेत्र से स्वयं चुनाव न लड़ने का निर्णय करके इन संभावनाओं को बल प्रदान किया है कि पार्टी तेज़ी के साथ कश्मीर में अपनी साख खोती जा रही है.

शेख़ मोहम्मद अब्दुल्लाह यानि उमर अब्दुल्लाह के दादा जम्मू कश्मीर के इतिहास के संभवत: सबसे प्रभावशाली नेता थे. वह 1930 के दशक में महाराजा हरि सिंह के ख़िलाफ़ विद्रोह करने के कारण वह एक लोकप्रिय नायक बन गये थे. उन्हें 'शेर–ए–कश्मीर' के नाम से पुकारा जाने लगा और 1947 में भारत के साथ जम्मू–कश्मीर के विलय के बाद शेख़ मोहम्मद अब्दुल्लाह जम्मू–कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गये, लेकिन कुछ वर्षों बाद ही उन्हें केन्द्र सरकार के निर्देशों पर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया. कुल मिलाकर 22 वर्षीय कारावास और संघर्ष के बाद जब 1975 में शेख़ अब्दुल्लाह ने फिर मुख्यधारा की राजनीति में आने का निर्णय किया तो इस 'शेर–ए–कश्मीर' ने गांदरबल चुनाव क्षेत्र को अपनी 'मांद' बना लिया. गांदरबल सीट अब्दुल्लाह परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती थी और इसी सीट पर शेख़ मोहम्मद अब्दुल्लाह ने भी चुनाव लड़े थे और उनके बाद उनके बेटे फ़ारूख़ अब्दुल्लाह ने भी और फिर फारूख़ के बेटे उमर अब्दुल्लाह ने भी इसे अपना चुनावी क्षेत्र बना लिया था. इस सीट के दम पर राज्य की सत्ता दशकों तक अब्दुल्लाह परिवार के हाथों में रही.

शेख़ मोहम्मद अब्दुल्लाह 1982 में अपनी मौत तक गांदरबल चुनाव क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व करते रहे थे. उनके बाद जब नेशनल कांफ्रेस का नेतृत्व फारूख़ अब्दुल्लाह के हाथों में आ गया तो उन्होंने भी 1983, 1987 और 1996 में इसी सीट से चुनाव लड़ा और जीते, यहां तक कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह पिछले विधानसभा चुनावों यानि 2008 के चुनाव में इसी सीट से जीतकर आये, लेकिन अब उमर अब्दुल्लाह के इस निर्णय से सभी लोग हैरान रह गये हैं, बल्कि नेशनल कांफ्रेंस के कई वरिष्ठ नेता उमर के इस निर्णय पर नाराज़ भी हो गये हैं. उमर अब्दुल्लाह की ओर से गांदरबल सीट छोड़ने की घोषणा के एक दिन बाद गांदरबल से संबंध रखने वाले नेशनल कांफ्रेंस के एक वरिष्ठ नेता और एमएलसी शेख़ गुलाम रसूल पार्टी से इस्तीफ़ा देकर मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गये. शेख़ गुलाम रसूल ने त्यागपत्र में यह बात स्पष्ट की कि गांदरबल में लोग नेशनल कांफ्रेंस से नाराज़ हैं और यहां पार्टी की साख पर प्रभाव पड़ेगा.

आम राय यह है कि चूंकि गांदरबल में अब्दुल्लाह परिवार और उनकी नेशनल कांफ्रेंस की साख ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए उमर अब्दुल्लाह ने इस बार गांदरबल को छोड़कर एक साथ सोनाबार और बेरूह की दो सीटों से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है. एक साथ दो चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का निर्णय भी सियासी पंडितों की नज़र में उमर अब्दुल्लाह का अपनी

जनवरी 2009 में जब उमर अब्दुल्लाह ने मुख्यमंत्री की हैसियत से राज्य की बागडोर संभाली तो सबको विश्वास था कि वह एक बेहतर शासक साबित होंगे. वह उम्र के लिहाज़ से उस समय तक भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे. वह उच्च शिक्षा प्राप्त भी थे. उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा था. वह अपने साधारण स्वभाव के लिए मशहूर थे

जीत पर विश्वास न होने की ओर इशारा करता है.

गांदरबल में नेशनल कांफ्रेंस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने चौथी दुनिया को बताया कि उमर अब्दुल्लाह ने अच्छा ही किया कि गांदरबल सीट छोड़ दी, क्योंकि उन्हें इस बार यहां हार का सामना करना पड़ता. लोगों में उनके प्रति सख़्त आक्रोश है. जनता के गुस्से का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में चुनाव जीतने के बाद उमर अब्दुल्लाह मुश्किल से ही तीन–चार बार यहां आये. लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें थीं लेकिन वह इन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, इसलिए इस बार यहां उनकी कामयाबी की कोई संभावना नहीं थी.

गांदरबल के एक पत्रकार साबिर अयूब ने बताया कि नेशनल कांफ्रेंस ने अश्फ़ाक़ जब्बार को यह सीट देकर एक सही निर्णय किया है, क्योंकि अश्फ़ाक़ जब्बार का इस क्षेत्र में ख़ासा प्रभाव है और यहां उमर अब्दुल्लाह के मुक़ाबले में अश्फाक़ के जीतने की अधिक संभावनाएं हैं. दरअसल अश्फ़ाक जब्बार, शेख़ अब्दुल्लाह जब्बार के बेटे हैं, जो महाराजा के ख़िलाफ़ जद्दोजहद और उसके बाद स्वर्गीय शेख़ मोहम्मद अब्दुल्लाह का दाहिना हाथ रहे थे. शेख़ अब्दुल जब्बार को 1990 में उग्रवादियों ने गोली मारकर क़त्ल कर दिया था.

नेशनल कांफ्रेंस के प्रवक्ता जुनैद मत्तु ने चौथी दुनिया को बताया कि उमर अब्दुल्लाह ने दरअसल पिछले साल अश्फ़ाक़ जब्बार के साथ वादा किया था कि अगर वह कांग्रेस पार्टी छोड़कर नेशनल कांफ्रेंस में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें गांदरबल चुनाव क्षेत्र से मेंडेट दिया जायेगा. उमर अब्दुल्लाह ने अपना वही वादा निभाया है. हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ इस तर्क को मानने से इंकार कर रहे हैं. उनका कहना है कि दरअसल जम्मू में भाजपा और घाटी में पीडीपी की लहर ने नेशनल कांफ्रेंस को हताश कर दिया है और नेशनल कांफ्रेंस पर चुनाव से पहले ही हार का डर हावी हो गया है.

राजनीतिक विश्लेषक मक़बूल साहिल का मानना है कि तीन पुश्तों तक कश्मीर पर शासन करने के बाद अब अब्दुल्लाह परिवार का पतन शुरू हो रहा है. उन्होंने ने बताया कि अब्दुल्लाह परिवार और उनकी नेशनल कांफ्रेंस की साख ख़त्म हो गई है. गांदरबल सीट उमर अब्दुल्लाह ने छोड़ दी, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां उन्हें हार का मुंह देखना पड़ सकता है. अब उमर अब्दुल्लाह का एक साथ दो सीटों से चुनाव लड़ना भी यह साबित करता है कि उन्हें जीत की कोई उम्मीद नहीं है. इसके अलावा गत संसदीय चुनावों में फ़ारूक़ अब्दुल्लाह की शर्मनाक हार ने भी अब्दुल्लाह परिवार और नेशनल कांफ्रेंस को हिलाकर रख दिया है. उत्थान के बाद पतन निश्चित होता है. दुनिया के हर कोने में परिवारों की सत्ता अंतत: समाप्त हुई ही है. ऐसा ही कुछ अब्दुल्लाह परिवार के साथ हो रहा है.

कहते हैं कि मुसीबत भी अकेले नहीं आती. अब्दुल्लाह परिवार के लिए एक और परशानी फ़ारूक़ अब्दुल्लाह और उनके चाचा व पार्टी के महासचिव शेख़ नज़ीर की स्वास्थ्य समस्या भी है. फ़ारूक़ अब्दुल्लाह इन दिनों लंदन में उपचार करा रहे हैं, जहां आने वाले चंद दिनों में उनके गुर्दे को बदला जाना है. शेख़ नज़ीर भी इस हद तक बीमार हैं कि उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियां रद्द कर दी हैं. ऐसी स्थिति में नेशनल कांफ्रेंस को चुनाव में विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. वैसे भी पिछले 6 वर्षों की नेशनल कांफ्रेंस सरकार में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनका ख़ामियाज़ा नेशनल कांफ्रेंस को निश्चित तौर पर उठाना पड़ेगा.

जनवरी 2009 में जब उमर अब्दुल्लाह ने मुख्यमंत्री की हैसियत से राज्य की बागडोर संभाली तो सबको विश्वास था कि वह एक बेहतर शासक साबित होंगे. वह उम्र के लिहाज़ से उस समय तक भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे. वह उच्च शिक्षा प्राप्त भी थे. उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा था. वह अपने साधारण स्वभाव के लिए मशहूर थे. इन सारी बातों के कारण उमर अब्दुल्लाह से लोगों की बहुत सी उम्मीदें जुड़ गईं लेकिन उनके सत्ता संभालने के कुछ महीने बाद ही दक्षिण कश्मीर के शोपियान में कथित रूप से दो महिलाओं की बलात्कार के बाद हत्या की घटना हुई. कश्मीर में एक आम राय है कि उमर अब्दुल्लाह सरकार ने इस मामले को दबाने और दोषियों को सज़ा से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इसके बाद साल 2010 में कश्मीर में क़त्ले–आम का बाज़ार गर्म कर दिया गया. पुलिस के द्वारा कथित रूप से 100 से अधिक लोग, जिनमें अधिकतर बच्चे शामिल थे, मार दिये गये. पिछले 6 वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के विभिन्न गंभीर मामले सामने आये लेकिन सरकार ने किसी भी मामले में दोषियों को पकड़ने का प्रयास नहीं किया. इस प्रकार की कई ऐसी घटनाएं हुई, जिस कारण उमर अब्दुल्लाह सरकार की छवि बुरी तरह प्रभावित हुई. फिलहाल स्थिति ऐसी है कि उमर अब्दुल्लाह को गांदरबल जैसी अपनी पारंपरिक सीट से भी जीत की उम्मीद नहीं रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड

बढ़ गई कांग्रेस–झामुमो की बेचैनी

मंगलानंद

पहले पूरा देश, फिर एक–एक प्रदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह चुनावी नारा अब झारखंड में भी दृष्टिगोचर होने लगा है. झारखंड के एक–दो दलों को छोड़कर सभी दलों के नेता भाजपा को घेरने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन भाजपा दोगुनी शक्ति के साथ मजबूत होती जा रही है. राज्य में कांग्रेस–झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन टूट जाने के बाद बन रही स्थितियों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने के कयास अभी से लगने शुरू हो गए हैं. हरियाणा एवं महाराष्ट्र में भाजपा ने अकेले दम पर सरकार बनाकर साबित कर दिया कि एकला चलो की नीति ही सबसे अच्छी है. अब वही नीति भाजपा झारखंड में अपना रही है.

81 सदस्यीय राज्य विधानसभा में भाजपा कहीं अकेले दम पर बहुमत हासिल न कर ले, यही सोचकर कांग्रेस,

आजसू के दावे वाली अन्य सीटों पर अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है. टिकट बंटवारे में पार्टी ने किसी भी दागी को उम्मीदवार बनाने से परहेज किया है. कृषि घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता, जांच के दायरे में आए अरुण मंडल, रामचंद्र बैठा एवं बैजनाथ राम सहित कई लोगों को टिकट से वंचित रखा गया है.

झामुमो एवं राजद के नेताओं की नींद हराम हो चुकी है. येन–केन प्रकारेण उक्त सारे दल एक बार फिर झारखंड में जोड़–तोड़ की सरकार बनाने की जुगत कर रहे हैं, लेकिन अब सबका खेल बिगड़ चुका है. 25 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशी नामांकन करा चुके हैं. भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक अनंत प्रताप देव भाजपा में शामिल हो गए हैं. कांग्रेस ने उन्हें पार्टी प्रत्याशी घोषित किया था. यह घोषणा हुए 24 घंटे भी नहीं बीते कि अनंत प्रताप ने पलटी मार दी और भाजपा में शामिल हो गए. चुनाव के ठीक पहले नेताओं द्वारा दल बदल का यह सिलसिला नया नहीं है. पहले भी यहां ऐसा होता रहा है. ऐसे अनेक उदाहरण हैं. कभी इंदर सिंह नामधारी भाजपा में थे, फिर अपना दल बनाया, राजद एवं जदयू में भी गए और बाद में निर्दलीय सांसद बने.

राधाकृष्ण किशोर कांग्रेस में थे, जदयू में गए, कांग्रेस में वापस आए और अब भाजपा में हैं. माधव लाल सिंह पहले वामदल में थे, फिर निर्दलीय रहे, बाद में कांग्रेसी हो गए और अब भाजपा में हैं. निएल तिर्की झामुमो से कांग्रेस में गए, फिर आजसू में गए और अब पुन: झामुमो में हैं. विजय हांसदा कांग्रेस में थे, फिर झामुमो में आए और सांसद बने. भाजपा ने अर्जुन मुंडा को खरसावां और सीपी सिंह को रांची विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है. भाजपा ने पांच महिलाओं और ईसाई समुदाय के दो उम्मीदवारों को भी चुनाव मैदान में उतारा है. 18 सीटों पर अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है. गठबंधन होने की स्थिति में आजसू को इनमें से सीटें दी जा सकती हैं. उधर रांची के सांसद राम टहल चौधरी द्वारा आजसू के साथ गठबंधन के प्रयास का विरोध किए जाने के बाद भाजपा ने हटिया सीट से सीमा शर्मा के नाम की घोषणा कर दी है. इस सीट पर अभी आजसू के नवीन जायसवाल विधायक हैं. आजसू ने यह सीट छोड़ने के लिए भाजपा पर दबाव बनाया था.

हालांकि, आजसू के दावे वाली अन्य सीटों पर अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है. टिकट बंटवारे में पार्टी ने किसी भी दागी को उम्मीदवार बनाने से परहेज किया है. कृषि घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता, जांच के दायरे में आए अरुण मंडल, रामचंद्र बैठा एवं बैजनाथ राम सहित कई लोगों को टिकट से वंचित रखा गया है. भाजपा ने राज्य की जिन 18 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, वे हैं शिकारीपाड़ा, बड़कागांव, रामगढ़, मांडू, हजारीबाग, धनवार, बगोदर, गोमिया, चंदनक्यारी, निरसा, टुंडी, घाटशिला, जुगसलाई, ईचागढ़, तमाड़, सिल्ली, कोलेबिरा एवं लोहरदगा. भाजपा के कई दिग्गजों को इस बार टिकट न मिलना तय है. वहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ चौधरी, लक्ष्मण सिंह एवं शीतल उरांव को भी पार्टी ने टिकट देने से परहेज किया है. फिलहाल झारखंड में भाजपा एकला चलो रे वाली नीति पर काम कर रही है. अगर यह नीति कामयाब हुई, तो इस बार झारखंड में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ आएगी. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

> लॉरेटो कॉन्वेंट रोड से कैंट जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे आवास विकास परिषद के बगल में विशाल जगह पर कब्जा करके वहां बसपा का ऐसा दफ्तर बनने लगा, जैसे लाल किला बन रहा हो. उसके ठीक पीछे मायावती का घर दुर्ग की तरह बन रहा था. उसके बगल में कब्जाई गई बेशक़ीमती जगह पर प्रेरणा-स्थल बनाया जाने लगा था और उसके पीछे मायावती के खासमखास सतीश चंद्र मिश्र की कोठी का शानदारीकरण किया जा रहा था. उक्त सारे काम क़रीब-क़रीब एक साथ हो रहे थे और एक साथ ही पूरे शहर का जीवन दूभर कर दिया गया था.

बिहार

पर्दे के पीछे से तीरों की बौछार

सरोज सिंह

राजद, जदयू और कांग्रेस के बीच बने महा-गठबंधन में इन दिनों पर्दे के पीछे से नेताओं ने एक-दूसरे पर दबाव बनाने वाले बयानों के तीरों की बौछार कर रखी है. इन तीरों का एकमात्र मकसद बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने दल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करना है. लेकिन दुर्भाग्य है कि इन तीरों की चपेट में कभी-कभी सूबे के मुखिया जीतन राम मांझी भी आ जाते हैं. ग़ौरतलब है कि नरेंद्र मोदी का राज्यों का विजय अभियान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उससे विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है. इसलिए न चाहते हुए भी गठबंधन बनाए रखना नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की मजबूरी हो गई है. दोनों ही नेता यह महसूस कर चुके हैं कि अगर अलग होकर नरेंद्र मोदी के सामने गए, तो परेशानी होनी तय है. दोनों नेता यह भी समझ रहे हैं कि महा-गठबंधन बनाए रखना बहुत ही दुष्कर कार्य है, क्योंकि सीटों के बंटवारे में बहुत सारे पेंच ऐसे हैं, जिन्हें सुलझा पाना बहुत मुश्किल है.

ग़ौरतलब है कि राज्य विधानसभा की 243 सीटों में 70 सीटें ऐसी हैं, जिन पर जदयू ने राजद प्रत्याशी को सीधे मुकाबले में हराया है. इन सीटों का बंटवारा कैसे और किस अनुपात में होगा, यह गणित दोनों दलों के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है. उधर रघुवंश बाबू ने यह कहकर महा-गठबंधन का पेंच और उलझा दिया कि सीटों के बंटवारे का आधार लोकसभा चुनाव में मिले वोटों को बनाया जाएगा. मतलब यह कि जिन सीटों पर राजद ने ज़्यादा वोट पाए हैं, उन पर वह अपना दावा पेश करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि अब पहले वाली बात नहीं है और सूबे के राजनीतिक हालात काफी बदल गए हैं, इसलिए राजद ही बड़े भाई की भूमिका में रहेगा. जाहिर है, इन बातों का जदयू में विरोध होना था और हुआ भी. प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया में कहा कि अभी इन बातों का समय नहीं आया है, इसलिए यह प्रसंग ही बेमानी है.

जानकार बताते हैं कि जदयू ने लालू प्रसाद से ऐसी बातें तत्काल रोकने के लिए कहा. उन्हें बताया गया कि इस तरह की बेमौसम बयानबाजी महा-गठबंधन की सेहत के लिए अच्छी नहीं है. मंत्री वृशिण पटेल कहते हैं कि गठबंधन तो शीशे का महल होता है. अगर एक भी पत्थर लग गया, तो महल गिर जाएगा. इसलिए बहुत संभल-संभल कर चलने और बोलने की ज़रूरत है. जदयू की तरफ़ से बनाए गए दबाव का असर भी हुआ और राजद ने अपनी छह नवंबर वाली बैठक को महज औपचारिक और ग़ैर-राजनीतिक बताया. जबकि पहले तय था कि इस बैठक में राजद के दस बड़े नेता लालू प्रसाद के साथ दिल्ली में महा-गठबंधन के भविष्य पर गंभीर चिंतन करेंगे. इसमें झारखंड में महा-गठबंधन जारी रखने पर भी विचार होना था, लेकिन इस बैठक को सिर्फ़ रस्मी बना दिया गया. अगले ही दिन लालू प्रसाद को एक बयान जारी करना पड़ा कि महा-गठबंधन पर बयान देने के लिए सभी नेता अधिकृत नहीं हैं और हर हाल में महा-गठबंधन जारी रखना है. नेता कौन होगा और कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेंगी, ये सब महत्वहीन बातें हैं. सबसे ज़्यादा महत्व इस बात का है कि सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करना है और ग़ैर भाजपाई वोटों का विभाजन नहीं होने देना है.

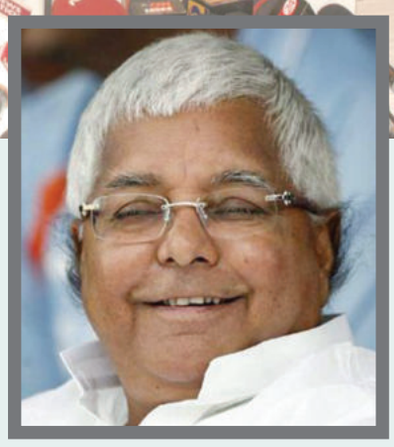

> शरद यादव को भी यह बात समझाने की कोशिश हो रही है कि हालात अगर यही बने रहे, तो फिर पार्टी के लिए मुश्किल होगी. हाल में शरद यादव के पटना दौरे को इसी संदर्भ में देखना उचित होगा. लेकिन, अब सवाल उठता है कि महादलित समाज के मुख्यमंत्री को हटाने का कितना ख़तरा पार्टी उठाने के लिए तैयार है.

लालू प्रसाद के इस बयान के बाद उम्मीद की जा रही है कि फिलहाल कुछ दिनों तक बयानबाजी का दौर बंद रहेगा. लेकिन यह स्थायी तौर पर बंद रहेगा, इसकी गारंटी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है. एक-दूसरे पर दबाव बनाने के लिए फिर बयान दिए जाएंगे और उसके बाद फिर शीर्ष स्तर पर खंडन आ जाएगा. जानकार बताते हैं कि राजद ने मोटे तौर पर तय कर लिया है कि वह 140 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगा. यह ऐसी संख्या है, जो जदयू को मान्य नहीं हो सकती. जदयू की अभी सूबे में सरकार है, इसलिए वह किसी भी क़ीमत पर अपनी छोटी भूमिका स्वीकार करने की ग़लती नहीं कर सकता. ऐसे में महा-गठबंधन बनाए रखने के पक्षधर नेताओं की राय है कि जदयू और राजद के बीच बराबर-बराबर सीटों का बंटवारा हो और शेष सीटें कांग्रेस को दे दी जाएं. एक फॉर्मूला यह बनाया जा रहा है कि 110-110 सीटों पर राजद और जदयू के प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में उतरें और बाकी 23 सीटें कांग्रेस को दे दी जाएं. लेकिन, राजद और कांग्रेस खेमे में इस फॉर्मूले को लेकर कोई उत्साह नहीं है. दोनों ही दल इसे अव्यवहारिक बता रहे हैं.

कांग्रेस इस चुनाव में अपनी ठीकठाक भूमिका चाहती है. उसे 50 से कम सीटें देने पर बात बनने वाली नहीं है. राजद 140 से नीचे आने के लिए तैयार नहीं है. ऐसे में महा-गठबंधन बनाए रखने में सबसे सहायक नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, जिनका डर दिखाकर यह महा-गठबंधन ज़िंदा रखा जा सकता है. उधर जीतन राम मांझी को लेकर भी जदयू के भीतर खींचतान जारी है. नीतीश और जीतन राम के बीच सही तालमेल नहीं है, यह चर्चा अब आम है, लेकिन इसमें एक नई बात यह हुई कि नीतीश कुमार के भरोसे के कई नेता अब पर्दे के पीछे से जीतन राम को हटाने और नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के अभियान में लग गए हैं. जीतन राम के कार्यकलाप पर नीतीश कुमार और उनके साथी अब चर्चा करना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं. नीतीश के रणनीतिकारों का मानना है कि जीतन राम के बयानों और कार्यशैली से सरकार की छवि प्रभावित हुई है. उस प्रभावित छवि के साथ जनता के बीच चुनाव में जाने से जदयू को भारी नुक़सान हो सकता है.

शरद यादव को भी यह बात समझाने की कोशिश हो रही है कि हालात अगर यही बने रहे, तो फिर पार्टी के लिए मुश्किल होगी. हाल में शरद यादव के पटना दौरे को इसी संदर्भ में देखना उचित होगा. लेकिन, अब सवाल उठता है कि महादलित समाज के मुख्यमंत्री को हटाने का कितना ख़तरा पार्टी उठाने के लिए तैयार है. जीतन राम भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं. वह अपने हिसाब से शासन चला रहे हैं. महादलितों को एकजुट करने का अभियान जारी है. वह बार-बार जोर दे रहे हैं कि अगर महादलित एकजुट हो जाएं, तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री फिर इसी समाज से हो सकता है. जीतन राम की इन बातों से जदयू खेमे में बेचैनी है. नीतीश समर्थकों को न निगलते बन रहा है और न उगलते. जीतन राम मस्त हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है. जो भी ख़तरा उठाना है, वह नीतीश कुमार और उनके खेमे को उठाना है. देखना दिलचस्प होगा कि आख़िर नीतीश कुमार इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तर प्रदेश

विकास के साथ राजनीति का जरिया बना फ्लाईओवर

दीनबंधु कबीर

विकास का पुल राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी का कद छोटा कर सकता है, उसे ढांप सकता है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को यह बात समझ में आती है, इसीलिए वह तमाम ऐसे विकास के काम जल्द से जल्द पूरे करना चाहते हैं, जिनसे उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी का कद ढंके और उसका फ़ायदा उन्हें अगले चुनाव में मिल सके. लखनऊ के सबसे पॉश इलाके माल एवेन्यू में मायावती ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो तांडव मचाया था, उससे स्थानीय लोग खासे आक्रांत थे. माल एवेन्यू और उससे सटे कैंट क्षेत्र में कोठियों पर कब्जा करने से लेकर अचल संपत्ति का जाल बिछाने की ऐसी दबंग हरकतें हुईं, जिनसे इलाकाई लोगों का जीना मुहाल हो गया था.

लॉरेटो कॉन्वेंट रोड से कैंट जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे आवास विकास परिषद के बगल में विशाल जगह पर कब्जा करके वहां बसपा का ऐसा दफ्तर बनने लगा, जैसे लाल किला बन रहा हो. उसके ठीक पीछे मायावती का घर दुर्ग की तरह बन रहा था. उसके बगल में कब्जाई गई बेशक़ीमती जगह पर प्रेरणा-स्थल बनाया जाने लगा था और उसके पीछे मायावती के खासमखास सतीश चंद्र मिश्र की कोठी का शानदारीकरण किया जा रहा था. उक्त सारे काम क़रीब-क़रीब एक साथ हो रहे थे और एक साथ ही पूरे शहर का जीवन दूभर कर दिया गया था. मुख्य सड़क पर बसपा का विशाल कार्यालय ऐसा बना, जैसे वह किसी राजनीतिक दल का कार्यालय नहीं, बल्कि कोई उच्च सुरक्षा वाली जेल हो. बसपा की छोटी बैठक भी होती, तो सड़क बंद कर दी जाती थी.

बसपा के दफ्तर में झांकने की तो बात ही छोड़ दें, अगर किसी बैठक में मायावती को खुद आना होता था, तो पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए जाते थे. लोगों को परेशानियों से बचाने के लिए माल एवेन्यू-कैंट रोड पर फ्लाई ओवर की योजना बनी. इससे एक तीर से दो-दो सटीक शिकार होने थे. लोगों का आना-जाना निर्बाध हो जाएगा और मायावती को अपने ठिगने होने का हमेशा एहसास भी होता रहेगा. यह एक सार्थक राजनीति थी, लिहाजा इस पर अधिक चिल्लपों भी नहीं मच सकी. फ्लाई ओवर के तेज गति से होने वाले काम ने ऊंचाई और निचाई का फ़र्क़ आम लोगों तक पहुंचाया. पिछले दिनों मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस फ्लाई ओवर का लोकार्पण किया. कार्यक्रम में प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल सिंह यादव, सेना के मध्य कमान के जीओसी-इन-सी लेफ्टिनेंट जनरल राजन बख्शी समेत कई लोग मौजूद थे.

अखिलेश मीडिया से नाराज़

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मीडिया से कुछ अधिक ही नाराज़ हैं. पुलिस सुधार की योजनाएं घोषित करते समय उन्होंने मीडिया को नहीं बख्शा. उन्होंने कहा कि क़ानून व्यवस्था पर मीडिया सदैव उन्हें बेवजह टारगेट करता है और प्रदेश की किसी भी घटना को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है. उसमें मेरी फोटो तक लगा दी जाती है. मीडिया को अच्छे काम नहीं दिखते. पुलिस-प्रशासन को मीडिया मौक़ा ही नहीं देता और उनके अच्छे काम नहीं दिखाता. मीडिया को अन्य राज्यों की क़ानून व्यवस्था अच्छी दिखती है. अखिलेश ने कहा कि 3-पी यानी पॉलिटीशियन, पुलिस और प्रेस चौथे पी यानी पब्लिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. जनता के प्रति इनकी विशेष ज़िम्मेदारी है. ये तीनों मिलकर जनता की बेहतरी के लिए काफी काम कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिज्ञों की ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि जनता उन्हें चुनकर भेजती है. ■

कद छोटा करने की सार्थक राजनीति को रेल फाटक से होने वाले जाम से राहत दिलाने का नाम दिया गया. कहा गया कि लखनऊ-दिलकुशा रेल खंड से गुजरने वाली ट्रेनों की संख्या अधिक है, इससे रेलवे फाटक (संख्या-214-स्पेशल) को बार-बार बंद करना पड़ता है. नतीजतन सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती थी. अब फोर लेन रेल ओवर ब्रिज बन जाने से लोगों को जाम की समस्या से छुटकारा मिल गया है. इस पुल से बसपा का दफ्तर-किला और मायावती का आवासीय-दुर्ग काफी नीचे दिखता है. यह पुल रिकॉर्ड अवधि में बनकर तैयार हो गया. पुल का निर्माण जून 2013 में शुरू हुआ और अक्टूबर 2014 पूरा हो गया. इसी तरह मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का ख्याल रखते हुए प्रदेश सरकार ने कब्रगाह की ज़मीन पर बिना कोई निर्माण किए एक फ्लाई ओवर बनाया. गोमती नगर स्थित उक्त इलाके में सड़क के दाईं ओर दो लेन मार्ग उपलब्ध था, जिसे चौड़ा करने में कब्रिस्तान की ज़मीन बाधक बन रही थी. ऐसे में कब्रिस्तान के ऊपर उसकी पूरी लंबाई में बिना कोई निर्माण किए

> बसपा के दफ्तर में झांकने की तो बात ही छोड़ दें, अगर किसी बैठक में मायावती को खुद आना होता था, तो पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए जाते थे. लोगों को परेशानियों से बचाने के लिए माल एवेन्यू-कैंट रोड पर फ्लाई ओवर की योजना बनी. इससे एक तीर से दो-दो सटीक शिकार होने थे. लोगों का आना-जाना निर्बाध हो जाएगा और मायावती को अपने ठिगने होने का हमेशा एहसास भी होता रहेगा.

एक एलीवेटेड पहुंच मार्ग बनाया गया और उसे रेलवे ओवर ब्रिज से जोड़कर यातायात सुगम किया गया. सितंबर 2013 में यह काम शुरू हुआ और एक वर्ष में पूरा कर लिया गया.

शासन के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि अखिलेश सरकार के कार्यकाल में छोटे-बड़े मिलाकर 262 पुल बने. इसी तरह प्रदेश की प्रमुख नदियों पर बड़े पुलों का निर्माण कराया जा रहा है. अखिलेश सरकार की नज़र अब 2017 के विधानसभा चुनाव पर है. लिहाजा, पुल के साथ-साथ पुलिस पर भी वह ध्यान देने लगी है. चुनाव में पुलिस की क्या-क्या भूमिकाएं हो सकती हैं, इस बारे में अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है. 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा से असंतुष्ट सिपाहियों ने अपना असर दिखाया और अब वही असर वापस लाने की तैयारी है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि आगामी तीन वर्षों में लगभग डेढ़ लाख कांस्टेबिल भर्ती किए जाएंगे. साफ़ है कि चुनाव आते-आते एक ऐसी बड़ी फौज खड़ी हो जाएगी, जो अखिलेश सरकार के प्रति सहानुभूति रखेगी. इसका असर चुनाव पर दिखेगा. पुलिस विभाग के लिए सुधार एवं सुविधाओं के कई कार्यक्रमों की पिछले दिनों घोषणा की गई. ■

feedback@chauthiduniya.com

तीर्थ पुरोहितों की एक बैठक में चिराग कीर्तिपाल, ईशांत वशिष्ठ, शांतनु, गौरव झा, शिवम क्षोत्रिय, श्रीकांत एवं प्रशांत ने उमा के बयान की निंदा की. तीर्थ मर्यादा रक्षा समिति की बैठक में अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने मांग की कि प्रधानमंत्री मोदी उमा को गंगा से जुड़े मंत्रालय से हटाएं. प्रदेश युवा कांग्रेस ने प्रदीप अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया कि उमा के हरिद्वार आगमन पर उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा. जनसंघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन खत्री ने कहा कि उमा संत होते हुए भी गंगा का इतिहास भूल गई हैं.

मध्य प्रदेश : नगर निगम और निकाय चुनाव

क्या व्यापम घोटाला कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगा?

चौथी दुनिया ब्यूरो

मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है. राज्य में नगर निगम और नगरीय निकायों में 28 नवंबर व 02 दिसंबर को चुनाव होंगे. 4 व 6 दिसंबर को परिणाम आ जाएंगे. तब यह सिद्ध हो जाएगा कि 9 साल से मुख्यमंत्री के पद पर काबिज शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है या उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है. पिछले साल दिसंबर में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को जबर्दस्त सफलता मिली थी और शिवराज तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुए थे. 2009 के मुकाबले 2013 में भाजपा को विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें मिली हैं. इसका सीधा सा मतलब है कि शिवराज के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में भाजपा का जनाधार बढ़ा. इसके पांच महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में भी मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा को 27 में से 25 सीटों पर जीत हासिल हुई. कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ ही अपनी सीट बचाने में कामयाब हो सके थे. हाल ही में तीन विधानसभा सीटों के लिए हुए उप-चुनाव में भाजपा को एक सीट पर हार का सामना करना पड़ा.

नगरीय चुनाव के प्रथम चरण में 11 नगर निगम और 280 नगर निकायों के चुनाव होंगे. इंदौर, ग्वालियर, सागर, रीवा, सतना, कटनी, खंडवा, देवास, बुरहानपुर, सिंगरौली और रतलाम में महापौर और पार्षदों के चुनाव होंगे. नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के अंतर्गत दिसंबर में 4 नगर निगम में महापौर और पार्षद चुने जाएंगे. इनमें भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा और मुरैना जिले शामिल हैं. दिसंबर में ही 2 नगर पालिका परिषद विदिशा, मैहर और 1 नगर परिषद बनखेड़ी में मतदान होगा. जबलपुर, छिंदवाड़ा और भोपाल के परिसीमन प्रस्ताव पर यदि राज्यपाल मुहर लगा देते हैं, तो इन जिलों में भी दिसंबर में ही चुनाव संपन्न हो सकेंगे अन्यथा यहां मतदान की तारीखें बदली जा सकती हैं.

व्यापम घोटाला शिवराज सरकार के लिए गले की फांस बना हुआ है, रह-रह कर इसमें नए खुलासे हो रहे हैं. हालांकि हाईकोर्ट की निगरानी में एसआईटी इसकी जांच कर रही है. कांग्रेस लगातार इस घोटाले की जांच सीबीआई से करने की मांग कर रही है. शिवराज सिंह चौहान की जांच एसआईटी से कराने के निर्णय पर अडिग हैं उन्हें विश्वास है कि एसआईटी मामले की तह तक पहुंच कर दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी. मुख्यमंत्री विधानसभा में यह मान चुके हैं कि एक हजार भर्तियां फर्जी हैं. भले ही वे आंकड़ा कम बता रहे हों, लेकिन यह तो मान रहे हैं कि फर्जी भर्तियां हुई हैं. सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए इतना ही काफी है. यह सच है कि व्यवसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) घोटाले और पीएमटी फर्जीवाड़े के कारण शिवराज सरकार की प्रतिष्ठा गिरी है.

व्यापम घोटाले के बाद अब शिवराज सरकार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (पीएससी) में हुई धांधलियों के आरोप में घिरती नजर आई. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुई गड़बड़ियां भी अब उजागर होने लगी हैं. आरटीआई से खुलासा हुआ है कि वर्ष 2006 में लोक सेवा आयोग के तत्कालीन चेयरमैन प्रदीप जोशी की नियुक्ति आरएसएस के प्रचारक विनोद जी के लिखित आदेश पर की गई थी जो कि असंवैधानिक है. गौरतलब है कि इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में साफ-साफ कहा था कि प्रदीप जोशी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी के रिश्तेदार हैं और उनकी नियुक्ति इस पद पर नहीं की जा सकती है. बावजूद इसके उनकी नियुक्ति की गई.

हालांकि स्थानीय निकाय के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं. इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों का ज्यादा असर नहीं पड़ता है. हालांकि देश में अभी भी मोदी लहर बरकरार है यह बात हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी को मिली सफलता से जाहिर हो जाती है. स्थानीय-वार्ड चुनाव में गली, मोहल्ले, बाजारों, शहर से जुड़ी समस्याएं और विकास कार्य ही प्रभावित करते हैं. राज्य में नगरीय निकाय चुनाव हों, उपचुनाव हो या मंडी-पंचायत चुनाव हों सत्तारूढ़ दल को आशाजनक परिणाम नहीं मिलते हैं तो उसके मुख्यमंत्री की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े होंगे और साथ ही उनकी लोकप्रियता पर भी आंच आएगी. इसलिए शिवराज इन चुनावों में जीत हासिल करने के लिए पूरा दम लगाएंगे. कांगेस पार्टी इसे लंबे समय से मुद्दा बनाए हुए है और लगातार शिवराज सिंह से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस इस मुद्दे को भुना नहीं पा रही है. ऐसे भी यह चुनाव शहरों के आधारभूत विकास का है. यहां यह मुद्दा प्रभावी भी नहीं हो सकता. लेकिन कांग्रेस के पास और कुछ ऐसा नहीं है जिसे लेकर वह चुनाव में उतर सके. व्यापम घोटाला भी उनके लिए संजीवनी साबित नहीं होता दिख रहा है. पिछली बार कांग्रेस केवल दो नगर निगमों पर ही महापौर का चुनाव जीत सकी थी. यदि वह अपनी उन्हीं सीटों को बचाने में सफल हो जाती है तो यह उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी.

पिछले बार हुए हुए निकाय चुनावों में भाजपा भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर जैसे मुख्य शहरों में महापौर के पद पर कब्जा किया था. पलड़ा इस बार भी भाजपा का ही भारी दिख रहा है. बड़ी संख्या में दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं. इसका सीधा असर कांग्रेस और दूसरे दलों की के भविष्य पर पड़ेगा. भले ही भाजपा को जीत हासिल हो जाए लेकिन उसे व्यापम और लोक सेवा आयोग में हुई धांधलियों का सच जनता के सामने लाना ही होगा और दोषियों को सजा देनी होगी नहीं तो प्रदेश भाजपा और शिवराज सिंह के लिए अच्छे दिन नहीं रह जाएंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

वर्ष 2009 परिणाम नगर निगम (महापौर)

भाजपा

1 भोपाल- कृष्णा गौर
2 इंदौर- कृष्णमुरारी मोघे
3 ग्वालियर-साधना गुप्ता
4 जबलपुर - प्रभात साहू
5 खंडवा - भावना शाह
6 रीवा - शिवेन्द्र सिंह पटेल
7 बुरहानपुर - माधुरी पटेल

कांग्रेस

8 कटनी - निर्मला पाठक
9 देवास - रेखा वर्मा

बसपा

10 सतना - पुष्कर सिंह तोमर
11 सिंगरौली - रेणु शाह

निर्दलीय

12 सागर- कमला बुआ

उत्तराखंड

उमा के बयान पर उबाल

राजकुमार शर्मा

केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा सफाई मंत्री साध्वी उमा भारती एक बार फिर अपने वक्तव्य को लेकर चर्चा में हैं. उनके इस ताजे बयान को लेकर देवभूमि उत्तराखंड में खासा उबाल देखने को मिल रहा है. गंगा तटों पर अस्थि विसर्जन रोकने संबंधी इस बयान की चारों तरफ़ जोरदार निंदा हो रही है. हरिद्वार एवं ऋषिकेश में विभिन्न संगठनों-संस्थाओं ने बैठक करके चेतावनी दी कि यदि ऐसा हुआ, तो गंगोत्री से गंगा सागर तक आंदोलन किया जाएगा.

हरिद्वार स्थित श्रीजयराम संस्थाएं के पीठाधीश्वर एवं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि इस तरह के बयान से पूरी मोदी सरकार बेपर्दा होती है. सरकार के मंत्री का यह बयान सनातन एवं हिंदू संस्कृति के विपरीत है. गंगा का धरती पर अवतरण लोगों को मोक्ष प्रदान करने के लिए हुआ था. पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनकर काम कर रही उमा भारती ऐसा बयान देकर जनता को असल मुद्दे से भटकाना चाहती हैं. ब्रह्मचारी ने कहा कि साध्वी होने के बावजूद उमा में सनातन एवं लोग संस्कृति की समझ का घोर अभाव है. त्रिवेणी घाट सहित धर्मनगरी में गंगा को गंदा करने वाले नाले कैसे बंद हों, कानपुर एवं वाराणसी में गंगा में औद्योगिक कचरे का गिरना कैसे बंद हो, सरकार को इस दिशा में कोई सार्थक पहल करनी चाहिए. ऐसा न करके मोदी सरकार जनभावना के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो सर्वथा अनुचित है.

नौ दिन चले अढ़ाई कोस वाली कहावत चरितार्थ कर रही केंद्र सरकार ने एक तरफ़ गंगा की सफाई को प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट घोषित कर रखा है, दूसरी तरफ़ मंत्रालय की मुखिया साध्वी उमा भारती केवल जुबानी तीर चलाकर जनता में हलचल पैदा कर रही हैं. शायद इसी वजह से राज्य सरकारें उनके साथ सहयोग नहीं कर पा रही हैं. पिछले दिनों गंगा प्राधिकरण की एक बैठक हुई. इस संबंध में पत्रकारों को भी बुलाया गया, लेकिन उन्हें तब तक इंतज़ार कराया गया, जब तक उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य के प्रतिनिधि वहां से विदा नहीं हो गए. उस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को छोड़कर किसी भी मुख्यमंत्री ने हिस्सा नहीं लिया. रावत को प्रेसवार्ता में शामिल नहीं किया गया. कुल मिलाकर गंगा को लेकर इन दिनों काम कम और राजनीति ज़्यादा हो रही है. हरिद्वार में ऑल इंडिया ब्राह्मण फेडरेशन की बैठक में महिला ब्राह्मण फेडरेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम भक्त ने कहा कि अनर्गल प्रलाप और सनातन संस्कृति विरोधी क़दम के कारण साध्वी उमा भारती का विरोध किया जाएगा. डॉ. राजेंद्र पाराशर ने परंपराएं तोड़ने का आरोप लगाते हुए उमा से त्याग-पत्र देने की मांग की.

तीर्थ पुरोहितों की एक बैठक में चिराग कीर्तिपाल, ईशांत वशिष्ठ, शांतनु, गौरव झा, शिवम क्षोत्रिय, श्रीकांत एवं प्रशांत ने उमा के बयान की निंदा की. तीर्थ मर्यादा रक्षा समिति की बैठक में अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने मांग की कि प्रधानमंत्री मोदी उमा को गंगा से जुड़े मंत्रालय से हटाएं. प्रदेश युवा कांग्रेस ने प्रदीप अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया कि उमा के हरिद्वार आगमन पर उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा. जनसंघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन खत्री ने कहा कि उमा संत होते हुए भी गंगा का इतिहास भूल गई हैं. महानगर व्यापार मंडल के सुनील सेठी ने कहा कि यदि यात्री गंगा तट पर नहीं आएंगे, तो व्यापार ठप हो जाएगा. बड़ा बाज़ार व्यापार मंडल की बैठक में चेतावनी दी गई कि उमा परंपराओं से खेलने का दुस्साहस न करें.

भाजपा गंगा प्रकोष्ठ के सह संयोजक प्रवीण शर्मा ने कहा कि परंपराओं को नहीं बदला जा सकता. उमा भारती चाहती हैं कि अस्थि विसर्जन वहां हो, जहां जल प्रचुर मात्रा में हो. हरिद्वार में भरपूर जल है, अत: यहां अस्थि विसर्जन नहीं रोका जा सकता. राहुल-प्रियंका ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि प्राचीनकाल से गंगा में अस्थि विसर्जन होता आ रहा है और अब प्रदूषण के बहाने उस पर रोक लगाने का फ़ैसला लेकर उमा भारती जनभावना से खेल रही हैं. उमा के बयान से सबसे ज़्यादा हैरान बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के विद्वान हैं. काशी श्मशान एवं मोक्ष के लिए ही जानी जाती है. उमा के बयान की सर्वत्र निंदा हो रही है. लोगों का यह भी कहना है कि सरकार महंगाई और काला धन जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए उमा को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

जनता परिवार प्रभावी विपक्ष और विकल्प बन सकता है

आख़िरकार, इस सरकार को आए छह महीने बीत चुके हैं. भाजपा ने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, जैसे काला धन वापस लाना और रोज़गार देना आदि, सरकार उन्हें पूरा करने के आसपास भी पहुंचती नहीं दिख रही है. अब जाकर पता चल रहा है कि इन बड़े वादों को पूरा करना कितना कठिन है. अख़बारों में छपे आलेखों से पता चलता है कि स्विस बैंक से पैसा निकल कर पहले ही मॉरीशस और सिंगापुर के रास्ते भारत पहुंच चुका है. सत्ता के क़रीब रहने वाले लोगों द्वारा लिखे गए आलेखों का अर्थ है कि सत्ता को यह एहसास हो गया है कि इन वादों को पूरा नहीं किया जा सकता.

प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के सख्त ख़िलाफ़ हैं, प्रशासन में एक नई संस्कृति कायम करने के इच्छुक हैं, लेकिन उन्हें मंत्रियों द्वारा घोषित संपत्ति के ब्यौरे पर भी एक नज़र डालनी चाहिए. अख़बारों में ख़बर आई है कि मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है. कांग्रेस का यह तरीका था कि किसी मामले की नोटिस उस वक्त तक न लो, जब तक कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोई केस दर्ज नहीं होता या आयकर विभाग की नींद नहीं खुल जाती. हालांकि, प्रधानमंत्री खुद इन जानकारियों की जांच करेंगे. आख़िरकार, अचानक कैसे कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है? यदि कोई आदमी अचानक बहुत अधिक पैसा कमा लेता है, तो प्रधानमंत्री को स्वयं इस मामले को देखना चाहिए कि क्या यह पैसा सही तरीके से कमाया गया है. अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर भूल जाइए कि ऐसे आदमी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा, उसे दंड दिया जाएगा या कोई कार्रवाई की जाएगी. ऐसे आदमी को कम से कम मंत्रिमंडल से तो ज़रूर बाहर कर देना चाहिए. एक मंत्री की छवि स्वच्छ होनी चाहिए.

यदि प्रधानमंत्री की छवि स्वच्छ है, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सहकर्मियों की छवि भी साफ़-सुथरी हो. अगर किसी की छवि के बारे में संदेह भी हो, तो उसे तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए. सिर्फ़ यही एक रास्ता है, न कि पहले की तरह आप क़ानून द्वारा कार्रवाई शुरू किए जाने का इंतजार करते रहें और इस सबमें सालों साल लग जाएं. दरअसल, इस मामले में देश को क़ानूनी कार्रवाई और सजा मिलने का इंतजार करने की सालों पुरानी आदत एवं संस्कृति से बाहर निकलना होगा. क्रिकेट के बारे में भी मैंने कुछ ऐसा ही कहा था कि जब किसी खिलाड़ी पर मैच फिक्सिंग या बेटिंग का जरा भी शक हो, तो उसे फौरन टीम से निकाल दिया जाना चाहिए. एक खिलाड़ी के लिए टीम से निकाले जाने से बड़ी कोई सजा हो ही नहीं सकती.

लोग हमेशा सीबीआई और सजा की बात करते रहते हैं. इसका कोई मतलब नहीं है. सबसे अच्छी सजा है, क्रिकेटर को टीम से निकालना या मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाना. आख़िरकार, केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर का पद बहुत ही शक्तिशाली पद होता है और जैसे ही आप इस पद से बाहर किए जाते हैं, आप सचमुच बहुत कुछ खो देते हैं. प्रधानमंत्री को चाहिए कि वह या तो किसी आईबी ऑफिसर या फिर पीएमओ के किसी वरिष्ठ सहयोगी को इनके रिकॉर्ड्स की जांच करने के लिए कहें और खुद भी इन मंत्रियों से पूछें कि दस सालों में उनके पास इतना अधिक पैसा यानी 70 करोड़ या 100 करोड़ कहां से आया? वह भी तब, जब न आपके पास पूंजी है, न प्रतिभा है, न कोई उद्योग है. आख़िर किस चीज से उन्होंने इतना पैसा कमाया?

अरुण जेटली के मामले में यह समझा जा सकता है कि वे एक कॉरपोरेट वकील रह चुके हैं, रोजाना की उनकी फीस ही लाखों रुपये की है. अगर उन्होंने यह पैसा कमाया है, तो टैक्स दिया है. एक बड़ी चल और अचल संपत्ति बनाई है. यह सब तर्कसंगत है, समझ में आता है. लेकिन ऐसे भी मंत्री हैं, जिनके पास न कोई ऐसी योग्यता है, न पूंजी है, तो फिर उनके पास इतना पैसा कहां से आया? अगर प्रधानमंत्री ऐसे मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से बाहर नहीं करते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि क्लीन गवर्नमेंट की बात सिर्फ़ बात भर ही है.

अरुण जेटली के मामले में यह समझा जा सकता है कि वे एक कॉरपोरेट वकील रह चुके हैं, रोजाना की उनकी फीस ही लाखों रुपये की है. अगर उन्होंने यह पैसा कमाया है, तो टैक्स दिया है. एक बड़ी चल और अचल संपत्ति बनाई है. यह सब तर्कसंगत है, समझ में आता है. लेकिन ऐसे भी मंत्री हैं, जिनके पास न कोई ऐसी योग्यता है, न पूंजी है, तो फिर उनके पास इतना पैसा कहां से आया?

अब बात विपक्ष की. कांग्रेस हतोत्साहित हो गई है. उसके 44 सांसद हैं. पहले की 3 लोकसभा में जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब किसी एक विपक्षी पार्टी के पास इतनी भी संख्या नहीं थी कि उसे लीडर अपोजीशन यानी नेता विपक्ष का दर्जा मिल सके, फिर भी वे प्रभावशाली थे. क्योंकि, तब विपक्ष में ऐसे लोग थे, जो अच्छी बहस करते थे, उनके पास तर्क और आंकड़े होते थे सरकार को घेरने के लिए. कांग्रेस को न जाने क्या हो गया है? अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी पार्टी को नेतृत्व देना भी चाहते हैं या नहीं? हालांकि, यह पार्टी की आंतरिक समस्या है. कांग्रेस सौ साल पुरानी पार्टी है. पहुंच और कार्यकर्ताओं के मामले में वह अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है. ठीक है कि भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पांच साल बाद कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी. लेकिन वह कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएगी, यदि वह अच्छा प्रयास नहीं करती है.

ऐसे में यह सराहनीय है कि मुलायम सिंह यादव ने जनता दल या जनता पार्टी को पुनर्जीवित करके एक सशक्त विपक्ष बनाने की पहल शुरू की है. जनता परिवार की एक बैठक हुई है, जो अच्छी रही. उन्हें आगे इस दिशा में काम करना चाहिए कि सबको मिलाकर एक पार्टी बने, एक सिंबल हो, एक झंडा हो. असल में ये सब लोग लोहिया के विचारों वाले हैं. अगर कांग्रेस नेहरू के विचारों वाली पार्टी है, भाजपा दीन दयाल उपाध्याय की विचारधारा वाली पार्टी है, तो समाजवादी लोग लोहिया की विचारधारा से संबंधित हैं. इसलिए मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार एवं शरद यादव में कोई वैचारिक मतभेद नहीं है. जितनी जल्दी ये सब खुद को मिलाकर एक सिंगल पार्टी बना लेते हैं, उतना ही यह मिशन खुद को एक प्रभावी विपक्ष बना पाएगा और अगले चुनाव में एक विकल्प बनकर उभर पाएगा.

आख़िरकार, इस सरकार को आए छह महीने बीत चुके हैं. भाजपा ने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, जैसे काला धन वापस लाना और रोज़गार देना आदि, सरकार उन्हें पूरा करने के आसपास भी पहुंचती नहीं दिख रही है. अब जाकर पता चल रहा है कि इन बड़े वादों को पूरा करना कितना कठिन है. अख़बारों में छपे आलेखों से पता चलता है कि स्विस बैंक से पैसा निकल कर पहले ही मॉरीशस और सिंगापुर के रास्ते भारत पहुंच चुका है. सत्ता के क़रीब रहने वाले लोगों द्वारा लिखे गए आलेखों का अर्थ है कि सत्ता को यह एहसास हो गया है कि इन वादों को पूरा नहीं किया जा सकता. ऐसे में, जनता परिवार उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़मीन तैयार करने के लिए एक जगह इस मांग के साथ एकत्र हो रहा है कि कृषि क्षेत्र को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है. मेक इन इंडिया तो ठीक है, लेकिन कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है. अगर वे ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध करना और उत्तर के इन दो बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों में समृद्धि देखना चाहते हैं, तो उन्हें किसानों को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

फॉलोअप रिपोर्ट का महत्व

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

मुझे एक फॉलोअप रिपोर्ट उदाहरण के रूप में याद आती है. राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद आदिवासी क्षेत्रों में जाने का कार्यक्रम बनाया था. वह देश के कई आदिवासी क्षेत्रों में गए. आदिवासियों की हालत पर अफ़सोस जाहिर किया तथा स्थिति सुधारने के आदेश दिए. मैं किसी रिपोर्ट के सिलसिले में बांदा गया हुआ था. वहां कैप्टन सीबी सिंह ने मुझसे पूछा कि जहां-जहां राजीव गांधी जाते हैं, वहां बाद में कुछ होता है या नहीं. मेरे मन में यह सवाल कौंधने लगा. मैंने एमजे अकबर से पूछा कि मैं एक रिपोर्ट करना चाहता हूं. मुझे नहीं मालूम कि कुछ निकलेगा या नहीं, क्या आप अनुमति देंगे?

उन दिनों मैं टेलीग्रॉफ का विशेष संवाददाता था तथा न्यूज लाइन के लिए विशेष रिपोर्ट करता था. न्यूज लाइन दूरदर्शन पर करंट अफेयर के इतिहास का पहला प्रोग्राम था, जिसे आनंद बाज़ार पत्रिका प्रोड्यूज करती थी तथा एमजे अकबर उसके प्रस्तोता थे. मैंने उनसे कहा कि मुझे एक रिपोर्ट करनी है. पर मैं खुद नहीं जानता था कि कुछ निकलेगा या नहीं. दरअसल,

संवाददाता को चाहिए कि वह घटना का इस तरह से वर्णन करे कि पाठक एक बार रिपोर्ट पढ़ना शुरू करे, तो अंत तक उसे छोड़े नहीं. घटना उसके सामने सिनेमा की तरह तस्वीरों की कड़ी के रूप में घटती दिखाई दे. संवाददाता की हर रिपोर्ट शब्द चित्र होनी चाहिए. खोजी रिपोर्ट के दो ख़तरे हैं. पहला ख़तरा है कि संबंधित पक्ष, चाहे सरकार हो या ठेकेदार, संवाददाता को हानि पहुंचा सकता है और दूसरा यह कि उसे खरीदने की कोशिश की जा सकती है.

मैं राजीव गांधी की आदिवासी क्षेत्रों की यात्रा की फॉलोअप रिपोर्ट करना चाहता था. एमजे अकबर ने बिना सेकेंड लगाए हां कर दी. मैं दिल्ली से कैमरा टीम लेकर राजस्थान गया. मैंने सबसे पहले उस जगह की शूटिंग की, जहां राजीव गांधी जीप पर सवार होकर आदिवासी क्षेत्रों में गए थे. उसी रास्ते को मैंने अपनी रिपोर्ट का विषय बनाया, जिससे होकर वह गुजरे थे.

सबसे पहले मुझे पानी की एक नाली मिली, जिसे सिंचाई की नाली कहकर राजीव गांधी को दिखाया गया था. वह नाली सूखी हुई थी. जब उसकी ईंट उठाई, तो सारा सीमेंट बालू की तरह भरभरा कर उखड़ गया. जिस रास्ते से राजीव गांधी गए, उस पर झाड़-झंखाड़ उग आए थे. मैंने उस भील दंपत्ति को तलाश निकाला, जिसे राजीव गांधी ने सौ रुपये दिए थे तथा आदेश दिया था कि इनकी वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की जाए. भील दंपत्ति ने बताया कि राजीव गांधी के जाने के बाद केवल एक व्यक्ति आया था सरकार की ओर से और वह वे सौ रुपये भी ले गया, जो राजीव गांधी ने उन्हें दिए थे. अब तक उनकी पेंशन स्वीकृत नहीं हुई है. मैं उस आदिवासी स्कूल में गया, जिसे पक्का बनवाने का आदेश राजीव गांधी ने दिया था. वहां का छप्पर भी लगभग गिर चुका था, पक्का होना तो दूर की बात थी. विकास योजनाएं शुरू करने का वादा भी राजीव गांधी ने किया था, पर कहां विकास और कहां की योजनाएं. राजीव गांधी तब भारत के सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री थे.

मैंने अपनी यह फॉलोअप स्टोरी ठीक उस दिन की, जिस दिन राजीव गांधी को उस क्षेत्र में गए छह महीने समाप्त हुए थे. यह रिपोर्ट न्यूज लाइन प्रोग्राम में दूरदर्शन पर आई. तब गोपी अरोड़ा ने यह रिपोर्ट रोकने की कोशिश की, वह तब प्रधानमंत्री के सचिव थे, पर राजीव गांधी के हस्तक्षेप से यह रिपोर्ट दूरदर्शन पर आई. इस रिपोर्ट के आते ही राजस्थान सरकार घबरा गई, ताबड़तोड़ बयान आए, पर राजीव गांधी ने कुछ दिनों बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री हरदेव जोशी का त्याग-पत्र ले लिया. न मुझे मालूम था कि यह रिपोर्ट क्या असर करेगी और न एमजे अकबर को मालूम था कि उनका न्यूज लाइन का प्रोग्राम केवल 13 एपिसोड के बाद बंद करा दिया जाएगा, क्योंकि गोपी अरोड़ा ने राजीव गांधी को समझा लिया था कि यदि न्यूज लाइन चलानी है, तो फिर और किसी विरोध की ज़रूरत नहीं है. एमजे अकबर के संपादन में चलने वाले न्यूज लाइन कार्यक्रम को देश के टीवी इतिहास के पहले न्यूज करंट अफेयर प्रोग्राम के रूप में तो स्थान मिला ही, पर यह कार्यक्रम आज

रिपोर्ट के आते ही राजस्थान सरकार घबरा गई, ताबड़तोड़ बयान आए, पर राजीव गांधी ने कुछ दिनों बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री हरदेव जोशी का त्याग-पत्र ले लिया. न मुझे मालूम था कि यह रिपोर्ट क्या असर करेगी और न एमजे अकबर को मालूम था कि उनका न्यूज लाइन का प्रोग्राम केवल 13 एपिसोड के बाद बंद करा दिया जाएगा, क्योंकि गोपी अरोड़ा ने राजीव गांधी को समझा लिया था कि यदि न्यूज लाइन चलानी है, तो फिर और किसी विरोध की ज़रूरत नहीं है.

के टीवी चैनलों के लिए पाठ्य पुस्तक का भी काम बखूबी कर सकता है. यह ताकत फॉलोअप रिपोर्ट की होती है.

संवाददाता के लिए आवश्यक है कि उसे समाचारों की समझ हो, वह पाठकों की नब्ज पहचानता हो, उसकी शैली रोचक हो तथा उसकी दृष्टि मानवीय हो. सच्ची घटनाओं और समाचारों को वह रोचक शैली में प्रस्तुत करे, जिससे पाठक रोमांचित हो जाए और शासन-तंत्र दहल जाए. पर रोचक शैली का मतलब अलंकार या अनुप्रास का उपयोग नहीं है. संवाददाता को चाहिए कि वह घटना का इस तरह से वर्णन करे कि पाठक एक बार रिपोर्ट पढ़ना शुरू करे, तो अंत तक उसे छोड़े नहीं. इतना ही नहीं, घटना उसके सामने सिनेमा की तरह तस्वीरों की कड़ी के रूप में घटती दिखाई दे. संवाददाता की हर रिपोर्ट शब्द चित्र होनी चाहिए. जो संवाददाता इस तरह की रिपोर्ट लिखते हैं, पाठक उनके नाम से रिपोर्ट न केवल पढ़ते हैं, बल्कि विश्वास भी करते हैं.

आम रिपोर्ट में संवाददाता छूट ले सकता है, पर खोजी रिपोर्ट में नहीं. खोजी रिपोर्ट लिखने के लिए पहले मन बनाना पड़ता है, क्योंकि खोजी रिपोर्ट के दो ख़तरे हैं. पहला ख़तरा है कि संबंधित पक्ष, चाहे सरकार हो या ठेकेदार, संवाददाता को हानि पहुंचा सकता है और दूसरा यह कि उसे खरीदने की कोशिश की जा सकती है. खोजी रिपोर्ट एक तरह से प्रमाणों से युक्त जांच एजेंसी की रिपोर्ट की तरह होती है, जिसमें दोनों पक्षों की बात की कोई जगह नहीं होती है. इस रिपोर्ट को संवादाता अपनी जांच की तरह लिखता है, जिसकी सच्चाई के पक्ष में प्रमाणों के साथ वह अपनी जांच प्रक्रिया की गवाही देता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

प्रधानमंत्री जी, अफ़वाहों पर तुरंत रोक लगाइए

मैं यह नहीं कहता कि प्रधानमंत्री जी को, देश में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन अपना कर्तव्य बनता है कि आगे आने वाले अच्छे या बुरे संकेतों को हम प्रधानमंत्री से भी बांटें. मैं यह भी मानता हूं कि जिस बात का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन नहीं हासिल होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों में काफी ऐसे होंगे, जिन्हें यह लगता होगा कि इस देश में अब वे कुछ भी कर सकते हैं. न उनसे कोई जवाब मांगने वाला है और न कोई उन्हें रोकने वाला.

सोशल मीडिया और फेसबुक पर एक कैंपेन चल रहा है. कैंपेन है कि अब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, तो यहां पर रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते और वे यहां रहकर हमारे विकास में हिस्सेदारी क्यों कर रहे हैं. इस कैंपेन का दूसरा बड़ा हिस्सा है कि आज़ादी के समय इतने हिंदू थे, इतने मुसलमान थे और अब इतने हिंदू हैं, इतने मुसलमान हैं तथा कुछ आंकड़े फैलाए जा रहे हैं, जिनकी सत्यता पर कोई दावा नहीं करता, लेकिन वे आंकड़े फैल रहे हैं. तीसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत कैंपेन का हिस्सा है कि कहीं भी गाड़ियों से लोग जाते हुए रुक जाते हैं, जहां मध्यम वर्ग और निम्न-मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, वहीं उतर कर वे बात करने लगते हैं कि भाई, मुसलमान यहां क्यों हैं, अब मुसलमानों का यहां क्या काम? ज़्यादातर लोग, देखा गया है कि ऐसी बातें सुनकर उठ जाते हैं, पर एक भी बैठा रहा, तो इस अफ़वाह या इस विचार को फैलाने वाला शख्स उस एक व्यक्ति को ही समझाने की कोशिश करता है. उत्तर भारत के ज़्यादातर शहरों में अचानक इस तरह की घटनाएं छिपे तौर पर होती दिखाई दे रही हैं.

हम जिसे सोशल मीडिया कहते हैं, जिसमें फेसबुक शामिल है, वह इस तरह की बातें फैलाने का एक प्रमुख क्षेत्र बन गया है. ऐसा लगता है कि जैसे दो-तीन लोगों की टीम इस तरह के पोस्ट करने में ही लगी हुई हैं. तब आख़िर ये दो-दो, तीन-तीन लोगों की टीमें किसके इशारे पर यह काम कर रही हैं? ये क्यों इस देश में भाईचारे के ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने के लिए छोटी-छोटी अफ़वाहों के रूप में समाचारों को फैला रही हैं. इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही केंद्र है और वह केंद्र है, देश का मुस्लिम समाज.

क्या ये घटनाएं सिर्फ़ आने वाले चुनावों में वोट लेने के लिए एक माहौल तैयार कर रही हैं या इसके पीछे कोई बड़ी साजिशी योजना काम कर रही है? बड़ी साजिशी योजना एक ही हो सकती है कि देश में फिर से एक बार इतिहास के सबसे बड़े दंगों को दोहराने की कोशिश की जाए, ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके. लोकतंत्र में वोट बहुत आवश्यक हैं, लेकिन लोकतंत्र में जीवन भी बहुत आवश्यक है, लोकतंत्र में भाईचारा भी बहुत आवश्यक है और लोकतंत्र में विकास भी बहुत आवश्यक है. इस तरह की अफ़वाहों, जो इन दिनों फेसबुक और फेसबुक का जो दूसरा आधुनिक तरीका है वाट्सऐप, के ऊपर तैर रही हैं, को फैलाने की साजिश आख़िर कहना क्या चाहती है? हमारे यहां एक भेड़-चाल है, इसीलिए कहावत बनी है कि कौआ कान ले गया. जब एक चिल्लाता है कि देखो, कौआ कान ले गया, तो दस लोग कान की तरफ़ देखने की बजाय कि वह है भी या नहीं, कौए की तरफ़ देखने लगते हैं कि कौआ कहां कान ले करके गया और यह मनोविज्ञान इस तरह के तथ्यों को सत्यापित नहीं करने देता. सिर्फ़ एक चीज पढ़कर उसके ऊपर सहज विश्वास कर लेना, जो आख़िर में जाकर हमारे मन में ही एक संशय को जन्म दे देता है.

मैं अपना एक उदाहरण बताता हूं कि फेसबुक पर किसी का संदेश आया कि राजस्थान के एक ज़िले के चार लड़के चेन्नई में भयानक एक्सीडेंट के शिकार हो गए हैं और चारों के चारों वहां के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं और सभी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनके घर वालों को पता लग सके. मैंने इस समाचार के ऊपर, जो फेसबुक पर आया था, विश्वास करके फौरन ईटीवी के लोगों को फोन किया और उनसे आग्रह किया कि चूंकि राजस्थान का मसला है, इसलिए आप इसे एक प्रमुख समाचार के रूप में दिखा दें. ईटीवी वालों ने मेरी बात पर भरोसा करते हुए उस समाचार को दिखा दिया. वह समाचार दिखाने के दस मिनट के भीतर उन लड़कों के घर वालों ने ईटीवी को फोन किया कि यह तो दो महीने पुरानी घटना है और वे लड़के आ भी गए हैं और उनमें एक लड़के की मृत्यु भी वहां हो चुकी है. पर यह सब दो महीने पहले हुआ. ईटीवी वालों ने मुझे फोन किया. मैंने उनसे क्षमा मांगी. मैं सिर्फ़ यह बताना चाहता हूं कि इस तरह की ग़ैर-ज़िम्मेदाराना चीजें वाट्सऐप और फेसबुक के जरिये जब फैलाई जा सकती हैं और मेरे जैसा आदमी जब उन्हें सत्यापित नहीं करता, तो इस देश के बहुत सारे साधारण लोग उन आंकड़ों को सत्यापित कैसे करेंगे या उन बातों का सत्यापन कैसे करेंगे, जिनका अफ़वाह के रूप में फेसबुक और वाट्सऐप के जरिये संप्रेषण हो रहा है.

इसलिए एक तरफ़ सरकार को बहुत सचेत होने की ज़रूरत है कि वह इस तरह की पोस्ट को, इस तरह की अफ़वाहों को, जिनका वाट्सऐप और फेसबुक पर इस्तेमाल हो रहा है, तत्काल रोके तथा दोषी लोगों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर मुकदमा चलाए. दूसरी तरफ़ वे सारे लोग, जो देश की सांस्कृतिक एकता में भरोसा करते हैं, जब इसे देखें, तो इसका विरोध करें. अक्सर लोग खामोश या तटस्थ रह जाते हैं और वह खामोशी या तटस्थता एक बड़े कांड की भूमिका बन सकती है. अगर इस तरह की अफ़वाहों को अनदेखा कर दें, तो ये अफ़वाहें धीरे-धीरे लोगों के मन में सत्य के रूप में अपनी जड़ें जमा लेंगी और उस समय उन लोगों का काम आसान हो जाएगा, जो देश में अस्थिरता और अशांति चाहते हैं. जिन्हें लगता है कि सिर्फ़ यही एक रास्ता है, जिसके जरिये बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाकर, लोगों को भावनात्मक तरीके से जागृत कर अपने पक्ष में वोट लिया जा सकता है. ये फासिस्ट तरीके हैं, जिनका इस्तेमाल किसी जमाने में मुसोलिनी और हिटलर कर चुके हैं. अब उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल अगर फिर से होते हुए हम देखें, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए.

सोशल मीडिया और फेसबुक पर एक कैंपेन चल रहा है. कैंपेन है कि अब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, तो यहां पर रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते और वे यहां रहकर हमारे विकास में हिस्सेदारी क्यों कर रहे हैं. इस कैंपेन का दूसरा बड़ा हिस्सा है कि आज़ादी के समय इतने हिंदू थे, इतने मुसलमान थे और अब इतने हिंदू हैं, इतने मुसलमान हैं तथा कुछ आंकड़े फैलाए जा रहे हैं, जिनकी सत्यता पर कोई दावा नहीं करता, लेकिन वे आंकड़े फैल रहे हैं. तीसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत कैंपेन का हिस्सा है कि कहीं भी गाड़ियों से लोग जाते हुए रुक जाते हैं, जहां मध्यम वर्ग और निम्न-मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, वहीं उतर कर वे बात करने लगते हैं कि भाई, मुसलमान यहां क्यों हैं, अब मुसलमानों का यहां क्या काम?

इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि अब वह देश के प्रधानमंत्री हैं और देश की संपूर्ण एकता उनकी संवैधानिक ज़िम्मेदारी भी है और क़ानूनी ज़िम्मेदारी भी है. इसलिए उन्हें अपनी मशीनरी को उन सभी लोगों के ऊपर नज़र रखने के लिए कहना चाहिए, जो नाम तो उनका लेंगे और काम देशद्रोह का करेंगे. वे लोग नरेंद्र मोदी के हितैषी नहीं हैं, नरेंद्र मोदी के दुश्मन हैं, क्योंकि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इस देश को एक रखना और विकास की तरफ़ ले जाना है. इसलिए इसके ऊपर नज़र रखने का काम अधिकारियों द्वारा, अपनी पार्टी द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अगर किसी का बुनियादी दायित्व है, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दायित्व है. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

चीन को चीन के अंदाज़ में जवाब

भारत को अच्छी तरह से मालूम है कि चीन सागर के उत्तर में चीन का जापान के साथ विवाद है. उसी विवाद से निपटने के लिए प्रधानमंत्री शिंजो अबे जापान के शांतिवादी संविधान में संशोधन के बिना उससे बाहर निकलने पर मजबूर हैं. मोदी के अबे के साथ अच्छे संबंध हैं. सरकारी तौर पर यह ज़रूर कहा जाएगा कि वियतनाम के साथ भारत का सहयोग किसी रणनीति का नतीजा नहीं है, लेकिन इस सहयोग के लिए जो समय चुना गया है, वह बहुत दिलचस्प है.

महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी पीढ़ी के दिग्गज नेता एसके पाटिल ने एक बार कहा था, जब रोम जाओ, तो रोमानिया वासियों की तरह से व्यवहार करना शुरू कर दो. उनके इस वक्तव्य में हास्य के साथ-साथ बुद्धिमत्ता का पहलू भी शामिल था. ऐसा लगता है कि चीनियों के साथ रिश्तों के संबंध में नरेंद्र मोदी इसी नीति को अपनाना चाहते हैं. दरअसल, इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि वह करो, जिसकी चीन को आपसे सबसे कम अपेक्षा हो यानी चीन के मामले में जापानियों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दो.

हेनरी किसिंजर ने चीन के ऊपर एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर चीनी रवैये की बड़ी सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की है. वह लिखते हैं कि चीन अपनी सीमा से लगे जिन देशों की सीमा को विवादित समझता है, उनकी सीमा में उसकी सेना घुसपैठ करती है और खुद-ब-खुद वापस चली जाती है, जैसे घुसपैठ कभी हुई ही नहीं थी. लेकिन, वह इससे यह संदेश देना चाहता है कि वह अपनी इच्छानुसार विवादित क्षेत्र पर जब चाहे, क़ब्ज़ा कर सकता है और यह कि क़ब्ज़ा करना या न करना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है.

कुछ यही हाल 1962 में भारत और चीन के बीच दो मुठभेड़ों के दौरान हुआ था. जवाहर लाल नेहरू यह सोच रहे थे कि भारत चीनियों को खदेड़ देगा. नतीजतन, दोनों तरफ़ से जमकर शक्ति प्रदर्शन हुआ, जिसमें भारत को हार की शर्मिंदगी उठानी पड़ी और (जहां तक मुझे याद है) चीनी सेना की एकतरफ़ा वापसी ने जैसे ज़ख्म पर नमक छिड़कने का काम किया था. हाल में भारत-चीन सीमा पर चीन की तरफ़ से घुसपैठ और फिर एकतरफ़ा वापसी की नीति एक बार फिर दोहराई गई. हालांकि यह भारत की नीति नहीं है, लेकिन कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर चीन की यह नीति आजमाई जा सकती है. पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर भारत इस नीति को अपनाए, तो मुझे पूरा यकीन है कि इसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे. यह बिना आक्रामक हुए ही आक्रामक होने का एक तरीका है.

आम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान

आम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर नर्म रुख अपना रखा था, लेकिन उन्होंने हिमालयी सरहद के मुद्दे को बड़े जोर-शोर से उठाया था. उन्होंने आम चुनाव में निर्णायक जीत के बाद से नियंत्रण रेखा को लेकर एक संयमित नीति अपना रखी है, हालांकि आक्रामक बयानबाज़ी जारी है.

पर नर्म रुख अपना रखा था, लेकिन उन्होंने हिमालयी सरहद के मुद्दे को बड़े जोर-शोर से उठाया था. उन्होंने आम चुनाव में निर्णायक जीत के बाद से नियंत्रण रेखा को लेकर एक संयमित नीति अपना रखी है, हालांकि आक्रामक बयानबाज़ी जारी है. जहां तक भारत-पाकिस्तान सीमा विवाद का प्रश्न है, तो इसे लेकर कोई नीतिगत परिवर्तन नहीं होगा. बहरहाल, चीन ज़रूर मोदी के संकल्प की परीक्षा ले रहा है. जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अहमदाबाद में खामन ढोकला और गरबा रास का आनंद उठा रहे थे, तब चीनी सेना भारतीय सीमा में बार-बार घुसपैठ कर रही थी. यह घटना साबित करती है कि या तो शी की कथनी और करनी में अंतर है या फिर चीनी सेना पर उनका नियंत्रण नहीं है.

संसार की छत कही जाने वाली इस लंबी सीमा पर चीनी सेना भारत के मुकाबले ज़्यादा मज़बूत और बेहतर साज़ो-सामान से लैस है. गंभीर मुठभेड़ की स्थिति में भारतीय सैनिकों के लिए चीनियों से मुकाबला करना कठिन होगा. हालांकि सरकार ने बेहतर तैयारी और अधिक संसाधन मुहैया कराने की घोषणा की है, लेकिन उसमें समय लगेगा. फ़िलहाल भारत को मालूम है कि वह चीन से इतने बड़े क्षेत्र में और इतनी ऊंचाई पर खुली जंग नहीं जीत सकता. इससे यह बात समझ में आ जाती है कि भारत ने अपनी विदेश और रक्षा नीति में कुछ अभूतपूर्व क़दम क्यों उठाए? वियतनाम के साथ समुद्र तल पर कच्चे तेल की खोज का समझौता और समुद्र तल पर स्थित उसके तेल के कुओं की रक्षा में सहयोग का भारतीय प्रस्ताव चीन को मुंह चिढ़ाने जैसा है. चीन और वियतनाम के बीच दक्षिण चीन सागर में बहुत समय से विवाद चल रहा है. इस क्षेत्र के फिलिपीन जैसे अन्य देशों ने भी अंतरराष्ट्रीय समुद्री क़ानून के आधार पर चीनी संप्रभुता की व्याख्या को चुनौती दी है, जो यहां ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है. भारत वियतनाम की सहायता कर रहा है, जिस पर चीन को आपत्ति है. लेकिन, वियतनाम की सहायता का यह क़दम बेख्याली में नहीं उठाया जा सकता है. दरअसल, भारत एक रणनीति के तहत चीन को यह जताने की कोशिश कर रहा है कि एक से अधिक सीमाएं हैं, जहां चीन की गर्दन मरोड़ी जा सकती है.

लिहाज़ा मैं यह कहूंगा कि भारत चीन की चाल उसी के ऊपर आजमा रहा है. यह भारत को अच्छी तरह से मालूम है कि चीन सागर के उत्तर में चीन का जापान के साथ विवाद है. उसी विवाद से निपटने के लिए प्रधानमंत्री शिंजो अबे जापान के शांतिवादी संविधान में संशोधन के बिना उससे बाहर निकलने पर मजबूर हैं. मोदी के अबे के साथ अच्छे संबंध हैं. सरकारी तौर पर यह ज़रूर कहा जाएगा कि वियतनाम के साथ भारत का सहयोग किसी रणनीति का नतीजा नहीं है, लेकिन इस सहयोग के लिए जो समय चुना गया है, वह बहुत दिलचस्प है. मोदी अभी हाल में अमेरिका गए थे, जहां उन्होंने बराक ओबामा से मुलाक़ात की. ओबमा पहले से यह घोषणा कर चुके हैं कि अमेरिकी नीति का झुकाव प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के पक्ष में होगा. इस तरह यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अबे और ओबामा (जिनके मोदी के साथ मधुर संबंध हैं) मोदी की वियतनाम नीति से खुश होंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

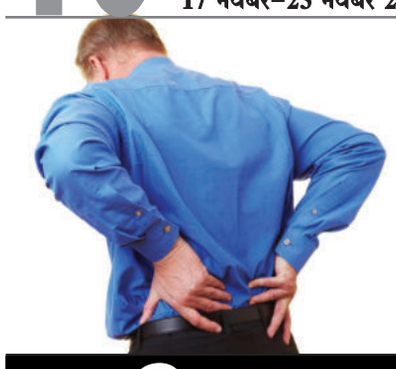

लोग अक्सर आगे की ओर झुक कर बैठते या चलते हैं. इस मुद्रा से टांगों के पिछले निचले हिस्से की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है. इसलिए यह जरूरी है कि ऑफिस में जिस कुर्सी पर बैठते हो वह सही हो और आपकी पीठ को सपोर्ट देती हो. इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लंबे समय तक कुर्सी पर न बैठें हर एक घंटे कुर्सी पर बैठने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें. क्योंकि लगातार बैठने से आपकी रीढ़ की हड्डी में तनाव पैदा हो सकता है.

महिला अरब जासूस अमीना दाऊद मुफ्ती

मोहब्बत और इंतकाम की दास्तान

वसीम अहमद

एक कहावत बेहद मशहूर है कि महिला मोहब्बत में अपनी जान खुशी–खुशी कुर्बान कर देती है और जब बदला लेने पर आती है, तो पूरे समाज को हिलाकर रख देती है. ऐसा ही कुछ ओमान की एक खूबसूरत महिला के साथ पेश आया. वह अपने महबूब को दिल–ओ–जान से चाहती थी. उसके एक इशारे पर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थी. उसकी खुशी के लिए उसने अपना वतन छोड़ा अपनी तमन्नाओं को दफन किया एवं अपनों की दुश्मनी मोल ली, लेकिन जब उसे पता चला कि वह जिसके लिए यह सब कुछ कर रही है. वह किसी और की याद में आहें भरता है, तो उसका दिल टूट गया और यहीं से उसके जीवन ने एक नया मोड़ लिया. वह जासूसी की दुनिया की अपने समय की बेताज महारानी बनकर सैकड़ों अरब महिलाओं को विधवा बनाने का सपना देखने लगी. यह दास्तान है अरब के ओमान में पहाड़ी क्षेत्रों में पलने वाली एक अमीना दाऊद मुफ्ती की. अमीना का जन्म 1939 में चरकेश कबीले में हुआ था. ये कबीला रूस के क़फक़ाज क्षेत्र से आकर यहां बसा था. अमीना अपने कबीले की चंचल और शोख हसीना थी. कबीले का हर जवान उसको हासिल करने का सपना देखता था, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था. अभी उसने जवानी की दहलीज पर ही कदम रखा था कि अज्ञात कारणों की वजह से उसके माता–पिता अपनी इस चांद सी बेटी को लेकर जॉर्डन चले गए. और वहीं बस गए. यहां आकर अमीना की योग्यता परवान चढ़ने लगी. वह सियासी एवं सामाजिक गतिविधियों में बढ़–चढ़कर भाग लेने लगी. बेहद खूबसूरत होने के साथ–साथ व्यवहारिक योग्यता ने अमीना को हर दिल की धड़कन बना दिया. लेकिन यह बात कोई और नहीं जानता था कि उसके दिल की धड़कन फिलिस्तीन का एक सुंदर नौजवान था. अमीना उसकी गंभीरता, बुद्धिमता एवं गठीले बदन से बहुत प्रभावित थी, लेकिन इसके बावजूद वह इस बात से बे–ख़बर थी कि जिस नौजवान को वह सपनों का सौदागर समझती है उसके दिल में कोई और बसी है. जब उसे इस बात का पता चला तो उसे बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन वह अपना हिम्मत नहीं हारी. अमीना ने अपनी शिक्षा जारी रखी और इस दौरान अपने महबूब को पाने की इच्छा को अपने सीने से लगाए रही. वह चाहती थी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करेक अपने महबूब के दिल में जगह बनाए, लेकिन बारहवीं कक्षा पास करने के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए यूरोप चली गईं. 1997 में उसने विएना विश्वविद्यालय में दाखिला लिया. वहां उसकी मुलाकात ऑस्ट्रिया की एक छात्रा साज़ा से हुई. वह अपने दोस्तों के बीच जूली के नाम से प्रसिद्ध थीं. फिर अमीना की उससे दोस्ती हो गई. अमीना वियाना में कई साल तक रहीं. इस दौरान उसने स्वयं को शिक्षा में व्यस्त रखा, लेकिन वो अपने फिलस्तीनी महबूब को एक पल के लिए भी भुला नहीं पाईं. वह उससे मिलने के लिए अगस्त 1961 में वापस ओमान आई, लेकिन यहां आकर उसे जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि जिससे मिलने के लिए वह लंबी यात्रा करके आई थी, मालूम हुआ कि उसने एक भूरी आंखों वाली लड़की से विवाह कर लिया है. यह समाचार सुनकर वह टूट गई. लाख कोशिशों के बावजूद वह उस नौजवान को दिल से नहीं निकाल पा रही थी. स्वयं को व्यस्त रखने के लिए वह ओमान से ऑस्ट्रिया चली गई और वहां बच्चों की एक प्ले वर्कशॉप ज्वाइन कर ली. इस वर्कशॉप में उसकी भेंट एक यहूदी लड़की शारा विराद से हुई और ये दोनों एक साथ रहने लगीं. अमीना एक दिन शारा के घर गईं, वहां शारा के सात साल बड़े भाई मोशिया से उसकी आंखें दो चार हुईं. मोशिया एक सुंदर एवं धीरे बोलने वाला फौज में कप्तान रैंक का पायलट था. धीरे–धीरे दोनों की मुलाकात का सिलसिला बढ़ता गया. ये मुलाक़ात धीरे–धीरे मोहब्बत में बदल जाती है. पांच साल तक तक मोहब्बत परवान चढ़ती गई. इस दौरान मोशिया ने मेडिकल साइंस ऑफ साइकोलॉजी में पीएचडी की डिग्री हासिल करने में अमीना की बहुत सहायता की. इसके बाद वह 1966 में जॉर्डन आ गई. इस दौरान उन्होंने एक स्थानीय समाचार पत्र में एक विज्ञापन देखा. इसमें शारीरिक तौर पर असमर्थ लोगों के एक हॉस्पीटल को किराए पर देने की बात थी. यह हॉस्पीटल स्वास्थ्य मंत्रालय के अर्न्तगत था. वह अगले दिन मंत्रालय में जाकर वह इस हॉस्पीटल को किराये पर ले लेती हैं. लेकिन कुछ महीने बाद हॉस्पीटल में वित्तीय घोटाले होने की वजह से सरकार ने इस डील को स्थगित कर दिया गया. मंत्रालय के इस रवैये से अमीना को बहुत दुख पहुंचता है. एक ओर अपने पहले महबूब से मिली बेवफाई उसके बाद मंत्रालय की ओर से वित्तीय घोटाले के आरोप ने अरबों के संबंध में उसके दिल में नफरत भर दी. वो इसी हालत में जून–1967 में फिर ऑस्ट्रिया चली गईं. इसके बाद उन्होंने अपने यहूदी महबूब माशिया से विवाह कर लिया. इसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर आनी मोर्शिया बिराद रख लेती है. वह अपने यहूदी पति मोशिया विराद के साथ एक फ्लैट में रहने लगती है, लेकिन यह भय उसे बराबर सता रहा था कि एक यहूदी से शादी करने के कारण अरबी लोग उसकी हत्या कर

देंगे. इसलिए वह हर एक नजर से बचकर गुमनामी का जीवन व्यतीत करने लगीं. 1972 में गर्मी की एक सुबह ऑस्ट्रिया के एक समाचार पत्र में एक विज्ञापन छपा. यह उनेक लिए मुंह मांगी मुराद के पूरा होने जैसा था. इजरायल को अपनी सुरक्षा सेना के लिए एक यूरोपीय यहूदी कार्यकर्ता की आवश्यकता थी. इसके लिए उन्होंने अपने पति को राजी कर लिया और जनवरी 1972 में इजरायल के लिए रवाना हो गई. जहां उसका भव्य स्वागत हुआ. पति–पत्नी दोनों को रिसोन गेस्ट हाउस में ठहरया गया. वहीं उसकी भेंट इजरायल के उच्चाधिकारियों से कराई गई. जिन्होंने उसके देश, परिवार विवाह एवं राजनीतिक दिलचस्पयों के संबंध में बहुत से प्रश्न किए गए. इसके बाद उसे रक्षा विभाग में शामिल कर लिया गया. इजरायल से जुड़ने के बाद वह बहुत खुश थी, लेकिन ये प्रसन्नता लंबे समय तक कायम नहीं रह सकी. क्योंकि उसके पति मोशिया विराद जिस हवाई जहाज को लेकर सीरिया पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे, वह सीरियाई मिसाइल ने निशाने पर आ गया. और वह मारा गया. इजरायल ने पायलट की जली हुई लाश को पाने की कोशिश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला.

यह खबर आनी पर बिजली बनकर गिरी और वह पागल की तरह चीखने चिल्लाने लगी. इसके बाद आनी के अंदर अरबों के विरुद्ध नफरत की आग और अधिक भड़कने लगी. वह अपने पति का बदला अरबों से लेना चाहती थी. यह सब करने के पहले वह बियाना के उस फ्लैट में गई जहां उसके पति की बहुत सी यादें मौजूद थीं. वह रात में वहीं रुकीं. सुबह सवेरे तीन इजरायली अधिकारियों ने उसे जगाया वास्तव उसके ससुराल वाले चाहते थे कि मोशिया का मुआवजा जो आधे मिलियन डॉलर और गेस्ट हाउस का वही फ्लैट जिसमें वह दोनों रहते थे को लेकर खामोशी से जीवन गुजार लिया जाए. इस सिलसिले में वो तीनों अधिकारी उससे बातचीत करने आए थे, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही लहर थी वह अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े.

उसने मुआवजा लेने के बजाए स्वयं इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का भाग बन गई. इसके बाद जासूसी की ट्रेनिंग ली और बारीकियों को सीखना–समझना शुरू कर दिया. उसके बाद वो बेरुत आईं जिससे कि वह अपने बदले की कार्रवाई को जारी रख सके. उसने वहीं से फिलिस्तीन से जुड़ी खुफिया जानकारी इजरायल भेजना शुरू की, लेकिन सितंबर 1975 में फिलिस्तीनी सरकार ने उसे देश का राज चुराने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया. वह पांच साल तक वो जेल में रही. इसके बाद इजरायल ने दो फिलस्तीनी बंदियों के बदले आनी को आजाद करा लिया. उसके बाद वो फिर इजरायल आ गई और वहां से उसने जॉर्डन में अपने संबंधियों को फोन किया, लेकिन उन्होंने यह कहकर उससे बात करने से इनकार कर दिया कि वह उनकी नजर में मर चुकी है. उसके बाद आनी के बारे में कोई समाचार नहीं मिला कि वह कहां और किस हाल में है. अलबत्ता 1984 में इजरायली सेना की पत्रिका बौमहानी में एक खबर छपी कि रक्षा मंत्रालय ने आनी मोशिया विराद की सेवाओं को देखते हुए उसे वजीफा देने का निर्णय लिया है. इजरायल का यह फैसला ठीक उसी तरह था जिस तरह ब्रिटेन ने 1949 में नूर इनायत खां(देखिए चौथी दुनिया 3 से 9 नवंबर 2014) को ब्रिटिश जार्ज क्राश अवार्ड, फ्रांस ने क्रोएक्स डी गोएरे पुरस्कार दिया गया. रॉयल मेल ने 25 मार्च 2014 को उस पर टिकट जारी कर उसकी सेवाओं को मान्यता दी थी. ■

feedback@chauthiduniya.com

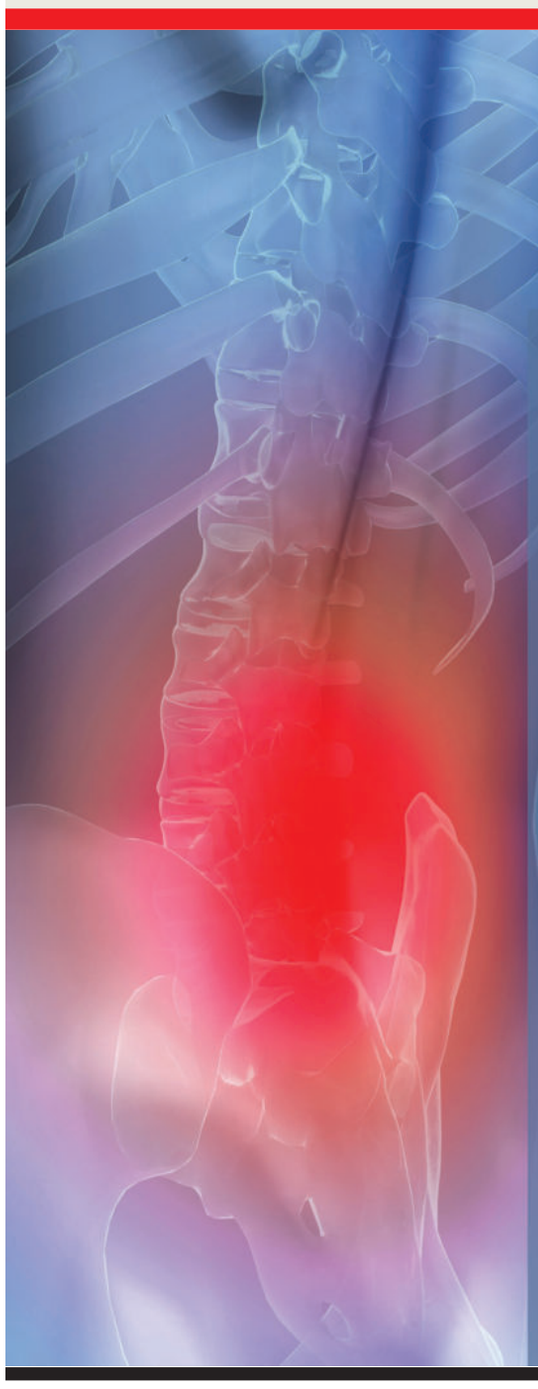

पीठ दर्द को हल्के में न लें

आजकल लोगों की पीठ में दर्द होना आम बात हो गई है. दिन भर ऑफिस में कुर्सी पर बैठने, दिन भर खड़े रहने या इस जैसे कई अन्य कारणों से पीठ का दर्द हो सकता है . पीठ का दर्द हमारे हर प्रकार के आनंद को समाप्त कर देता है बावजूद इसके हम इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं. यह बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि पीठ की समस्याएं रातों–रात पैदा नहीं होतीं. यह कई घटनाओं या अस्त–व्यस्त जीवनशैली का परिणाम होती है. जैसे कि शरीर का ज्यादा वजन, सोने का असामान्य तरीका, मानसिक तनाव आदि. यह सभी एक लंबे समय के दौरान एकत्रित होती है और पीठ दर्द के रूप में सामूहिक रूप से दिखाई देती है. पूरी दुनिया के तकरीबन 80 प्रतिशत लोगों को जीवन के किसी न किसी स्तर पर पीठ संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. यह कोई एक समस्या हो सकती है या कई समस्याओं का जोड़ भी. डॉक्टरों का कहना है कि पीठ दर्द के लिए बाज़ार में कई तरह की दवाएं उपलब्ध हैं लेकिन इस समस्या से दीर्घकालिक आराम के लिए जीवनशैली में मूलभूत परिवर्तन करना बहुत जरूरी है. जहां तक पीठ दर्द की बात है तो रोजमर्रा की जिंदगी में आसान उपायों को अपनाकर जैसे कि सीधे बैठना, नियमित तौर पर चलना, वजन कम करना, संतुलित भोजन तथा कुछ खास तरह की खसरत करकर इससे बचा जा सकता है. हो रहे दर्द का इलाज किया जा सकता है. किसी भी अन्य समस्या की तरह पीठ दर्द के लक्षणों को नजरअंदाज न करें और इलाज में देरी न करें. पीठ का दर्द कभी भी अपने आप नहीं जाता. इसके लिए आपको कुछ न कुछ उपाय करना पड़ता है. इस समस्या को गंभीर होने देने से बचाव के लिए शुरूआत में ही जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करके इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है. अन्यथा सर्जरी ही इसका अंतिम इलाज है.

पैदल चलना : नियमित तौर पर पैदल चलना ही पीठ के दर्द को रोकने का सबसे कारगर तरीका है. आपके जूते चप्पलों का आपकी पीठ पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है. आरामदायक जूते बहुत ही महत्वपूर्ण हैं पैरों की सुरक्षा के साथ –साथ वह शरीर और रीढ़ की हड्डी को एक सीध में रखते हैं. आरामदायक जूते मांसपेशियों में मोच या खिंचाव को होने से रोकते हैं. हाई हील वाले सैंडल लंबे समय तक पहनने से पीठ के निचले हिस्से पर खिंचाव या मोच की समस्या आ सकती है.

पीठ पर कम वजन डालें: आकार में बहुत बड़े हैंड बैग्स, लैपटॉप बैग्स तथा ट्रैवल बैग्स अत्यधिक आरामदायक दिख सकते हैं परंतु वास्तव में इनसे चोट लगने की संभावना रहती है. सामान्य तौर पर आपका बैग आपके शरीर के वजन के 10 प्रतिशत से अधिक वजन वाला नहीं होना चाहिए. बैग की दोनों स्ट्राइप का इस्तेमाल करना चाहिए. एक ही कंधे पर बैग का वजन डालने से पीठ दर्द की समस्या उत्पन्न होती है. पीठ पर बैग से खिंचाव न होने दें और जहां तक हो सके पीठ पर कम से कम वजन लेकर चलें.

सही गद्दे का चुनाव: लोगों में इस बात को लेकर गलत फहमी है कि सोते समय चोट नहीं लग सकती. लेकिन हक़ीकत यह है कि सही तरह से और सही तरह के गद्दे का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से पीठ दर्द की समस्या उभरती है. दिन भर काम करने के बाद जब आप सो रहे होते हैं तभी रीढ़ की हड्डी को आराम करने का अवसर मिलता है. सही ढंग से सोकर आप आप अपनी पीठ की रक्षा कर सकते हैं. सोते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका गद्दा न तो अधिक सख्त हो और न ही अधिक नर्म. यह ऊंचाई में 5 इंच से अधिक का भी नहीं होना चाहिए. चूंकि हमारी रीढ़ की हड्डी कर्वी होती है इसलिए हमें फर्श पर सोने या अत्यधिक नर्म गद्दे पर सोने जैसे विकल्प नहीं चुनने चाहिए.

काम के दौरान ब्रेक लें: लोग अक्सर आगे की ओर झुक कर बैठते या चलते हैं. इस मुद्रा से टांगों के पिछले निचले हिस्से की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है. इसलिए यह जरूरी है कि ऑफिस में जिस कुर्सी पर बैठते हो वह सही हो और आपकी पीठ को सपोर्ट देती हो. इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लंबे समय तक कुर्सी पर न बैठें हर एक घंटे कुर्सी पर बैठने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें. क्योंकि लगातार बैठने से आपकी रीढ़ की हड्डी में तनाव पैदा हो सकता है.

वजन कम करें: शरीर का वजन कम करना हमेशा सही रहता है. शरीर का अधिक वजन होना ठीक उस तरह है जेसे आप सदैव बीस किमी का वजन उठाए रहते हों. अपना वजन कम करके आप अपनी पीठ की रक्षा कर सकते हैं. अधिक वजन से छुटकारा पाना आपकी पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव से छुटकारा दिलाने में सहायक होता है. कैल्शियम से भरपूर डाइट हड्डियों के लिए बढ़िया होती है और इस तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी भी ताकतवर बनती है.

नियमित रुप से स्ट्रैच करें : यह अपनी पीठ को चोट रहित रखने का यह सबसे आसान और प्रभावी तरीका है. स्ट्रैचिंग से आपकी पीठ की मांसपेशियां ढीली रहती हैं. पीठ के दर्द को रोकने तथा इसका उपचार करने में स्ट्रैचिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है. पीठ, पेट तथा नितंबों की मांसपेशियों को सही अवस्था में रखने के लिए स्ट्रैचिंग बहुत सहायक सिद्ध होती है. स्ट्रैचिंग ताकतवर मांसपेशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशियां चोट लगने या सूजन के खतरे से बची रहती हैं.

सही प्रकार की कसरत करें: जब आप पीठ की चोट के कारण कसरत करना बंद कर देते हैं और अपनी मांसपेशियों की गतिविधियों को रोक देते हैं ऐसे में आपको अधिक पीड़ा होती है. शरीर के लिए सही प्रकार की कसरत बहुत महत्वपूर्ण है. शारीरिक गतिविधियों में लगे रहना बहुत जरूरी है. पीठ में आपकी मांसपेशियां बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह आपकी रीढ़ की हड्डी को तथा शरीर के पूरे ऊपरी हिस्से को सपोर्ट देती हैं. इन्हें ताकतवर बनाए जाने की आवश्यकता होती है ताकि ये सामान्य ढंग से कार्य करने में सक्षम हो सके.

सैर करना या दौड़ना : यह रीढ़ की हड्डी को तंदुरुस्त रखने का सबसे बढ़िया तरीका है. रोजाना ऐसा करने से रीढ़ की हड्डी की चोट से बचाव होता है. आपको लचक को पहल देनी चाहिए. योगा करने से तनाव कम होता है यह आपका पीठ दर्द से बचाव करता है. तनाव के कारण आपकी मांसपेशियां कठोर हो सकती हैं इसलिए पीठ के ऊपरी हिस्से में तनाव से खुद को राहत दिलाएं क्योंकि यह तनाव आपके लिए पीठ की चोट का खतरा पैदा कर सकता है.

धूम्रपान छोड़ें : अध्ययनों से यह पता चला है कि धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों में धूम्रपान न करने वालों के मुकाबले पीठ दर्द का खतरा अधिक रहता है क्योंकि निकोटीन रीढ़ की हड्डी की डिस्क्स में रक्त प्रवाह को बाधित करता है.

सपोर्ट के साथ ड्राइव करें: जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो इस बात को सुनिश्चित करें आप की सीट आरामदायक है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी पीठ को नुक्सान तो नहीं पहुंचा रहे हों. अधिकतर समस्याएं कार की सीट के साथ सही तरीके से एडजस्ट नहीं करने की वजह से होती है या ड्राइविंग के दौरान सिर को आगे रखने की वजह से पीठ की मांस पेशियों में खिंचाव होता है.

सूर्य की रोशनी से बचाव ठीक नहीं : यदि आप सूर्य की रोशनी से बचते हैं तो इसके दुष्प्रभावों का कोई अंत नहीं है. सूर्य की रोशनी में विटामिन में विटामिन डी बनता है. विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है. जो लोग सूर्य की रोशनी में कम जाते हैं उनमें पीठ संबंधी समस्याएं अधिक होती हैं. पीठ दर्द को कम करने के लिए विटामिन डी की मात्रा का अधिक सेवन करना वास्तव में बहुत सहायक होता है. ■

– चौथी दुनिया ब्यूरो

धार्मिक प्रभाव वाली इस्तक़लाल पार्टी ने संसदीय चुनावों के लिए पूर्ण रूप से पर्दानशीन महिलाओं को बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारा था यानि अगर उनकी उम्मीदवार संसद में जीतकर जातीं तो हर सेशन में नक़ाबपोश महिलाएं बैठतीं. इस्तक़लाल पार्टी भंग हो चुकी तहफ़ुज़ इंक़लाब लीग और इससे जुड़े इस्लामवादियों की पार्टी समझी जाती है.

मां के नाम रेहाना का खत

मेरी मौत के बाद मेरे अंग दान कर दिए जाएं

दुनिया भर की मानवाधिकार संस्थाओं की अपील के बावजूद ईरान में 26 वर्षीय रेहाना जब्बारी को देश के एक भूतपूर्व ख़ुफ़िया अधिकारी मुर्तजा अब्दुलअली सर्हिंदी के क़त्ल के जुर्म में 25 अक्टूबर की सुबह तेहरान स्थित जेल में सज़ा-ए-मौत दे दी गई. रेहाना की रिहाई की मुहिम में लगे लोगों का कहना था कि उससे क़त्ल का कुबूलनामा बहुत दबाव में लिया गया था और यह कि सर्हिंदी उसका बलात्कार करना चाहता था जिससे बचने के लिए उसने आत्मरक्षा में उसका क़त्ल किया था. वर्ष 2007 से सज़ा-ए-मौत के साये में जी रही रेहाना ने जेल की काल कोठरी से अपनी फांसी से कुछ माह पहले अपनी मां के नाम एक पत्र लिखा था. कहते हैं कि जब मौत सामने हो तो इंसान झूठ नहीं बोलता. यहां हम रेहाना का मार्मिक पत्र ह-ब-ह प्रकाशित कर रहे हैं जो न केवल ईरान के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करता है बल्कि पूरी दुनिया से सज़ा-ए-मौत को ख़त्म करने पर पुनर्विचार करने के लिए सवाल भी कर रहा है.

प्यारी शोलेह,

मुझे आज मालूम हुआ कि किसास (ईरानी दंड संहिता में प्रतिकार का क़ानून) का सामना करने की बारी मेरी है. मुझे दुःख है कि आपने मुझे यह बताने का मौक़ा क्यों नहीं दिया कि मैं अपने जीवन की किताब के आखिरी पन्ने पर पहुंच गई हूं. क्या आपको नहीं लगता कि यह मुझे जानना चाहिए था? आपको मालूम है कि मैं कितनी शर्मिंदा हूं कि आप उदास हैं? आप इस मौके पर मेरी तरफ से अपना और अब्बा का हाथ चूम क्यों नहीं लेतीं?

दुनिया ने मुझे 19 साल तक जिंदा रहने का मौक़ा दिया. दरअसल उस भयानक रात को मेरा क़त्ल होना चाहिए था. मेरी लाश को शहर के किसी कोने में फ़ेंक दिया जाना चाहिए था. जिसकी वजह से एक-दो दिन बाद किसी पुलिस अफसर ने मेरी शिनाख्त करने के लिए आपको अपने दफ्तर बुलाया होता, जहां आकर आपको यह भी पता चलता की मेरा बलात्कार हुआ है. कातिल का कभी सुराग नहीं लगता क्योंकि आपके पास न उतनी दौलत है और न ही ताक़त. उसके बाद आप दुःख और शर्मिंदगी के साथ अपनी ज़िन्दगी गुज़ारतीं और शायद कुछ साल बाद इस दुःख और पीड़ा की वजह से आप भी दुनिया से रुख़सत हो जातीं.

लेकिन बदकिस्मती से यह कहानी बदल गई. मेरी लाश को शहर किसी कोने में फेंकने के बजाय पहले एविन जेल के क़ैद-ए-तन्हाई की कब्र में डाल दिया गया, और अब शहर की क़ब्रनुमा जेल में. इसे आप अपनी किस्मत समझ कर सब्र कीजिये, क्योंकि आप तो ज़्यादा अच्छी तरह से जानतीं हैं कि मौत ज़िंदगी का खात्मा नहीं होती.

आप ने तो मुझे शिक्षा दी थी कि इंसान इस दुनिया में कुछ तजुर्बे हासिल करने और कुछ सीखने आता है, और हर जन्म के साथ उसको एक ज़िम्मेदारी दी जाती है. आपने मुझे यह भी सिखाया था कि कभी-कभी इंसान को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है. मुझे याद है जब आपने मुझे यह बताया था कि मुझे ले जाते समय गाड़ीवान ने मुझ पर कोड़े बरसाने वाले का विरोध किया था, लेकिन कोड़े मारने वाले ने उसके चेहरे और सिर पर कोड़े का वार किया. जिसकी वजह से गाड़ीवान की मौत हो गई. आप ने मुझे सिखाया था कि मर कर भी इंसानी मूल्यों का निर्माण करना चाहिए.

जब हम स्कूल जाते थे तो आप ने हमें सिखाया था कि झगड़े और शिकायत के दौरान भी भद्र महिला की तरह पेश आना चाहिए. आपको मालूम है कि आपकी शिक्षा ने हमारे व्यवहार को कितना प्रभावित किया था? आपके अनुभव ग़लत थे क्योंकि जब यह घटना घटित हुई तो मेरे अनुभव ने मेरा साथ छोड़ दिया. अदालत में मेरे मुक़दमे की सुनवाई के दौरान मुझे निर्मम हत्यारे और क्रूर अपराधी के रूप में पेश किया गया. मैंने कोई आंसू नहीं बहाया. मैंने रहम की भीख नहीं मांगी. रो-रो कर आसमान-ज़मीन एक नहीं किया क्योंकि मुझे क़ानून पर भरोसा था.

मुझ पर यह इल्जाम लगाया गया मैं जुर्म के समय मैंने शोर नहीं मचाया. आप जानती हैं कि मैंने आज तक एक मच्छर नहीं मारा, और तिलचट्टों को पकड़ कर उन्हें बाहर फ़ेंक दिया करती थी. अब मैं एक सुनियोजित कातिल बन गई हूं. जानवरों के साथ मेरे सुलूक की व्याख्या मेरे लड़का होने की ख्वाहिश के तौर पर की गई. जज ने इस हकीक़त को जानने की ज़हमत नहीं उठाई कि हादसे के वक़्त मेरे लम्बे नाख़ून पर पॉलिश लगी हुई थी.

वे कितने आशावादी थे जिन्हें ऐसे जजों से इंसाफ की उम्मीद थी! किसी जज ने इस इस बात पर सवाल नहीं उठाया कि बॉक्सिंग की महिला खिलाड़ी की तरह मेरे हाथ सख्त नहीं हैं. आपने मुझे इस देश से प्यार करना सिखाया, शायद इस देश को मेरी ज़रूरत ही नहीं थी. क्योंकि जब मुझ पर आरोपों के मुक्के बरसाए जा रहे थे और उन भद्दे और बेहूदा इल्जामों को सुन कर मैं रो रही थी तब मेरी मदद करने कोई नहीं आया. जब मैंने अपनी खूबसूरती की आखिरी निशानी अपने बालों को मुंडवा लिया तो मुझे 11 दिन क़ैद-ए-तन्हाई की सजा सुना दी गई.

प्यारी शोलेह, आप यह सुन कर रोइयेगा नहीं. हिरासत के पहले ही दिन पुलिस थाने में जब एक उम्रदराज़ अविवाहित एजेंट ने मेरे (लम्बे) नाखूनों के कारण मेरी पिटाई की थी तो मैं समझ गई थी दुनिया के इस क्षेत्र में खूबसूरती की कद्र नहीं है. यहां किसी को न चेहरे की खूबसूरती, न सोच की खूबसूरती, न लिखावट, न आंखों और नज़र की खूबसूरती और न ही मधुर आवाज़ की ज़रूरत है.

मेरी प्यारी मां, मेरी विचारधार बिलकुल बदल गई है और आप इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं. मेरी बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी. मैं अपनी लिखी हुई चीज़ें एक शख्स को दे दूंगी ताकि जब मुझे आपकी गैर मौजूदगी में और जानकारी के बिना मुझे फांसी दे दी जायेगी तो वह चीज़ें आप तक पहुंच जाएं. मैंने विरासत के तौर पर अपनी बहुत सारी हस्तलिखित चीज़ें छोड़ जाओगी.

बहरहाल, अपनी मौत से पहले मैं आप से कुछ मांगना चाहती हूं, जिसे आप को अपनी पूरी शक्ति लगा कर मेरे लिए किसी तरह करना होगा. हकीक़त में मैं आप से, इस देश से और पूरी दुनिया से केवल यही एक मांग है. मुझे मालूम है आपको इसे पूरा करने के लिए समय चाहिए. इसलिए अपनी वसीयत का एक हिस्सा पहले दे रही हूं. कृपया आप अपने आंसू पोंछ लें और मेरी बात सुनें. मैं चाहती हूं कि आप अदालत जाएं और मेरी ख्वाहिश उन्हें बताएं. मैं इस तरह का ख़त जेल से नहीं लिख सकती क्योंकि जेल प्रमुख इसकी इजाज़त नहीं देगा. इसलिए एक बार फिर आपको मेरी वजह से दुःख सहना पड़ेगा. इस काम के लिए अगर आप किसी के सामने हाथ भी फैलाएंगी तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, हालांकि मैंने अपनी जान बचाने के लिए किसी के सामने हाथ फ़ैलाने से आपको कई बार मना किया था.

मेरी मेहरबान मां, प्यारी शोलेह, आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अज़ीज़ हैं, मैं ज़मीन के अंदर सड़ना नहीं चाहती. मैं नहीं चाहती कि मेरी आंखें और मेरा जवान दिल यूं ही मिट्टी में मिल जाये. लिहाज़ा आप मेरी तरफ से गुज़ारिश कीजिये कि फांसी पर लटकाए जाने के तुरंत बाद मेरा दिल, गुर्दा, आंखें, हड्डियां और मेरे शरीर का हर वह अंग जो किसी के जिस्म में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है निकल लिया जाए और किसी ज़रूरत मंद को तोहफे में दे दिया जाए. मैं यह नहीं चाहती कि जिसे यह अंग दिए जाएं उसको मेरा या मेरी पहचान बताई जाए ताकि वह मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता खरीदे या मेरे लिए दुआ करे.

मैं अपने दिल की गहराईयों से यह बात कह रही हूं कि मैं अपने लिय कोई कब्र नहीं चाहती जहां आप आयें, मातम करें और दुःख उठाएं. मैं यह भी नहीं चाहती कि आप मेरे लिए काला (मातमी) लिबास पहने. आप कोशिश करके मेरे मुश्किल दिनों को भूल जाइये. मुझे हवाओं के हवाले कर दीजिये ताकि वह अपने साथ मुझे उड़ा ले जाए.

दुनिया को मुझसे प्यार नहीं है, क्योंकि दुनिया यह नहीं चाहती कि उसका भी वही हश्र हो जो मेरा हुआ था. अब मैं इसे छोड़ कर मौत को गले लगाने जा रही हूं. मैं अल्लाह की अदालत में इंस्पेक्टर शमलौ को कटघरे में खड़ा करूंगी, जज के ऊपर मुक़दमा दायर करूंगी और सुप्रीम कोर्ट के उन जजों का दामन पकडूंगी जिन्होंने मुझे जीते-जी मार डाला और मुझे तकलीफ पहुंचाने का कोई मौक़ा नहीं छोड़ा.

मैं खालिके काएनात की अदालत में डॉ फरवंदी का दामन भी पकडूंगी, मैं कासिम शाबानी पर मुक़दमा चलाउंगी और उन सबसे सवाल पुछूंगी जिन्होंने जानबुझ कर या अनजाने में मुझे कसूरवार साबित किया और मेरे अधिकारों को कुचल दिया, और इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कभी-कभी जो नज़र आता है वह हक़ीकत नहीं होता, बल्कि आंखों का धोखा होता है.

मेरी प्यारी रहमदिल शोलेह, आने वाली दुनिया में हम और आप अभियोक्ता होंगे और दूसरे अभियुक्त. देखते हैं अल्लाह क्या चाहता है. मैं आपको तब तक गले लगाए रखना चाहती हूं जब तक मेरा दम न निकल जाए. मैं आप से बहुत प्यार करती हूं.

रेहाना

01, अप्रैल, 2014 ■

feedback@chauthiduniya.com

ट्यूनीशिया संसदीय चुनाव परिणाम

अरब क्रांति का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है

हाल ही में ट्यूनीशिया में हुए चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अरब स्प्रिंग यहीं से आरंभ हुआ था. ट्यूनीशिया में अरब क्रांति के लगभग साढ़े तीन साल बाद नई संसद के चुनाव के लिए मतदान हुआ. राजधानी ट्यूनीश और दूसरे शहरों में मतदान केंद्रों पर मतदाता काफ़ी उत्साहित दिखे. हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कम रहा. कहा जाता है कि 1987 में जैनुल आबिदीन के राष्ट्र प्रमुख बनने के बाद युवाओं में राजनीतिक रुचि लगभग ख़त्म हो गई थी. वह इस तानाशाह शासक के कारण अपने और अपने देश के भविष्य को लेकर निराश हो चुके थे लेकिन अरब क्रांति के नतीजे में 2011 में इस तानाशाह को सरकार छोड़नी पड़ी और चुनाव हुए, जिसमें इस्लामवादी पार्टी अलनेहज़ा को अधिक सीटें मिलीं. उसने सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार का गठन किया. इसके बाद देश के क़ानूनों में कुछ संशोधन किए गए और यह तय किया गया कि देश का ढांचा धर्मनिर्पेक्षता पर आधारित होगा. इसी ढांचे को बुनियाद बनाकर 2014 के संसदीय चुनाव हुए. इसी संशोधन के तहत चुनाव प्रक्रिया में पुरुषों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व में संतुलन स्थापित किया गया और इन्हें संसद में समान प्रतिनिधित्व देने का भी प्रावधान किया गया.

चुनावों में अलनिदा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. अलनिदा का गठन 2013 में हुआ था और यह स्वतंत्र व धर्मनिरपेक्ष नेताओं के गठबंधन का समूह है. जिसमें ऐसे नेता भी शामिल हैं जो पूर्व राष्ट्रपति जैनुल आबिदीन के शासन का हिस्सा भी रहे हैं. दूसरी बड़ी पार्टी अलनेहज़ा है. यह इस्लामवादी पार्टी और जैनुलआबिदीन के बाद इसी पार्टी ने सत्ता संभाली थी लेकिन जल्द ही वहां के युवाओं ने इस्लामी व्यवस्था के बजाए धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था पर सरकार स्थापित करने की मांग करना शुरू कर दी थी, जिस कारण अलनेहज़ा को सरकार छोड़नी पड़ी थी.

इन चुनावों में जनता ने कुल 217 सीटों में से अलनिदा को 85, अलनेहज़ा को 69 सीटें दी हैं. इसके अलावा इंडीपेंडेंट नेशनल यूनियन को 16, पॉपुलर फ्रंट को 15, आफ़ाक़ ट्यूनिश पार्टी को 8 और अन्य को 24 सीटें मिली हैं. ट्यूनीशिया में कुल मतदाताओं की संख्या 5 मिलियन 285 हज़ार 136 है. आंकड़े बताते हैं कि अब ट्यूनीशिया के लोग धार्मिक कट्टरता से बाहर निकलकर महिलाओं को भी राष्ट्रीय विकास का हिस्सा बनाने के पक्ष में आने लगे हैं. यह संदेश हर इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां इस्लामी सत्ता के नाम पर महिलाओं को शैक्षणिक, राजनीतिक क्षेत्र में क़दम रखने से रोका जाता है. अरब देशों में ट्यूनीशिया एकमात्र ऐसा देश है जहां महिलाओं को हर जगह संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है और वे चुनावों में हिस्सा लेने के अलावा अन्य क्षेत्रों में पुरुषों के समान भागीदारी कर रही हैं.

ट्यूनीशिया के इस चुनाव से कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं. एक तो यह कि युवाओं में धार्मिक रुझान तो पाया जाता है लेकिन वह इसमें कट्टरता को पसंद नहीं करते हैं. यहां तक कि इस समय इनके सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या अर्थव्यवस्था की है. यही कारण है कि इस बार अधिकतर राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान आर्थिक सुधारों का ही नारा दिया था.

2014 के आम चुनावों में हिजाब पहनने वाली महिलाओं को चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं. धार्मिक प्रभाव वाली इस्तक़लाल पार्टी ने संसदीय चुनावों के लिए पूर्ण रूप से पर्दानशीन महिलाओं को बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारा था यानि अगर उनकी उम्मीदवार संसद में जीतकर जातीं तो हर सेशन में नक़ाबपोश महिलाएं बैठतीं. इस्तक़लाल पार्टी भंग हो चुकी तहफ़ुज़ इंक़लाब लीग और इससे जुड़े इस्लामवादियों की पार्टी समझी जाती है. इस्तकलाल के इस नज़रिए पर टिप्पणी करते हुए ट्यूनीशिया की सक्रिय महिला राजनीतिज्ञ रजाबिन सल्लामा कहती हैं कि अगर पार्लियामेंट में नक़ाबपोश महिलाएं बैठी होंगी तो दुनिया में क्या संदेश जाएगा. दुनिया हमारे देश को कट्टरपंथी कहना शुरू कर देगी. चुनाव परिणामों से यह बात सामने आ गई है कि जनता ने इस्तक़लाल जैसी पार्टियों को ख़ारिज कर दिया है. लिहाज़ा जिन 68 महिलाओं को जीत मिली है, उनमें से 35 अलनिदा से और 27 अलनेहज़ा से हैं और बाक़ी सीटें अन्य पार्टियों को मिली हैं.

चुनाव के बाद देश में धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था स्थापित होनी थी और महिलाओं को आबादी के अनुपात से प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी, इसलिए कहीं न कहीं यह संदेह था कि इस्लामवादी समूह बाधा डालने का प्रयास कर सकता है. इसीलिए मतदाताओं को सुरक्षा देने के लिए 80 हज़ार अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था की गई थी. इसके अलावा 500 विदेशी और 14 हज़ार देशी पर्यवेक्षक चुनावी गतिविधियों पर नज़र जमाए हुए थे. इस वजह से चुनाव बेहद शांतिपूर्ण हुए.

ट्यूनीशिया के इस चुनाव से कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं. एक तो यह कि युवाओं में धार्मिक रुझान तो पाया जाता है लेकिन वह इसमें कट्टरता को पसंद नहीं करते हैं. यहां तक कि इस समय इनके सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या अर्थव्यवस्था की है. यही कारण है कि इस बार अधिकतर राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान आर्थिक सुधारों का ही नारा दिया था. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अलनिदा के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होगा अपनी सहयोगी पार्टी के अपनी योजनाओं और स्कीमों से संतुष्ट रखना. वह इस पर अमल कर पाएगी या नहीं यह तो आने वाला समय ही बताएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

बड़े भाई! तुम मुझे पीठ पर बिठा लो और शिकारी कुत्तों से बचाओ. तुम तो एक दुलत्ती मारोगे तो कुत्ते भाग जाएंगे. घोड़े ने कहा–मुझे बैठना नहीं आता. मैं तो खड़े–खड़े ही सोता हूं. मेरी पीठ पर कैसे चढ़ोगे? मेरे पांव भी दुख रहे हैं. इन पर नई नाल चढ़ी हैं. मैं दुलत्ती कैसे मारूंगा? तुम कोई और उपाय करो. तब खरगोश ने गधे के पास जाकर कहा–मित्र गधे! तुम मुझे शिकारी कुत्तों से बचा लो. मुझे पीठ पर बिठा लो. जब कुत्ते आएं तो दुलत्ती झाड़कर उन्हें भगा देना. गधे ने कहा–मैं घर जा रहा हूं. समय हो गया है.

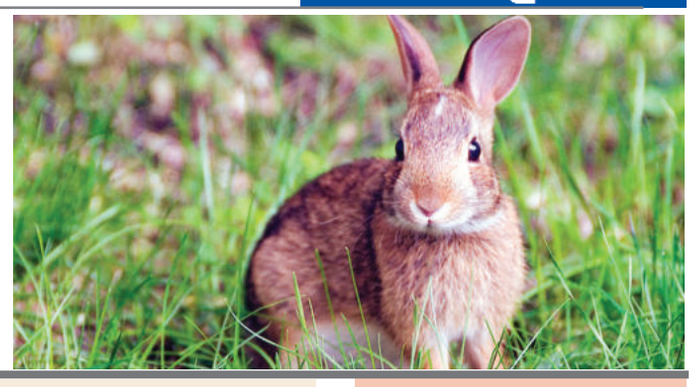

साई के दर से कोई खाली नहीं जाता

चौथी दुनिया ब्यूरो

साई बाबा की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि विश्व के वही एक मात्र आधार हैं. साई बाबा निश्चित ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी. साई बाबा भक्तों को हर संकट से बचाते हैं और सभी को कुशलता भवसागर से पार उतार देते हैं. आज विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है, जहां के लोग श्री शिरडी के साई बाबा के नाम से परिचित न हों. वह भारत के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के आध्यात्मिक विभूति थे. मान्यता है कि उनका जन्म लगभग 1838 ई. में महाराष्ट्र के पथरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उन्हें कुछ वर्ष तक एक मुस्लिम फकीर परिवार ने पाला था. उसके बाद साई शेलू गांव के एक ब्राह्मण संत गुरू वेंकुशा के आश्रम में 12 वर्ष तक रहे थे. 1854 ई में साई अपने गुरू के आदेश व आशीर्वाद से शिरडी गांव में चले गए थे. वहां लगभग दो माह तक एक युवक संत के रूप में रहने के बाद साई अचानक वहां से चले गए थे. तीन वर्ष बीतने के बाद 1858 में एक बारात के साथ बैलगाड़ी में बैठकर शिरडी आए थे और फिर वहीं बस गए थे. वहां साई ने एक त्यागी हुई पुरानी वीरान पड़ी मस्जिद को अपना स्थान बनाया और जो द्वारिका माई के नाम से प्रसिद्ध है. यह नाम साई के द्वारा ही दिया गया है. साई 60 वर्षों तक उसी मस्जिद में रहे थे और 80 वर्ष के आयु में साई ने शिरडी में ही अपना प्राण त्यागा था. साई ने किसी को भी अपने परिवार, जाति धर्म के बारे में नहीं बताया था, लेकिन कुछ प्रमाणों से माना जाता है कि वह एक ब्राहम्ण परिवार में जन्में थे. वे शिरडी में फकीर का एक सीधा–सादा जीवन व्यतीत करते थे. वह हमेशा अल्लाह मालिक है कहते रहते थे. साई मानवों व पशु–पक्षियों सभी को अपना प्रेम और सद्भाव देते थे. उनके पास संस्कृत. उर्दू, अरबी, मराठी, हिंदी, और तमिल भाषाओं की जानकारी थी. साई शिरडी गांव में केवल पांच परिवारों से ही रोज दिन में दो बार भिक्षा मांग कर लाते थे. जो भी भिक्षा में मिल जाता उसे द्वारिका माई में लाते थे और सभी को मिट्टी के बर्तन (परात) में सभी को मिलाकर रख देते थे. कुत्ते, बिल्लियां, चिड़ियां आकर उसका एक अंश आकर खा जाते थे, तब उसके बाद बचे भिक्षा को भक्तों के साथ मिल बांट कर खाते थे. साई के द्वारा द्वारिका माई में स्थापित की गई धुनी आज भी लगातार प्रज्ज्वलित हो रही है. साई अपने भक्तों को और वहा आने वाले आंगतुको को धुनी की भस्म(ऊदी) को आशीर्वाद के साथ दिया करते थे और उनके सभी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट दूर हो जाते थे और वे त्रिकोलदर्शी थे. लोगो के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जानते थे, पशु–पक्षियों वअन्य प्रणियों के पूर्व जन्मों के बारे में उन्हें पूर्ण जानकारी होती थी. साई ने जिसको आशीर्वाद दे दिया, वह हमेशा ही प्रसन्न होकर रहता था. साई ने कई अत्यंत रोमांचकारी चमत्कार किए थे, उन्होंने केवल स्वाभाविक रूप से करूणावश चमत्कार किया था दिखाने के लिए नहीं जैसा कि आज कल कई संत करते हैं. साई के चमत्कारों तथा भक्तों पर अनुग्रह की ख्याति धीरे–धीरे भारत समेत पूरे विश्व में फैल गई. उन्हें विश्व गुरू स्वीकार किया गया है. साई के शिरडी में रहते समय साठ वर्षों के दौरान हजारों दुखी भक्त और याचक उनकी कृपा पाने के लिए आए थे और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी. महाराष्ट्र के एक महान भक्त श्री दामोलक हेमाडयंत ने साई से प्राथना की थी कि वे उनके दिव्य जीवन, चमत्कारों और उपदेशों पर एक ग्रंथ लिखने की अनुमति दे दें. साई ने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा था कि जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा. उसकी भक्ति में दिनों–दिन बृद्धि होगी. जो मेरे चरित्र और कार्यों का श्रद्धापूर्वक गायन करेगा, उसकी मैं हर प्रकार से सहायता करूंगा. साई कहते हैं, जो भक्त उनको हृदय और प्राणों से चाहेगा. वे सदैव प्रसन्न रहेगें. साई की लीलाओं का जो कीर्तन करेगा, उसे परमानंद और चिर–संतोष की उपलब्धि हो जाएगी. साई कहते हैं यह मेरा वैशिष्ठय है कि जो कोई अनन्य भाव से ही मेरी शरण आता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरा निरन्तर पूजन, स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है. उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूं. साई कहते हैं मेरी कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनों, मनन करो. सुख और शांति प्राप्ति का सरल मार्ग यही है. केवल साई के उच्चारण मात्र से भक्तों के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें तीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

वार,छोड़ न यार

इसे महज संयोग ही नहीं कहा जा सकता कि जब सीमा पर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से लड़ रह रहे थे, उसी समय शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हीं दोनों देशों को दिया गया. भारत के कैलाश सत्यार्थी एंव पाकिस्तान की मलाला युसुफजई को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना कहीं न कहीं यही साबित करता है कि अन्तरराष्ट्रीय बिरादरी भी चाहती है कि एशिया के ये दो महत्वपूर्ण देश शांति के साथ रहे और पूरे विश्व को शांति एवं अमन का संदेश देते रहे.

–संजय कुमार, समस्तीपुर,बिहार.

छवि सुधारनी होगी

जब तोप मुकाबिल हो–अखिलेश यादव के तीन घंटे (03 नवंबर–09 नवंबर 2014) पढ़ा काफी तथ्यपरक है. संतोष भारतीय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ अपने लोहिया ग्राम के दौरे का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव की इमानदारी की बात कही है. यह बिल्कुल सही है कि अखिलेश यादव प्रदेश में इमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं और उनकी इमानदारी पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते. यह नहीं कहा जा सकता कि अखिलेश सरकार कार्य नहीं कर रही है, लेकिन सभी सरकारों में कुछ कामचोर लोग होते हैं, वैसे ही अखिलेश सरकार में भी हैं. अखिलेश सरकार को प्रशासन और अपने मंत्रियों पर नियंत्रण करना होगा और उनके कार्यो की समीक्षा करनी चाहिए, जिससे प्रदेश के लोगों में अखिलेश यादव की एक अच्छी छवि बन सके.

–प्रमोद श्रीवास्तव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

कैसे आएगा कालाधन

आलेख–कालाधन लाने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत है, नेताओं की नहीं(03 नवंबर–09 नवंबर 2014)पढ़ा काफी विचारोत्तेजक है. कमल मोरारका ने बिल्कुल सही कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लोगों को बताना चाहिए कि वह कालाधन रखने वालों के खिलाफ क्या आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं. मोदी ने लोकसभा चुनाव दौरान कहा था कि वो विदेशों में बैंकों में जमा कालाधन देश में लाएंगे और कालाधन आया तो हर गरीब के जेब में 15–20 लाख रुपये होंगे. प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में यह तो जरूर लोगों को विश्वास दिलाया कि कालाधन का पाई–पाई लाएंगे, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि कालाधन कितना है यह पता नहीं है. कालाधन लाने के लिए सरकार को विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए कि कैसे कालाधन को देश में आ सकता है.

–वशिष्ठ नारायण तिवारी, यमुना विहार, दिल्ली.

सबके लिए समान अधिकार हो

श्री संतोष भारतीय
नई दिल्ली

मैं चौथी दुनिया समाचार पत्र के नए अंक में नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रकाशित आपकी संपादकीय की सराहना करता हूं. देश के विकास को बाजार के हवाले कर दिया गया है, जिससे लोगों की बुनियादी जरूरतों का पूरा होना बहुत ही कठिन हो जाएगा और इसके कारण अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बीच आर्थिक असमानता बढ़ेगी. दरअसल देश में उच्च वर्ग देश की जनसंख्या का 0.1 प्रतिशत हैं, लेकिन मोटे तौर पर तकरीबन 60 प्रतिशत पूंजी और संसाधनों को नियंत्रित करता है. तथाकथित मध्यम वर्ग देश की जनसंख्या का तकरीबन 3 प्रतिशत है. धीरे-धीरे करके मोदी उच्च वर्ग, जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर और अभिजात वर्ग शामिल हैं, के संरक्षक बनते जा रहे हैं. मैं नरेंद्र मोदी की परख संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके द्वारा दिए भाषणों के आधार पर नहीं करता, बल्कि उनके सत्ता संभालने के बाद उनके द्वारा किए गए कार्यों और घोषणाओं के आधार पर करता हूं. अभी हाल में जो देखने में आया है आप उससे भली भांति वाकिफ हैं कि उन्होंने कालाधन रखने वालों का किस तरह बचाव किया. वास्तव में नरेंद्र मोदी जो क्रोनी कैपेटलिज्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन मैं आपके इस विचार से असहमत हूं कि एक समय ऐसा आएगा जब देशवासी न केवल मोदी की पूंजीपतियों और उच्चवर्ग के लिए बनाई जा रही नीतियों के विरोध में न केवल धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे, बल्कि विद्रोह करेंगे. ■

–सैय्यद शहाबुद्दीन, ई–मेल के द्वारा.

कांग्रेस का सच

कवर स्टोरी–राम मंदिर विवाद कांग्रेस ने पैदा किया–2, मुर्ति किसने रखी किसने रखवाई (03 नवंबर–09 नवंबर 2014) पढ़ा तथ्यपरक आलेख है. शीतला सिंह के आलेख से कई ऐसी जानकारियां सबके सामने आई हैं, जो देश में कम ही लोगों को पता होगी. मैंने इससे पहले चौथी दुनिया में प्रकाशित कवर स्टोरी राम मंदिर विवाद कांग्रेस ने पैदा किया वह भी पढ़ा था, उस आलेख जो कुछ जानकारी नहीं मिल पाई थी, वह जानकारी शीतला सिंह के इस आलेख से सबके सामने आ गई. बाबरी मस्जिद परिसर में मुर्ति रखने से बाबरी विध्वंस तक कई दृश्य देखने को मिले, जो दिखा उसी को लोगों ने सच्चाई मान ली, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और थी, जो इस आलेख से पूरे देश के सामने आई है कि पर्दे के पीछे से कांग्रेस खेल खेलती रही. इस आलेख को पढ़कर साफ हो जाता है इन सबके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है.

–रमाशंकर सिंह, दरभंगा, बिहार.

निर्भीक समाचार–पत्र

चौथी दुनिया एक निडर एवं तथ्यों पर आधारित समाचार–पत्र है, जो आज के दौर में भी मिशन वाली पत्रकारिता कर रहा है. इसमें प्रकाशित सभी आलेख तथ्यों पर आधारित होते हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद नई–नई जानकारियां हासिल होती हैं. संतोष भारतीय द्वारा लिखा गया तोप मुकाबिल पढ़कर काफी अच्छा लगता है. इसमें कवर स्टोरी से लेकर सियासी दुनिया, विविध दुनिया, बाकी दुनिया, साहित्य दुनिया, साई महिमा और जगमग दुनिया यानी सभी पृष्ठों पर प्रकाशित सामग्री काफी अच्छी होती है. आशा है कि चौथी दुनिया में आगे भी ऐसी ही सामग्री पढ़ने को मिलती रहेगी. ■

–पुर्णिमा मिश्रा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

दोस्ती की पहचान

एक जंगल में गाय, घोड़ा, गधा और बकरी चरने आते थे. उन चारों में मित्रता हो गई. वे चरते–चरते आपस में कहानियां कहा करते थे. पेड़ के नीचे एक खरगोश का घर था. एक दिन उसने उन चारों की मित्रता देखी. खरगोश पास जाकर कहने लगा–तुम लोग मुझे भी मित्र बना लो. उन्होंने कहा–अच्छा. तब खरगोश बहुत प्रसन्न हुआ. खरगोश हर रोज उनके पास आकर बैठ जाता. एक दिन खरगोश उनके पास बैठा कहानियां सुन रहा था. अचानक शिकारी कुत्तों की आवाज सुनाई दी. खरगोश ने गाय से कहा–तुम मुझे पीठ पर बिठा लो. जब शिकारी कुत्ते आएं तो उन्हें सींगों से मारकर भगा देना.

गाय ने कहा–मेरा तो अब घर जाने का समय हो गया है. तब खरगोश घोड़े के पास गया.

कहने लगा–बड़े भाई! तुम मुझे पीठ पर बिठा लो और शिकारी कुत्तों से

बचाओ. तुम तो एक दुलत्ती मारोगे तो कुत्ते भाग जाएंगे.

घोड़े ने कहा–मुझे बैठना नहीं आता. मैं तो खड़े–खड़े ही सोता हूं. मेरी पीठ पर कैसे चढ़ोगे? मेरे पांव भी दुख रहे हैं. इन पर नई नाल चढ़ी हैं. मैं दुलत्ती कैसे मारूंगा? तुम कोई और उपाय करो. तब खरगोश ने गधे के पास जाकर कहा–मित्र गधे! तुम मुझे शिकारी कुत्तों से बचा लो. मुझे पीठ पर बिठा लो. जब कुत्ते आएं तो दुलत्ती झाड़कर उन्हें भगा देना.

गधे ने कहा–मैं घर जा रहा हूं. समय हो गया है. अगर मैं समय पर न लौटा, तो कुम्हार डंडे मार–मार कर मेरा कचूमर निकाल देगा. तब खरगोश बकरी की तरफ चला.

बकरी ने दूर से ही कहा–छोटे भैया! इधर मत आना. मुझे शिकारी कुत्तों से बहुत डर लगता है. कहीं तुम्हारे साथ मैं भी न मारी जाऊं. इतने में कुत्ते पास आ गए. खरगोश सिर पर पांव रखकर भागा. कुत्ते इतनी तेज दौड़ न सके. खरगोश झाड़ी में जाकर छिप गया.

वह मन में कहने लगा–हमेशा अपने पर ही भरोसा करना चाहिए .

शिक्षा–दोस्ती की परख मुसीबत में ही होती है.

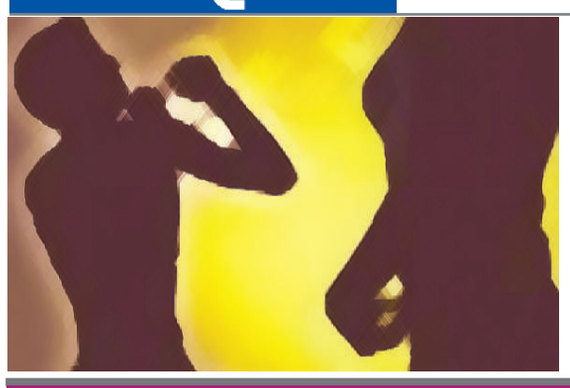

शादी का मसला पेश हुआ. नागपुर के करोड़पति सेठ मक्खन लाल बहुत लहराए हुए थे. उनकी लड़की से शादी हो गई. मक्खन लाल का उसी शादी में दीवाला निकल गया. इस वक्त मगन दास से ज़्यादा ईर्ष्या योग्य आदमी और कौन होगा? उसकी ज़िंदगी की बहार उमंगों पर थी. मुरादों के फूल अपनी शबनमी ताजगी में खिल-खिलकर हुस्न और ताजगी का समां दिखा रहे थे.

साहित्यकार का अकेलापन

अनंत विजय

दिल्ली स्थित हिंदी भवन का सभागार. तिथि 28 अक्टूबर, 2014. वक्त शाम के क़रीब साढ़े सात बजे. मौक़ा हिंदी के मशहूर साहित्यकार राजेंद्र यादव की पहली पुण्यतिथि पर स्मरण आयोजन. कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद तमाम साहित्य प्रेमी बाहर लॉबी में एक-दूसरे से बातें कर रहे थे. वहीं नामवर जी भी खड़े थे और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आशीर्वाद दे रहे थे. कुछ साहित्य प्रेमी नामवर जी के साथ सेल्फी ले रहे थे, तो कुछ लोग उन्हें किसी कार्यक्रम आदि में आने का निमंत्रण दे रहे थे. किसी बात पर अचानक नामवर जी ने कहा कि इस वक्त उनसे ज़्यादा अकेला कौन है? नामवर जी ने पता नहीं, किस रौ में यह बात कही. उनके इस कथन से मेरे ज़ेहन में पूरे हिंदी साहित्य के अस्सी पार लेखकों का अकेलापन और उसका दंश एक झटके में कौंध गया. नामवर जी ने जब अकेलेपन की बात की, तो साहित्यिक पत्रिका पाखी के युवा संपादक की नई किताब हाशिए पर हर्फ का एक लेख स्मरण हो आया. अपनी इस नई किताब में प्रेम भारद्वाज ने आलोचक के अकेलेपन के बहाने नामवर जी के व्यक्तित्व की गांठें खोलने की कोशिश की है.

अपने उस लेख में प्रेम भारद्वाज ने नीत्से को उद्धृत करके कहा है कि आदमी अंतत: अकेला होता है. उसी लेख में प्रेम भारद्वाज ने नामवर सिंह का एक भाषण उद्धृत किया है. आलोचना का भविष्य विषय पर बोलते हुए उक्त भाषण की शुरुआत नामवर सिंह ने अज्ञेय की कविता से की थी-एक तनी हुई रस्सी है/ जिस पर मैं नाचता हूं/ मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूं/ कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूं/ कि तनाव चूके ढीले, मुझे छुट्टी हो जाए/ पर तनाव ढीलता नहीं/ और इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता/ पर तनाव वैसे ही बना रहता है/ सब कुछ वैसा ही बना रहता है/ और मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं/मुझे नहीं. रस्सी को नहीं/ खंभे को नहीं/ रोशनी को नहीं/ तनाव को नहीं/ देखते हैं नाच. अज्ञेय की इस कविता के बहाने नामवर जी ने अपना दर्द तो सामने रखा ही, अपनी पूरी पीढ़ी के दंश को संकेतों में उजागर कर दिया.

नामवर सिंह हिंदी के वह हीरामन हैं, जिनके आसपास भी इस वक्त कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है. उम्र के इस पड़ाव पर काल से होड़ लेती हिंदी आलोचना की यह शिखर शख्सियत बिल्कुल अकेली है और अकेलेपन का दंश झेलते हुए भी स्वयं को साहित्य की सेवा में होम कर रही है. नामवर जी दिल्ली में अकेले रहते हैं और उनके सबसे बड़े साथी किताबें एवं पत्र-पत्रिकाएं हैं. नामवर जी ने कभी कहा था कि मामला मरजाद का है, इसलिए मुंह नहीं खोल सकता. हमें नामवर जी के उस मरजाद का सम्मान करना चाहिए, लेकिन हम वृहद हिंदी समाज की कृतघ्नता पर तो सवाल खड़े कर ही सकते हैं. नामवर

जी के न लिखने पर सवाल खड़े करने वालों को नामवर जी के योगदान का न तो अंदाज़ा है और न उनके कामों का ज्ञान. जिस तरह लगभग दो दशकों से नामवर जी अपने भाषणों से नई पीढ़ी को हिंदी में संस्कारित कर रहे हैं, वह अद्वितीय है. नामवर जी आज हिंदी की धरोहर हैं, उन्हें संभाल कर रखने की ज़िम्मेदारी पूरे हिंदी जगत की है. दिल्ली में रहते हुए भी अगर आज हिंदी का सबसे बड़ा आदमी अपने अकेलेपन की बात करता है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है.

दरअसल, अगर हम हिंदी के साहित्य समाज को देखें, तो उसमें वरिष्ठ लेखकों के प्रति एक उपेक्षा का भाव दिखाई देता है, खासकर महानगर में रहने वाले साहित्यकार महानगरीय व्यस्तता के बहाने वरिष्ठ लेखकों की उपेक्षा कर जाते हैं. यह हमारे समाज के पश्चिमीकरण होने का एक संकेत है, जहां संबंधों की गर्माहट या उष्मा स्वार्थ या डॉलर की गर्माहट से तय होती है. हिंदी समाज हमेशा से संयुक्त परिवार की तरह रहा है, जहां हम अपने बुजुर्गों का न केवल सम्मान करते हैं, बल्कि उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं, मौक़े-बेमौक़े उनसे सलाह-मशविरा भी लेते रहते हैं. हिंदी साहित्य का जो हमारा महानगरीय समाज है, वह अपने वरिष्ठ एवं बुजुर्ग लेखकों को अकेलेपन के बियावान में छोड़ देता है. एक बार राजेंद्र यादव से मैंने पूछा था कि उन्हें कभी अकेलापन नहीं लगता है? जोरदार ठहाके के बाद उन्होंने कहा था, मैं तो हर रोज अकेलेपन से होड़ लेता रहता हूं. उनके ठहाके के पीछे के अकेलेपन को उस वक्त मैंने महसूस किया था.

अकेलेपन से उसी होड़ का नतीजा था कि यादव जी ने अपने आपको युवाओं से जोड़ लिया था. अकेलेपन की उसी होड़ की वजह से वह काल से होड़ लेने लगे. उन्होंने युवाओं में अपने आपको इतना रमाना शुरू कर दिया कि वह गाहे-बगाहे विवाद की वजह बनने लगे. अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक वह विवादित बने रहकर अकेलेपन को परास्त करते रहे. अकेलेपन से होड़ लेने की जिद में वह काल से होड़ नहीं ले पाए. अगर हम मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें, तो अकेलापन एक बहुत ही जटिल मानसिक स्थिति है. मनोविज्ञान के मुताबिक, अकेलेपन का दंश भीड़ में रहने के बावजूद महसूस किया जा सकता है. ऐसा भी नहीं है कि जो शख्स सफलता की बुलंदियां हासिल कर लेता है, वह अकेलेपन का शिकार नहीं होता है. शिखर पर पहुंचने वाला और दुनिया के तमाम सुख-सुविधाओं का उपभोग करने वाला भी अकेला हो सकता है. इस अकेलेपन में अगर अपने समाज की उपेक्षा भी शामिल हो जाए, तो फिर वह घातक हो सकती है. मनोविज्ञान के अलग-अलग शोधों में यह नतीजा निकला है कि एक खास प्रकार के समूह में रहते हुए भी अगर कोई व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, तो इस बात की संभावना रहती है कि उस समूह के अन्य सदस्य भी उसका शिकार हो जाएं. इस तरह उसके फैलने की आशंका ज़्यादा रहती है.

नामवर सिंह हिंदी के वह हीरामन हैं, जिनके आसपास भी इस वक्त कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है. उम्र के इस पड़ाव पर काल से होड़ लेती हिंदी आलोचना की यह शिखर शख्सियत बिल्कुल अकेली है और अकेलेपन का दंश झेलते हुए भी स्वयं को साहित्य की सेवा में होम कर रही है. नामवर जी दिल्ली में अकेले रहते हैं और उनके सबसे बड़े साथी किताबें एवं पत्र-पत्रिकाएं हैं.

यह सिर्फ़ नामवर सिंह या राजेंद्र यादव का नहीं, बल्कि अस्सी पार लेखकों के पूरे समूह का मामला है, चाहे वे दिल्ली में रह रहे हों या देश के अलग-अलग शहरों में. आज अगर हम हिंदी साहित्य जगत को देखें, तो सिर्फ़ दिल्ली में अस्सी पार के बारह-चौदह लोग इस वक्त हैं. यह दिल्ली के हिंदी समाज के लिए गौरव की बात है कि एक साथ इतने वरिष्ठ लोगों का सानिध्य उसे हासिल है. केदारनाथ सिंह, रामदरश मिश्र, गोपाल राय एवं द्रोणवीर कोहली जैसे तमाम लेखक दिल्ली और आसपास रहते हैं, लेकिन नई पीढ़ी में उन्हें लेकर उत्साह नहीं, बल्कि उपेक्षा का भाव दिखाई देता है. ऐसे वरिष्ठ साहित्यकारों से सीखने की बजाय कुछ नए लेखक उन पर कीचड़ उछाल कर अपनी प्रसिद्धि का रास्ता तलाश रहे हैं. बड़े साहित्यकारों की आलोचना या उन पर साहित्यिक हमले करके मशहूर होने की ललक हाल में थोड़ी कम हुई है. राजेंद्र यादव की पहली पुण्यतिथि पर हुए इस आयोजन में तीस-पैंतीस लोगों का जुटना वरिष्ठ लेखकों के प्रति साहित्य समाज की उपेक्षा का सूचक है. नामवर सिंह ने इस ओर इशारा भी किया. उन्होंने उपस्थित लोगों को राजेंद्र यादव से सच्चा प्यार करने वाला करार दिया, तो कम उपस्थिति पर हैरानी भी जताई. हमें अपने बुजुर्ग साहित्यकारों को क़दम-क़दम पर यह एहसास कराना होगा कि वे हमारे लिए अहम हैं.

हम हिंदी के नए पाठक तैयार करने के लिए अपने बुजुर्ग लेखकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी कोई पहल दिखाई नहीं देती है. कोई ऐसा आयोजन नहीं होता, जहां वरिष्ठ लेखकों के अनुभवों से नई पीढ़ी को लाभ मिल सके. साहित्य समाज उनका उपयोग नहीं कर पा रहा है. वे अपने घर में रहते हैं और वहीं साहित्य को ओढ़ते-बिछाते अकेलेपन से संघर्ष करते रहते हैं. अस्सी पार लेखकों के अलावा दिल्ली में इस वक्त सत्तर-अस्सी के बीच भी दर्जन भर लेखक हैं. उनसे भी नई पीढ़ी को साहित्य में दीक्षित कराने का काम किया जा सकता है. इस वय के धवलकेशी साहित्यकारों में अशोक वाजपेयी एवं गंगा प्रसाद विमल ने कार्यक्रमों आदि में अपनी भागीदारी से खुद को प्रासंगिक बना रखा है, लेकिन यह इन दोनों का व्यक्तिगत प्रयास है. आज अब ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बुजुर्ग साहित्यकारों को सम्मान देने के अलावा उनका साथ भी दें. उन्हें हम अपने कार्यों में सहभागी बनाएं और अकेलेपन के जबड़े से बाहर निकालने का श्रम करें. सरकारी संस्थाओं एवं मृतप्राय: लेखक संगठनों से यह अपेक्षा करना व्यर्थ है. साहित्य अकादमी जैसी संस्थाएं इस दिशा में निजी संस्थाओं को जोड़कर सार्थक पहल कर सकती हैं. अगर ऐसा हो पाता है, तो हम हिंदी का एक नया समाज गढ़ सकेंगे. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

कहानी

त्रिया चरित्र

प्रेमचंद

सेठ लगन दास जी के जीवन की बगिया फलहीन थी. कोई ऐसा मानवीय, आध्यात्मिक या चिकित्सात्मक प्रयत्न न था, जो उन्होंने न किया हो. यूं शादी में एक पत्नी-व्रत के कायल थे, मगर ज़रूरत और आग्रह से विवश होकर एक-दो नहीं, पांच शादियां कीं. यहां तक कि उम्र के चालीस साल गुज़र गए और अंधेरे घर में उजाला न हुआ. बेचारे बहुत रंजीदा रहते. यह धन-संपत्ति, ठाट-बाट, वैभव और ऐश्वर्य क्या होंगे. मेरे बाद इनका क्या होगा, कौन भोगेगा, यह ख्याल बहुत अफ़सोसनाक था. आख़िर यह सलाह हुई कि किसी लड़के को गोद लेना चाहिए. मगर यह मसला पारिवारिक झगड़ों के कारण सालों तक स्थगित रहा. जब सेठ जी ने देखा कि बीवियों में अब तक बदस्तूर कशमकश हो रही है, तो उन्होंने नैतिक साहस से काम लिया और होनहार अनाथ लड़के को गोद ले लिया. उसका नाम रखा गया मगनदास. उसकी उम्र पांच-छह साल से ज़्यादा न थी. बला का जहीन और तमीजदार. मगर औरतें सब कुछ कर सकती हैं, दूसरे के बच्चे को अपना नहीं समझ सकतीं. यहां तो पांच औरतों का साझा था. अगर एक उसे प्यार करती, तो बाकी चार औरतों का फर्ज था कि उससे नफरत करें. हां, सेठ जी उसके साथ बिल्कुल अपने लड़के-सी मुहब्बत करते थे. पढ़ाने को मास्टर रखे, सवारी के लिए घोड़े. रईसी ख्याल के आदमी थे. राग-रंग का सामान भी मुहैया था. गाना सीखने का लड़के ने शौक किया, तो उसका भी इंतजाम हो गया. गरज जब मगन दास जवानी पर पहुंचा, तो रईसाना दिलचस्पियों में उसे कमाल हासिल था. उसका गाना सुनकर उस्ताद लोग कानों पर हाथ रखते. शहसवार ऐसा कि दौड़ते हुए घोड़े पर सवार हो जाता. डील-डौल, शक्ल-सूरत में उसका-सा अलबेला जवान दिल्ली में कम होगा.

शादी का मसला पेश हुआ. नागपुर के करोड़पति सेठ मक्खन लाल बहुत लहराए हुए थे. उनकी लड़की से शादी हो गई. मक्खन लाल का उसी शादी में दीवाला निकल गया. इस वक्त मगन दास से ज़्यादा ईर्ष्या योग्य आदमी और कौन होगा? उसकी ज़िंदगी की बहार उमंगों पर थी. मुरादों के फूल अपनी शबनमी ताजगी में खिल-खिलकर हुस्न और ताजगी का समां दिखा रहे थे. मगर तकदीर की देवी कुछ और कोशिश कर रही थी. वह सैर-सपाटे

के इरादे से जापान गया हुआ था कि दिल्ली से ख़बर आई, ईश्वर ने तुम्हें एक भाई दिया है. मुझे इतनी खुशी है कि शायद ज़्यादा अर्से तक ज़िंदा न रह सकूं. तुम बहुत जल्द लौट आओ. मगन दास के हाथ से तार का कागज छूट गया और सिर में ऐसा चक्कर आया, जैसे किसी ऊंचाई से गिर पड़ा हो.

मगन दास का किताबी ज्ञान बहुत कम था, मगर स्वभाव की सज्जनता से वह खाली हाथ न था. हाथों की उदारता ने, जो समृद्धि का वरदान है, हृदय को भी उदार बना दिया था. उसे घटनाओं की इस काया पलट से दु:ख तो ज़रूर हुआ, आख़िर इंसान ही था, मगर उसने धीरज से काम लिया और एक आशा व भय की मिली-जुली हालत में स्वदेश रवाना हुआ. रात का वक्त था. जब अपने दरवाजे पर पहुंचा, तो नाच-गाने की महफिल सजी देखी. उसके क़दम आगे न बढ़े, वह लौट पड़ा और एक दुकान के चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए. इतना तो उसे यकीन था कि सेठ जी उसके साथ भी भलमनसी और मुहब्बत से पेश आएंगे, बल्कि शायद अब और भी कृपा करने लगें. सेठानियां भी अब उसके साथ ग़ैरों-सा बर्ताव न करेंगी. मुमकिन है, मझली बहू, जो इस बच्चे की खुशनसीब मां थीं, उससे दूर-दूर रहें, मगर बाकी चारों सेठानियों की तरफ़ से सेवा-सत्कार में कोई शक नहीं था. उनकी डाह से वह फ़ायदा उठा सकता था. तो भी उसके स्वाभिमान ने गवारा न किया कि जिस घर में वह मालिक की हैसियत से रहता था, उसी घर में अब एक आश्रित की हैसियत से ज़िंदगी बसर करे. उसने फ़ैसला कर लिया कि अब यहां रहना न मुनासिब है, न मसलहत. मगर जाऊं कहां? न कोई ऐसा फन सीखा, न कोई ऐसा इल्म हासिल किया, जिससे रोजी कमाने की सूरत पैदा होती. रईसाना दिलचस्पियां उसी वक्त तक कद्र की निगाह से देखी जाती हैं, जब तक वे रईसों के आभूषण रहें. जीविका बन कर वे सम्मान के पद से गिर जाती हैं.

अपनी रोजी हासिल करना तो उसके लिए कोई मुश्किल काम न था. किसी सेठ-साहूकार के यहां मुनीम बन सकता था, किसी कारखाने का एजेंट हो सकता था, मगर उसके कंधे पर एक भारी जुआ रखा हुआ था, उसे क्या करे. एक बड़े सेठ की लड़की, जिसने लाड़-प्यार में परवरिश पाई, उससे यह कंगाली की तकलीफें क्यों झेली जाएंगी. क्या मक्खन लाल की लाड़ली बेटी एक ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद करेगी, जिसे रात की रोटी का भी ठिकाना नहीं! मगर इस फिक्र में अपनी जान क्यों खपाऊं. मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की. मैं बराबर इंकार करता रहा. सेठ जी ने जबरदस्ती मेरे पैरों में बेड़ी डाली है. अब वही इसके ज़िम्मेदार हैं. मुझसे कोई वास्ता नहीं. लेकिन, जब उसने दोबारा ठंडे दिल से इस मसले पर ग़ौर किया, तो बचाव की कोई सूरत नज़र न आई.

आख़िकार उसने यह फ़ैसला किया कि पहले नागपुर चलूं, जरा उन महारानी के तौर-तरीके देखूं, बाहर-ही-बाहर उनके स्वभाव-मिजाज की जाच करूं. उस वक्त तय करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए. अगर रईसी की बू उनके दिमाग से निकल गई है और मेरे साथ रूखी रोटियां खाना उन्हें मंजूर है, तो इससे अच्छा फिर और क्या. लेकिन, अगर वह अमीरी ठाट-बाट के हाथों बिकी हुई हैं, तो मेरे लिए रास्ता साफ़ है. फिर मैं हूं और दुनिया का गम. ऐसी जगह जाऊं, जहां किसी परिचित की सूरत सपने में भी न दिखाई दे. ग़रीबी की जिल्लत नहीं रहती, अगर अजनबियों में ज़िंदगी बसर की जाए. यह जानने-पहचानने वालों की कनखियां और कनबतियां हैं, जो ग़रीबी को यंत्रणा बना देती हैं. इस तरह दिल में ज़िंदगी का नक्शा बनाकर मगन दास अपनी मर्दाना हिम्मत के भरोसे नागपुर की तरफ़ चला. उस मल्लाह की तरह, जो किश्ती और पाल के बगैर नदी की उमड़ती-घुमड़ती लहरों में स्वयं को डाल दे. ■

...क्रमश:

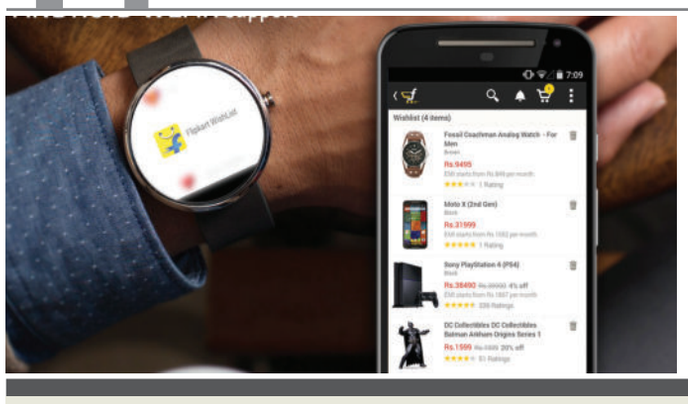

> इस नई ऐप से यूजर्स अपने स्मार्ट बैंड या स्मार्टवॉच पर फ्लिपकार्ट की नोटिफिकेशन देख सकेंगे. कंपनी का कहना है कि भविष्य में इस ऐप में अनगिनत फीचर्स जोड़े जा सकेंगे जिनमें से एक होगा ग्राहक द्वारा स्मार्टवॉच की मदद से ही अपने फ्लिपकार्ट ऑर्डर को ट्रैक कर पाना.

माइक्रोसॉफ्ट की पहली वियरेबल डिवाइस

माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला वियरेबल गैजेट लॉन्च किया है. माइक्रोसॉफ्ट बैंड एक फिटनेस डिवाइस है जिसे यूजर्स की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बनाया गया है. ये फिटनेस बैंड 19 एमएम चौड़ा है और 8.7एमएम पतला. इसकी स्क्रीन 11गुणा33एमएम की है. स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो 64एमबी इंटरनल स्टोरेज के साथ इस डिवाइस में आरएम कोर्टेक्स एम4 एमसीयू प्रोसेसर दिया गया है. इस बैंड में 10 सेंसर दिए गए हैं. इनमें हार्ट रेट सेंसर, 3 एक्सिस एक्सिलोमीटर, जीपीएस, एम्बिएंट लाइट सेंसर, स्किन टेम्प्रेचर सेंसर. यूवी सेंसर, कैपेसिटि सेंसर, माइक्रोफोन और गैलवेनिक स्किन रिस्पॉन्स सेंसर शामिल हैं. इसमें टेक्सट मैसेज. ई–मेल, सोशल नेटवर्किंग, कॉल और अलार्म नोटिफिकेशन, फिटनेस डाटा रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स उपलब्ध हैं. इसकी कीमत लगभग 12000 रुपये है. ये फिटनेस बैंड विंडोज 8.1

फोन ओएस, आईओएस7.1 और 8, एंड्रॉयड4.3–4.4 ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है. ■

मैटेलिक सैमसंग गैलक्सी–3

स्मार्टफोन की लोकप्रियता को देखते हुए सैमसंग ने मटैलिक यूनिबॉडी के साथ प्रीमियम डिजाइन वाला गैलक्सी 3 स्मार्टफोन लॉन्च किया है. सैमसंग गैलक्सी3 में 960 गुणा540 पिक्सल रेजोल्यूशन का 4.5 इंच का एचडी सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और साथ ही इसमें 1.2 गीगाहर्ट्ज क्वॉड–कोर प्रोसेसर और एक जीबी रैम है. यह एंड्रॉयड 4.4 किटकैट पर आधारित है. सैमसंग गैलक्सी 3 में पीछे की तरफ एलईडी फ्लैश के साथ 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा है और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा है. इसमें वाइड सेल्फी, पाम सेल्फी, ऐनिमेटेड जीआईएफ, ब्यूटी फेस फीचर्स और रियर–कैम सेल्फी जैसे फीचर्स हैं. इसमें 16 जीबी इंटरनल स्टॉरेज हैं और 64 जीबी तक माइक्रो–एसडी कार्ड लगाया जा सकता है. इस पर 30एफपीएस पर फुल एचडी (1920गुणा1080 पिक्सल) वीडियो प्ले किए जा सकते हैं. सैमसंग गैलक्सी 3 में बैटरी 1900एमएएच की है. कनेक्टिविटी ऑप्शंस में जीपीआरएस, एज, 3जी, 4जीएलटीई, वाई–फाई, ब्लूटूथ, एनएफसी (एलटीई वर्जन में) और ए–जीपीएस/ग्लोनास शामिल हैं. ■

हीरो ने उतारीं दो ई–साइकिल

टू व्हीलर कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक ने अपनी अवियॉर सीरीज के तहत दो ई–साइकिल बाजार में लॉन्च की है. ये ई–साइकिल बेंगलुरू, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और चेंन्नई में भी उपलब्ध होंगी. छह स्पीड गियर की ई–साइकिल में लिथियम बैटरी इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया है जिसे 4.5–5.5 घंटों में चार्ज किया जा सकता है. यह ई–साइकिल अधिकतम 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है. इनको पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए तैयार किया गया है. ये ई–साइकिल वियर एमएक्स और वियर एफएक्स के नाम से बाजार उतारी गई हैं. इन ई–साइकिल की कीमत 18,990 और 19,290 रुपये रखी गई हैं. ■

जियोमी लाएगी 9 इंच का सबसे सस्ता टैबलेट

चाइनीज हैंडसेट बनाने वाली कंपनी जियोमी स्मार्टफोन के बाद अब कंपनी भारतीय ग्राहकों को सस्ते टैबलेट उपलब्ध कराना चाहती है. स्मार्टफोन बाजार में अच्छी लोकप्रियता पाने के बाद जियोमी ने अब टैबलेट बनाने की योजना बनाई है. कंपनी सस्ते टैबलेट बाजार में उतारना चाहती है. जियोमी केटैबलेट को लेकर बात करें तो यह पहली बार नहीं है कि कंपनी नया टैबलेट बना रही हो. इससे पहले भी जियोमी केटैबलेट बाजार में बिकते थे, हालांकि भारत में यह उपलब्ध नहीं हैं. जियोमी ने एमआइ पैड नाम से टैबलेट लॉन्च किया था. यह टैबलेट भी काफी मशहूर है, लेकिन कंपनी अब भारतीय बाजार में सस्ते टैबलेट बनाकर और ज्यादा लोकप्रियता पाना चाहती है. इस टैबलेट की खुबियों की बात करें तो इसकी 9.2 इंच का डिस्प्ले होगी. इसकेअलावा इस बजट टैबलेट में 1.2 गीगाहर्ट्ज का क्वॉड–कोर प्रोसेसर मिलेगा. इसमें आपको 1जीबी की रैम मिलेगी. इसकेसाथ ही 8जीबी की इंटरनल मेमोरी भी उपलब्ध रहेगी. अब अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो इस टैबलेट में एंड्रॉयड किटकैट 4.4.4 का ओएस मिलेगा. वहीं कनेक्टिविटी में ब्लूटुथ, वाइ–फाइ आदि मिलेगा. फिलहाल इसमें सिंगल सिम स्लॉट उपलब्ध रहेगा. इसकी कीमत लगभग 9000 रुपये होगी. ■

मिनटों में चार्ज हो सकता मोबाइल फोन

एचटीसी ने एक ऐसा चार्जर बनाया है जो मोबाइल फोन को मिनटों में चार्ज कर सकता है. कंपनी के अनुसार यह रैपिड चार्जर 2.0 है और यह कई तरह के हैंडसेट की चार्जिंग का समय 40 फीसदी तक घटा सकता है. यह चार्जर क्वॉलकॉम की नई तकनीक न्यू क्विक चार्ज 2.0 टेक्नोलॉजी से लैस है और यह किसी भी तरह के स्मार्टफोन या टैबलेट को तेजी से चार्ज कर सकता है. कंपनी का दावा है कि रैपिड चार्जर 2.0 किसी भी बैटरी को 15 मिनटों में चार्ज करके उसका टॉक टाइम 8 घंटे तक बढ़ा सकता है. एचटीसी के तमाम फोन इससे चार्ज हो सकते हैं. रैपिड चार्जर 2.0 मोटोरोला के टरबो चार्जर की तरह ही है. ■

ऑडी की पावरफुल कार आर 8 कॉम्पटिशन

ऑडी अपनी सबसे पावरफुल कार ऑडी आर8 कॉम्पटिशन लॉन्च करने की तैयारी में है. इसमें ब्लैक कार्बन फाइबर के पुर्जे इस्तेमाल किए गए हैं. इसमें 19 इंच के ग्लॉस ब्लैक एलॉय व्हील्स हैं. ऑडी आर8 में 5.2–लीटर वी10 इंजन है, जो 570 पीएस पावर देता है. इसमें 7–स्पीड एस ट्रॉनिक ट्रांसमिशन और ऑल–व्हील ड्राइव सिस्टम है. इनकी बदौलत यह महज 3.2 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ लेती है. इसकी अधिकतम स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा है. इसकी केवल 60 यूनिट्स तैयार की जाएंगी. इंटरनेशनल बाजार में कंपनी नवंबर में ऑर्डर लेना शुरू करेगी. ■

ऑडी आर8 में 5.2–लीटर वी10 इंजन है, जो 570 पीएस पावर देता है. इसमें 7–स्पीड एस ट्रॉनिक ट्रांसमिशन और ऑल–व्हील ड्राइव सिस्टम है. इनकी बदौलत यह महज 3.2 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ लेती है. इसकी अधिकतम स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा है.

एचपी ने लॉन्च की शानदार स्मार्ट वॉच

एचपी ने एक सी स्मार्टवॉच पेश की है, जो दिखने में सामान्य घड़ी की तरह ही है. एचपी ने इस स्मार्टवॉच को मिशेल बेटियन के साथ मिलकर बनाया है तथा वो सभी फीचर दिए हैं जो अब आई सभी स्मार्टवॉच में उपलब्ध है. यह स्मार्टवॉच आईओएस और एंड्रॉयड ओएस वाले गैजेट्स से कनेक्ट होती है. इसें सिल्वर और लिमिटेड एडिशन इन दो वेरियंट में उतारा गया है. हालांकि लिमिटेड एडिशन की सिर्फ 300 यूनिट ही बिक्री के लिए जारी की जा रही है. एचपी बेस्टियन स्मार्टवाच के सिल्वर वेरियंट की कीमत 21,400 रुपये होगी और लिमिटेड एडिशन की कीमत लगभग 39,900 रुपये होगी. अत्याधुनिक फीचर्स से लैस एचपी बेस्टियन स्मार्टवॉच में मोनोक्रोम एलईसीडी डिस्पले दिया गया है जिसमें नोटिफिकेशंस, मैसेज, मौसम की जानकारी, स्टॉक प्राइस जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें एक छोटा सा टाइमपीस डायल भी दिया गया है.

एचपी बेस्टियन स्मार्टवॉच सिल्वर वेरियंट में 44 एमएम स्टेनलैस स्टील केसिंग और तीन एक्सचेंजेबल स्ट्रेप्स दिए गए हैं. यह स्मार्टवॉच वाटरप्रूफ है जबकि इसमें शानदार बैटरी दी गई है जो लगातार एक हफ्ते तक चलती है. जबकि लिमिटेड एडिशन में एलिगेटर लेदर स्ट्रेप सफायर ग्लास और पीवीडी पेंटिंग के साथ दिया है. ■

स्मार्ट वॉच के लिए फ्लिपकार्ट का नया ऐप

फ्लिपकार्ट ने अपने ग्राहकों को एक नया तोहफा दिया है. कंपनी ने खासतौर पर एंड्रॉयड वियरेबल डिवाइस इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए एक नई ऐप्लीकेशन तैयार की है. इस नई ऐप से यूजर्स अपने स्मार्ट बैंड या स्मार्टवॉच पर फ्लिपकार्ट की नोटिफिकेशन देख सकेंगे. कंपनी का कहना है कि भविष्य में इस ऐप में अनगिनत फीचर्स जोड़े जा सकेंगे जिनमें से एक होगा ग्राहक द्वारा स्मार्टवॉच की मदद से ही अपने फ्लिपकार्ट ऑर्डर को ट्रैक कर पाना. इस समय यदि फ्लिपकार्ट पर मौजूद वियरेबल डिवाइस की बात की जाए तो इस वेबसाइट पर मोटोरोला की मोटो 360 स्मार्टवॉच बिक्री के लिए उपलब्ध है. इसके अलावा वेबसाइट पर गर्मिन व मार्टियन के वियरएबल डिवाइस भी मौजूद हैं. इसके अलावा यदि एंड्रॉयड वियर फ्लिपकार्ट ऐप की विशेषताओं की बात करें तो यह एप आपको फ्लिपकार्ट पर खरीददारी, सामान की पेमेंट करना, नोटिफिकेशन देख पाना व मनचाहे प्रोडक्ट्स को आसानी से खोज पाने की सुविधा देती है. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

पाकिस्तान के खिलाफ भुवनेश्वर को पहली बार टीम इंडिया के लिए खेलने को मौका मिला तो उन्होंने जश्न मनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया. भुवी ने अपनी करियर की पहली गेंद पर ही विकेट झटका था. टी–20 और वन–डे की कामयाबी के बाद भुवनेश्वर को टेस्ट टीम के लिए भी बुलावा मिला. अपने करियर के पहले टेस्ट मैच की दो पारियों में हुए 226 ओवर में से भुवनेश्वर को महज़ 13 ओवर डालने का मौका मिला और उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 के हैदराबाद टेस्ट के पहले दिन अपने पहले 9 ओवर के स्पेल में भुवनेश्वर ने दिखा दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी प्रभावशाली होने की काबिलियत रखते हैं.

सफलता की राह पर चल पड़ी है मेरठ मेल

सचिन तेंदुलकर से भुवनेश्वर का पुराना नाता है. भुवनेश्वर भारत के चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं. जिनका जन्म सचिन तेंदुलकर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना शुरू करने के बाद हुआ और उन्हें उनके साथ खेलने का सौभाग्य भी मिला. लेकिन यह महज़ एक इत्तेफाक ही है कि भुवनेश्वर को पहली बार राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में जगह सचिन तेंदुलकर की वजह से ही मिली थी. आज भुवनेश्वर को वह पुरस्कार मिला है जिसे जीतने वाले सचिन पहले क्रिकेटर थे. 24 वर्षीय भुवी यह पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं.

नवीन चौहान

उत्तर प्रदेश का मेरठ विश्वस्तरीय खेल उत्पादों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. लेकिन समय के साथ मेरठ को यहां के खिलाड़ियों की वजह से भी पहचाना जाने लगा है. सबसे पहले भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होकर प्रवीण कुमार ने मेरठ को पहचान दिलाई. इसके बाद प्रवीण की विरासत को आगे लेकर चल रहे युवा गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार उनसे भी एक कदम आगे निकल गए हैं. इस साल के आईसीसी पुरस्कारों में भुवी को एलजी पीपुल्स च्वाइस अवार्ड से नवाजा गया है. भुवनेश्वर यह पुरस्कार पाने वाले चौथे खिलाड़ी हैं. 2010 में शुरू हुआ यह पुरस्कार सबसे पहले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को दिया गया था. इसके बाद श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार ने लगातार दो बार(2011 और 2012) यह पुरस्कार जीता. पिछले साल यह पुरस्कार टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया था. भुवनेश्वर ने इस पुरस्कार की दौड़ में शामिल आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी तेज गेंदबाजों मिशेल जॉनसन और डेल स्टेन को पीछे छोड़ दिया. इस पुरस्कार की दौड़ में इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान चार्लेट एडवर्ड और श्रीलंका के कप्तान एंजिलो मैथ्यूज़ भी शामिल थे.

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से भुवनेश्वर का पुराना नाता है. भुवनेश्वर भारत के चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जिनका जन्म सचिन तेंदुलकर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलना शुरू करने के बाद हुआ और उन्हें उनके साथ खेलने का सौभाग्य भी मिला. लेकिन यह महज़ एक इत्तेफाक ही है कि भुवनेश्वर को पहली बार राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में जगह सचिन तेंदुलकर की वजह से ही मिली थी. आज भुवनेश्वर को वह पुरस्कार मिला है जिसे जीतने वाले सचिन पहले क्रिकेटर थे. 24 वर्षीय भुवी यह पुरस्कार जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं. 17 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास करियर शुरु करने वाले भुवी पहली बार सुर्खियों में तब आये थे जब उन्होंने सचिन तेंदुलकर को घरेलू क्रिकेट में बिना खाता खोले पवेलियन भेजने का कमाल कर दिखाया था. वाकया जनवरी 2009 का है. हैदराबाद में हुए रणजी ट्रॉफी फाइनल में भुवनेश्वर का सामना क्रिकेट इतिहास के महानतम बल्लेबाज़ों में से एक सचिन तेंदुलकर से हुआ था. उस वक्त घरेलू क्रिकेट में किसी गेंदबाज में इतनी ताकत नहीं थी कि वह सचिन को लगातार 12 गेंदों तक परेशान करे और एक भी रन न बनाने दे. लेकिन भुवी ने ऐसा किया और स्पेल के तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने तेंदुलकर को आउट करके भारतीय ज़मीं पर फर्स्ट क्लास मैच में पहली बार शून्य से उनकी मुलाकात करवाई. भारतीय टीम में सेलेक्ट होने से ठीक पहले साल 2012–13 में दिलीप टॉफी के सेमीफाइनल में आठवें पायदान पर बल्लेबाजी करते हुए भुवनेश्वर ने128 रनों की बेहतरीन पारी खेल कर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया था.

भुवी भारतीय क्रिकेट की एक बड़ी खोज हैं. उन्होंने अभी अपना अंतरराष्ट्रीय करियर शुरू किया है. छोटे से करियर में ही नई गेंद से विकेट लेना उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया है. उन्होंने अपनी सधी हुई गेंदबाज़ी से एक अलग पहचान बनाई है. एक तेज़ गेदबाज़ के रूप में टीम इंडिया को शुरुआती कामयाबी दिलाने में उन्होंने बेहतरीन भूमिका निभायी है. सबसे अच्छी बात यह है कि भुवी ने दाएं और बायें दोनों हाथ के बल्लेबाज़ों के ख़िलाफ बराबर सफलता हासिल की है. भुवनेश्वर शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया से तेज़ गेंदबाज़ ग्लेन मैक्ग्रा के मुरीद रहे हैं. वह मैक्ग्रा की तरह एक ही स्पॉट पर लगातार गेंद गिराने के हुनर को अपना बनाने की हसरत रखते थे. उन्होंने मैक्ग्रा के नक्शे कदम पर चलते हुए गति से ज्यादा लाइन लेंथ और स्विंग पर काम किया. मैक्ग्रा की जगह गेंद को एक ही स्पॉट से अंदर और बाहर ले जाने की क्षमता उन्हें एक बेहतरीन गेंदबाज बनाती है.

सचिन की ही तरह उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ भुवी को पहली बार टीम इंडिया के लिए खेलने को मौका मिला.उन्होंने जश्न मनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाया अंतरराष्ट्रीय करियर की पहली गेंद पर ही विकेट झटक लिया. टी–20 और वन–डे की कामयाबी के बाद भुवनेश्वर को टेस्ट टीम के लिए भी बुलावा मिला. अपने करियर के पहले टेस्ट मैच की दो पारियों में हुए 226 ओवर में से भुवनेश्वर को महज़ 13 ओवर डालने का मौका मिला और उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 के हैदराबाद टेस्ट के पहले दिन अपने पहले 9 ओवर के स्पेल में भुवनेश्वर ने दिखा दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी प्रभावशाली होने की काबिलियत रखते हैं. भुवनेश्वर कुमार का पहला टेस्ट विकेट बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका पहला विकेट, जब उन्होंने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज नासिर जमशेद को बाहर जाती गेंदों से छकाने के बाद अंदर आती गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया था. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के हर फॉर्मेट में पहला विकेट बोल्ड के रुप में लेकर एक अनोखी हैट्रिक बनाई. अपने पहले टी–20 मैच में भुवी ने 4 ओवर में 9 रन देकर तीन विकेट लिए थे. यह पदार्पण टी–20 मैच का प्रदर्शन का नया विश्वरिकॉर्ड था.

एलजी पीपुल्स च्वाईस पुरस्कार जीतने की खबर पाने के बाद भुवनेश्वर कुमार ने कहा कि सबसे पहले मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने एलजी पीपुल्स च्वाइस अवार्ड के लिए मुझे वोट किया. इस पुरस्कार के मेरे लिए बहुत मायने हैं यह पुरस्कार मुझे केवल मेरे व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए नहीं मिला है इसके पीछे प्रशंसकों के प्यार और समर्थन का भी योगदान है. आज मैं जहां हूं वह मैं अपने माता–पिता और प्रशिक्षकों की वजह से हूं. उन्होंने मुझे जीवन में जो सिखाई गई बातों की वजह से हूं. मैं अपनी टीम के साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उनके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था, इसलिए आप सभी का बहुत–बहुत धन्यवाद.

क्रिकेट के हर फॉर्मेट में उन्हें जैसे–जैसे कामयाबी मिलती गई, भुवनेश्वर का हौसला बढ़ता गया. इंग्लैंड में खेली गई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में भुवनेश्वर की भूमिका बेहद अहम रही. इसके बाद वेस्टइंडीज़ में हुई त्रिकोणीय वन–डे सीरीज़ में भुवनेश्वर मैन ऑफ द सरीज भी बने. इसके बाद भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे में टेस्ट सीरीज में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन किया. इंग्लैंड दौरे पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया और इसके बाद टेस्ट करियर में पहली बार एक पारी में पांच विकेट लिए. इसके बाद अगले टेस्ट में भी उन्होंने अपना करिश्माई प्रदर्शन जारी रखा और दूसरी बार पारी में पांच विकेट लिए. साथ ही सीरीज में तीसरी बार अर्धशतकीय पारी खेली. भारतीय टीम को सीरीज में 1–3 से हार मिली. बावजूद इसके भुवी को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया. छोटे से करियर में भुवी की अब तक इस बात के लिए काफी तारीफ हुई है कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बड़े–बड़े नामों को अपनी गेंदों से पस्त किया है. भुवी अब तक करियर में 11 टेस्ट, 39 वनडे और 9 टी–20 मैच खेल चुके हैं. उन्होंने तीन फॉर्मेट में क्रमशः 28,42 और 11 विकेट भी चटकाए हैं. उनके प्रदर्शन में लगातार सुधार भी आ रहा है.

जहीर ख़ान के टीम से बाहर रहने के बाद भुवी ने मोहम्मद शमी के साथ भारतीय टीम की गेंदबाजी को संभाल लिया है. 2015 में ऑस्ट्रेलिया–न्यूजीलैंड की संयुक्त मेज़बानी में होने वाले विश्वकप में वह भारतीय गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत होंगे. वहां की तेज पिचों में उनकी स्विंग होती गेंदों टीम इंडिया को खिताब बचाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होंगी. विश्वकप से ठीक पहले टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रही है. 24 नवंबर से 1 फरवरी तक भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई धरती पर चार टेस्ट मैच और त्रिकोणीय श्रृंखला खेलेगी. इसके बाद 14 फरवरी को विश्वकप का आगाज़ होगा. यह दौरा भुवनेश्वर के लिए पहला ऑस्ट्रेलियाई दौरा होगा. जहां की परिस्थितियों से तालमेल बैठाने के लिए उन्हें जरूरत से बहुत ज्यादा वक्त मिलेगा. दो साल से भी छोटे से करियर में भुवनेश्वर तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ी हैं. एकदिवसीय रैंकिंग में वह सातवें पायदान पर हैं. इतने ही कम समय में वह भारतीय टीम की सबसे मजबूत कड़ी बन गए हैं. उनके बारें उनके टीम मेट्स और कोच भी कहते हैं कि वह एक अनुशासित खिलाड़ी हैं. वह सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं और अपनी सीमाओं को बखूबी जानते हैं यही उनकी सफलता का राज है. अगर उन्हें दूसरे छोर से सहयोग मिले तो वह टीम को निश्चित तौर पर सफलता दिलाते हैं. यदि परिस्थितियां स्विंग के लिए अनुकूल हों तो कप्तान धोनी भी उनसे विकेट की आशा करते हैं वह उन्हें मैच के आखिरी समय के लिए बचाकर नहीं रखते हैं. यह धोनी उनके प्रति विश्वास को दिखाता है.

मेरठ मेल चल पड़ी है और वह अंततः सफलता के किस मुकाम पर पहुंचकर रुकेगी, यह तो वक्त ही बताएगा. फिलहाल मेरठ मेल जिस गति से आगे बढ़ रही है और सफलता के जिन से होकर गुजर रही है उससे तो लगता है वह देश के लिए सफलता की नई इबारत लिखेंगे और भारतीय तेज़ गेदबाजी को एक नए मुकाम तक लेकर जाएंगे. ■

navinonline2003@gmail.com

सचिन की आत्मकथा का विमोचन

भारत रत्न मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बहुप्रतीक्षित आत्मकथा प्लेयिंग इट माई वे का विमोचन मुंबई के एक पांच सितारा होटल में हुआ. उनकी आत्मकथा के विमोचन के कार्यक्रम में क्रिकेट जगत के दिग्गजों के साथ परिवार के सदस्य मौजूद थे. सचिन ने अपनी आत्मकथा की पहली प्रति अपनी मां रजनी तेंदुलकर को भेंट की. उनकी मां सचिन के करियर का आखिरी टेस्ट मैच देखने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम भी गईं थीं. सचिन ने अपनी आत्मकथा में जिंदगी के कई अनछुए पहलुओं के बारे में भी लिखा है. उनमें उनकी और उनकी पत्नि अंजली के बीच की प्रेम कहानी का भी जिक्र है. सचिन ने बताया कि इस बारे में लिखना उनके लिए काफी मुश्किल था क्योंकि इसके बारे में हम दोनों के अलावा किसी को कुछ नहीं मालूम था. अंजली से जब वह पहली बार एयरपोर्ट पर मिले थे तब उन्हें सचिन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था. सचिन ने कोच ग्रेग चैपल की भूमिका के बारे में भी लिखा है इसे लेकर विवाद भी हो रहा है. उनके गुरू रमाकांत आचरेकर भी कार्यक्रम में मौजूद थे. उन्हें किताब भेंट करने के बाद सचिन ने कहा कि मैं किताब के लॉन्च होने के बाद पहली प्रति किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहता था जो मेरे जीवन में काफी विशेष है. ■

मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट में बड़े क्रिकेटर का नाम

आईपीएल–6 में सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच करने वाली जस्टिस मुकुल मुद्गल कमिटी ने जांच की अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है. इस रिपोर्ट में भारतीय टीम के एक ऐसे क्रिकेटर पर उंगली उठाई गई है, जो साल 2011 में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का सदस्य भी रह चुका है. एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि इस खिलाड़ी के तार सट्टेबाजों और मैच को फिक्स करने वाले लोगों से जुड़े हैं. यह खिलाड़ी अब टीम इंडिया के नियमित सदस्य नहीं हैं, लेकिन आईपीएल के उस सेशन में उसके लिए मोटी बोली लगाई गई थी. खास बात है कि यह खिलाड़ी चेन्नई सुपरकिंग्स या राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा नहीं था. स्पॉट फिक्सिंग के मामले राजस्थान रॉयल्स के तीन क्रिकेटर गिरफ्तार हुए थे और चेन्नई सुपरकिंग्स के अधिकारी गुरुनाथ मयप्पन सट्टेबाजी के आरोपों से घिर गए थे. इस वजह से यह दोनों टीमें जांच के दायरे में खासतौर पर थीं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

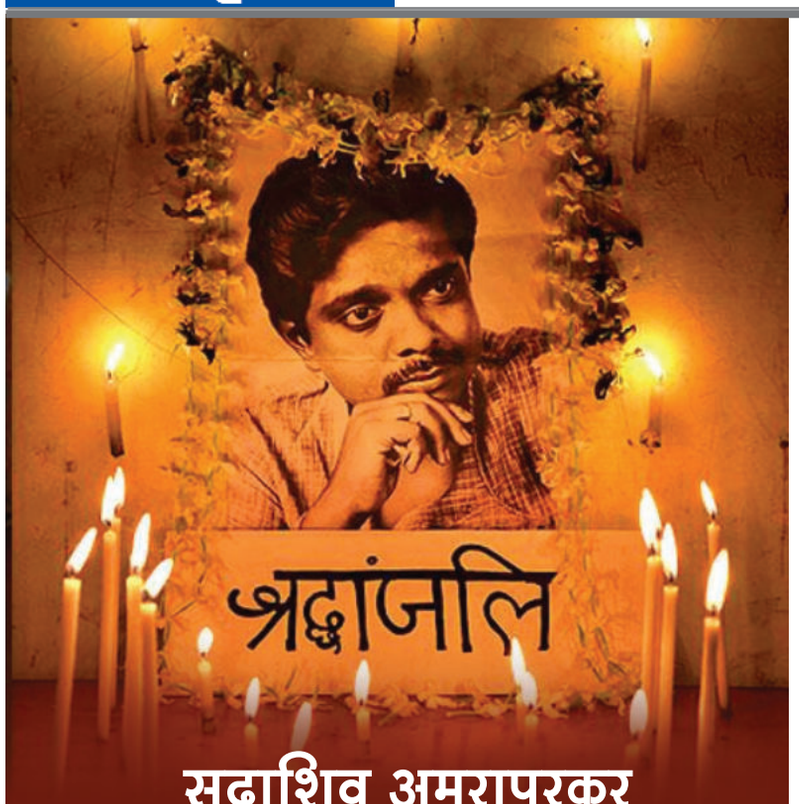

सदाशिव अमरापुरकर

एक (खल) नायक नहीं रहा

फिल्म सड़क की महारानी को कौन भूल सकता है. 1991 में उन्हें फिल्म सड़क में महारानी नाम के किन्नर की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था. संयोग से सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कारों में देना शुरू किया गया और संयोग से यह पुरस्कार सदाशिव अमरापुरकर को मिला. प्रारंभिक दौर में या कहें एक दशक तक वह फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाते रहे.

अस्सी और नब्बे के दशक के लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर 64 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया. वह फेफड़ों के संक्रमण से पीड़ित थे. मुंबई के एक निजि अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था.

सदाशिव अमरापुरकर का जन्म 11 मई 1950 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक ब्राम्हण परिवार में हुआ था. उनके पिता अहमदनगर एक जाने-माने व्यक्ति थे. सदाशिव अमरापुरकर का असली नाम गणेश कुमार नरोड़े था. परिवार और साथी उन्हें तात्या कहकर पुकारते थे. वह बचपन से ही सक्रिय थे. समाज के हर समुदाय के लोगों से उनकी मित्रता थी. बचपन से ही अभिनय में उनकी रुचि थी. उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए किया साथ ही उन्होंने थियेटर में अभिनय करना जारी रखा. यह बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि सदाशिव एक प्रशिक्षत गायक थे. लेकिन नाक से गाने की वजह से उन्होंने गायकी को बतौर करियर नहीं अपनाया.

सदाशिव ने मराठी फिल्म आमरस से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था. इसके बाद उन्होंने एक नाटक में बाल गंगाधर तिलक का रोल अदा किया था. जहां उन पर गोविंद नेहलानी की नज़र पड़ी. उस समय वह अपनी नई फिल्म अर्धसत्य के खलनायक के किरदार के लिए एक कलाकार की खोज में थे. फिल्म हिट रही और अमरापुरकर की डॉन रामा शेट्टी के रूप में बहुत प्रशंसा हुई. उनके डॉयलाग डिल्वरी का उस दौर के पॉपुलर खलनायकों से हटकर था. इस वजह से भी वह काफी लोकप्रिय हुए. अर्धसत्य के बाद अमरापुरकर को पुराना मंदिर, नासूर, मुद्दत, वीरू दादा, जवानी, फरिश्ते जैसी फिल्मों में छोटी-छोटी भूमिकाएं मिलीं. लेकिन 1987 में धर्मेंद्र के साथ फिल्म हुकूमत में उन्होंने मुख्य खलनायक के रुप में काम किया. फिल्म सुपरहिट रही. फिल्म ने कमाई के मामले में मिस्टर इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया था. उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के ही-मैन धर्मेंद्र के लिए लकी मैसकॉट माना जाता था. उन्होंने धर्मेंद्र के साथ मुद्दत, फरिश्ते, पुराना मंदिर और कई अन्य फिल्मों में काम किया. एक दशक तक खलनायक की भूमिका सफलतापूर्वक निभाने के बाद सदाशिव ने चरित्र और हास्य अभिनेता के रुप में काम किया. आंखें, इश्क, गुप्त, कुली नंबर-1, आंटी नंबर -1 जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया.

उन्होंने अपने करियर में तीन सौ से भी अधिक फिल्मों में काम किया. उन्होंने हिन्दी, मराठी के अलावा बंगाली, उड़िया, हरियाणवी आदि क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया. वह जीवनपर्यंत समाजसेवा के कार्यों में लगे रहे. उनके मन में ग्रामीण युवाओं के लिए एक विशेष जगह थी. फिल्मी करियर में उन्हें दो बार फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया. पहली बार वर्ष 1984 में उन्हें फिल्म अर्धसत्य के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का फेयर पुरस्कार दिया गया था. फिल्म सड़क की महारानी को कौन भूल सकता है. 1991 में उन्हें फिल्म सड़क में महारानी नाम के किन्नर की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था. संयोग से सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कारों में देना शुरू किया गया और संयोग से यह पुरस्कार सदाशिव अमरापुरकर को मिला.

चरित्र और हास्य अभिनेता के रूप में उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्में आंखें, इश्क, कुली नंबर-1, आंटी नंबर वन गुप्त आदि हैं. इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान मराठी फिल्मों की ओर केंद्रित कर लिया. अमरापुरकर के करियर की आखिरी फिल्म 2012 में आई बांबे टॉकीज रही. इस फिल्म को हिंदी सिनेमा के सौ साल होने के उपलक्ष्य में बनाया गया था. पिछले कुछ सालों से वह सिर्फ चुनिंदा फिल्में ही कर रहे थे.

सदाशिव एक अच्छे अभिनेता होने के साथ-साथ एक अच्छे इंसान भी थे. जीवन के आखिरी दिनों में किताबें पढ़ते, पेंटिंग करते और लिखते थे. इसके आलावा वह सक्रिय रुप से समाजसेवा के कार्यों में लगे रहे. फिल्मों से इतर वह सामाजिक कार्यों में ज्यादा रुचि ले रहे थे. होली में पानी की बर्बादी के विरोध में उन्होंने आवाज भी उठाई. इसके बाद उन पर कुछ युवकों ने हमला भी कर दिया था. उम्र का साठवां पड़ाव पार करने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके अंदर का कलाकार एक परफेक्ट रोल की प्रतीक्षा कर रहा है. लेकिन वह रोल उन्हें मिल न सका और वह दुनिया को ही अलविदा कह गए. फिल्म सड़क उन्होंने महारानी के किरदार को सजीव कर दिया. उनका यह किरदार अमजद खान के फिल्म शोले के गब्बर सिंह के किरदार के समकक्ष का है. बॉलीवुड के खलनायकों का इतिहास जब कभी भी लिखा जाएगा. उसमें सदाशिव अमरापुरकर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

सलमान के गुण गा रही हैं जैकलीन

जैकलीन ने सलमान के साथ काम करने के अनुभव को बेहतरीन बताते हुए कहा कि सलमान एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं. वह फिल्मन के सेट कभी भी अपनी कोई भी राय किसी पर नहीं थोपते. वह एक अलग ही तरह के इंसान हैं. वे सबकी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं.

पूर्व मिस श्रीलंका और बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज इन दिनों सलमान खान के गुण गा रही है. जैकलीन ने सलमान के साथ फिल्म किक में काम किया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया था. जैकलीन को कहना है कि, सलमान के साथ काम करने के बाद उनके करियर को किक लग गई है. इसके बाद से उनके पास काफी फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं और वे इसकी वजह सिर्फ सलमान को मानती हैं. आजकल कोई भी उनसे उनके करियर के बारे में पूछता है तो वे सीधे सलमान का नाम लेती हैं. उनकी तारीफों के पुल बांधती नजर आती हैं. जैकलीन ने सलमान के साथ काम करने के अनुभव को बेहतरीन बताते हुए कहा कि सलमान एक बहुत ही अच्छे इंसान है. वह फिल्म के सेट कभी भी अपनी कोई भी राय किसी पर नहीं थोपते हैं. वह एक अलग ही तरह के इंसान है. वह सबकी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं. वे अपने को-स्टॉर से कभी नहीं उलझते. जैकलीन इन दिनों रणबीर कपूर और अर्जुन रामपाल के साथ फिल्म रॉय की शूटिंग में व्यस्त हैं.■

1983 विश्वकप जीत पर फिल्म

आजकल बॉलीवुड में खेल और खिलाड़ियों की जिंदगी पर फिल्में बनाने का नया ट्रेंड शुरू हुआ है. मेरीकॉम और महेंद्र सिंह धोनी के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम के वर्ष 1983 में विश्वकप जीतने पर आधारित एक फिल्म का निर्माण किया जाने वाला है. इसमें हरियाणा हरिकेन के नाम से मशहूर क्रिकेटर और 1983 में भारत को विश्वविजेता बनाने वाले कप्तान कपिल देव की भूमिका रणदीप हुड्डा निभाते नज़र आ सकते हैं. फिल्म का निर्देशन पूरण सिंह चौहान करेंगे. चर्चा है कि निर्देशक फिल्म को लेकर काफी रिसर्च कर रहे हैं और कपिल देव के साथ भी गहराई से बात कर रहे हैं.■

राजनीति-2 और गंगाजल-2 का फर्स्ट लुक जारी

बॉलीवुड के जानेमाने फिल्मकार प्रकाश झा ने अपनी आने वाली फिल्म गंगाजल-2 का पहला लुक जारी कर दिया है. गंगाजल के पोस्टर में एक महिला पुलिसकर्मी हाथ में पिस्तौल लिए नज़र आ रही हैं. गंगाजल के सीक्वल के लिये प्रकाश ने मध्यप्रदेश की एक महिला पुलिस अधिकारी की जिंदगी और उपलब्धियों से प्रेरणा ली है. वर्ष 2003 में प्रदर्शित फिल्म गंगाजल में अजय देवगन और ग्रेसी सिंह ने मुख्य भूमिका में थे. नई फिल्म के संबंध में प्रकाश झा ने कहा कि मैंने इस फिल्म में महिला के किरदार को मुख्य रखा है क्योंकि ये मध्य प्रदेश की एक महिला पुलिस अधिकारी के सम्मान में है जिनकी उपस्थिति एक तेजतर्रार रवैये को दर्शाती है. मैं इस समय उनके नाम का खुलासा नहीं कर सकता. चर्चा है कि फिल्म के मुख्य किरदार के लिए करीना कपूर को एप्रोच किया गया है. प्रकाश ने पहले फिल्म में अजय देवगन को लेने का फैसला किया था लेकिन कहानी की मांग के मुताबिक अभिनेत्री का किरदार अहम था. इस बार अजय फिल्म में नहीं हैं क्योंकि फिल्म में एक पुरूष पुलिसकर्मी का किरदार नहीं है. हालांकि अजय देवगन को फिल्म कहानी पसंद आई है और उन्होंने खुद को फिल्म के प्रेजेंटर के तौर पर जोड़ लिया है. अजय के साथ मैं कई और फिल्मों में काम करना चाहता हूं. इसी तरह राजनीति-2 का पोस्टर भी रिलीज किया गया. इसमें संसद के सामने लोगों की भीड़ को संघर्ष करते दिखाया गया है.राजनीति-2 की स्टारकास्ट को लेकर प्रकाश झा ने अभी कोई खुलासा नहीं किया है. राजनीति एक बॉक्स ऑफिस में सफल रही थी.■

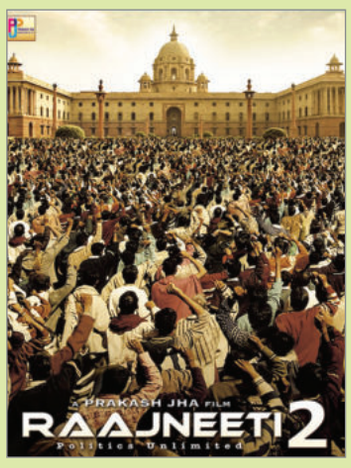

जॉली एलएलबी के सीक्वल के लिए बेताब हैं अरशद वारसी

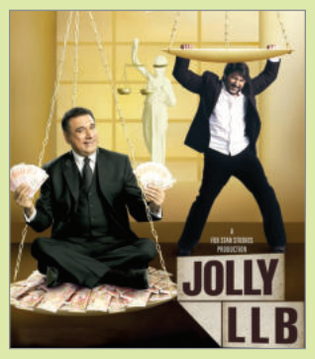

सुभाष कपूर ने साल 2013 में अरशद वारसी, बोमन इरानी और सौरभ शुक्ला को लेकर जॉली एलएलबी बनाई थी. फिल्म को 61 वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था.

बॉलीवुड में अपने कॉमिक अभिनय के लिए मशहूर अरशद वारसी अपनी सुपरहिट फिल्म जॉली के सीक्वल जॉली एलएलबी-2 में काम करने के लिए बेहद उत्साहित हैं. अरशद ने ट्वीट किया कि पिछली रात जॉली एलएलबी-2 के कुछ सीन सुने और मेरे पास अपने रोमांच को जाहिर करने के लिए शब्द नहीं हैं कि मैं फिल्म की शूटिंग के लिए कितना बेताब हूं. गौरतलब है कि सुभाष कपूर ने साल 2013 में अरशद वारसी, बोमन इरानी और सौरभ शुक्ला को लेकर जॉली एलएलबी बनाई थी. फिल्म को 61 वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था. साथ ही सौरव शुक्ला को सर्वश्रेष्ठ सहअभिनेता का पुरस्कार भी इसी फिल्म के लिए मिला था. इसके बाद सुभाष कपूर अब इस फिल्म का सीक्वल बना रहे हैं.■

चौथी दुनिया

17 नवंबर–23 नवंबर 2014

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार-झारखंड

चुनावी तस्वीर बदल देंगे बागी

सूत्रों पर भरोसा करें तो ज्ञानू की टीम मोटे तौर पर मन बना चुकी है और अदालती प्रक्रियाओं से निपटने के बाद इनके साथी अपने-अपने दल का चुनाव कर लेंगे और जोर-शोर से चुनावी अभियान में जुट जाएंगे. वैसे अदालत से भी उन्हें न्याय की उम्मीद है. ज्ञानू कहते हैं कि न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है और न्याय पाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम सर्वोच्च अदालत तक जाएंगे. ज्ञानू कहते हैं कि स्पीकर साहब ने तानाशाही फरमान सुनाया है. स्पीकर ने नीतीश कुमार के दबाव में आकर बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त की. हमने स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

सरोज सिंह

जैसा की तय था जदयू के बागी विधायकों के पर कतरने का काम अब पूरा किया जा रहा है. पहली खेप में चार निपटाए गए और अब आगे की तैयारी हो रही है तीन या चार फिर नपेंगे. जदयू के बागी विधायक भी मानसिक तौर पर इस तरह के फैसले के लिए तैयार बैठे थे. बागियों के नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बिना देर किए अपने साथियों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया और अगले ही दिन मुलाकात यात्रा पर निकल गए. ये बागी विधायक अब पूरे बिहार में घूम-घूम कर नीतीश कुमार की तानाशाही और असंवैधानिक रवैये को जनता और जदयू के कार्यकर्ताओं को अवगत कराएंगे. यह सिलसिला चुनाव तक चलता रहेगा लेकिन इन सबके बीच सूबे की चुनावी राजनीति को प्रभावित करने के लिए जदयू के बागी विधायक एक व्यापक कार्ययोजना पर भी काम कर रहे हैं. कई चरणों में लागू होने वाली इस रणनीति पर अगर सही तरीके से अमल हो गया तो यह कहना गलत नहीं होगा कि बिहार के चुनावी नतीजे अभी के अनुमानों से कुछ अलग ही होंगे. बागियों ने पहले यह तय किया है कि जहां-जहां भी नीतीश कुमार संपर्क यात्रा पर जाएंगे, उनके पीछे बागी भी जाएंगे और नीतीश कुमार के वादों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे. बागी चाहते हैं कि नीतीश कुमार अपनी इस संपर्क यात्रा से कार्यकर्ताओं को भ्रम में न रख सकें. कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि इस बार झांसे में आने की जरूरत नहीं है. नीतीश कुमार ने जो वादा किया, उसे आज तक नहीं निभाया है.

बागी गुट की दूसरी पहल यह हो रही है कि वह जीतन राम मांझी को आगे रखकर जदयू की एक अलग तस्वीर बनाने की काशिश कर रहे हैं. बागी विधायक चाहते हैं कि अगर जदयू में ही रहने की नौबत बन गई तो कम से कम उनका नेता जीतन राम मांझी को बनाया जाए और दल के अंदर नीतीश कुमार की तानाशाही को एकदम कम कर दिया जाए. लेकिन अगर नीतीश कुमार का प्रभाव पार्टी में बना रह गया तो फिर एक अलग रास्ता बनाया जाएगा. जानकार सूत्र बताते हैं कि बागी विधायकों ने तय किया है वे एक साथ किसी एक पार्टी में नहीं जाएंगे. क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया जाएगा कि कौन सा नेता किस दल में जाएगा. मसलन किसे भाजपा में जाना है, किसे लोजपा में जाना है और किसे रालोसपा में जाना है. तीनों दलों के प्रमुखों से इन लोगों की प्रारंभिक बात हो जाने की भी चर्चा है. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मंगल पांडेय ने तो बागी विधायकों को अपने दल में लेने का औपचारिक न्योता भी दे दिया है. बागी अपने क्षेत्र के जातीय और राजनीतिक समीकरण को देखते हुए एनडीए के दलों में जाने का निर्णय ले सकते हैं. बताया जा रहा है कि वैसे भी रालोसपा और लोजपा में मजबूत प्रत्याशियों की कमी है. अगर

बागी गुट की दूसरी पहल यह हो रही है कि वह जीतन राम मांझी को आगे रखकर जदयू की एक अलग तस्वीर बनाने की काशिश कर रहे हैं. बागी विधायक चाहते हैं कि अगर जदयू में ही रहने की नौबत बन गई तो कम से कम उनका नेता जीतन राम मांझी को बनाया जाए और दल के अंदर नीतीश कुमार की तानाशाही को एकदम कम कर दिया जाए.

कुछ सिटिंग विधायक अगर इन दोनों दलों का दामन थामते हैं तो फिर भाजपा को भी इन्हें ज्यादा सीट देने में परेशानी नहीं होगी और उनके जीतने की संभावना भी बढ़ जाएगी. सूत्रों पर भरोसा करें तो ज्ञानू की टीम मोटे तौर पर मन बना चुकी है और अदालती प्रक्रियाओं से निपटने के बाद इनके साथी अपने-अपने दल का चुनाव कर लेंगे और जोर-शोर से चुनावी अभियान में जुट जाएंगे. वैसे अदालत से भी उन्हें न्याय की उम्मीद है. ज्ञानू कहते हैं कि न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है और न्याय पाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम सर्वोच्च अदालत तक जाएंगे. ज्ञानू कहते हैं कि स्पीकर साहब ने तानाशाही फरमान सुनाया है. स्पीकर ने नीतीश कुमार के दबाव में आकर बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त की. हमने स्पीकर के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

अब किरकिरी से बचने के लिए पीके शाही को आगे कर बयान दिलवाया जा रहा है. यह कितना हास्यास्पद है कि स्वेच्छा से दल छोड़ने के आधार पर स्पीकर ने जिन चार विधायकों की सदस्यता समाप्त की, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दूसरे दिन पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से मुक्त करते हुए निष्कासन की कार्रवाई की. राज्यसभा उपचुनाव के बाद विधानसभा सत्र के दौरान चारों विधायकों को पार्टी का व्हिप जारी किया गया और सभी ने उसके अनुरूप आचारण किया है. हाईकोर्ट में दायर याचिका में बागियों ने तर्क दिया है कि राज्यसभा चुनाव में संविधान की 10वीं अनुसूची लागू नहीं होती है. इस अनुसूची के तहत सदन के भीतर सदस्यों की गतिविधि पर ही अमल हो सकता है. स्पीकर ने इस अनुसूची के तहत कार्रवाई कर संविधान का उल्लंघन किया है. बागियों के अनुसार विधायकों पर कर्रवाई करने में भेदभाव बरता गया है. राज्यसभा चुनाव में जदयू के 14 विधायक निर्दलीय उम्मीदवारों के प्रस्तावक बने. पहले प्रस्तावक गजानंद शाही थे. इनके अलावा रेणु कुशवाहा और दाउद अली भी प्रस्तावक बने थे. इसके बावजूद सिर्फ ज्ञानू, रवीन्द्र, नीरज बबलू और राहुल पर कार्रवाई हुई. विधायक रेणु कुशवाहा, अन्नू शुक्ला और पूनम देवी यादव ने लोकसभा चुनाव में जदयू का खुलकर विरोध किया था. रेणु ने नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर मधेपुरा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया. अन्नू ने जदयू से इस्तीफा देकर वैशाली से लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा जबकि पूनम ने खगड़िया में राजद प्रत्याशी के लिए प्रचार किया था. यह सरासर दलबदल का मामला था, लेकिन तीनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. पूर्व विधायक की सुविधा संविधान के माध्यम से मिलती है. सदस्यता समाप्त करने के क्रम में स्पीकर ने पूर्व विधायक वाली सुविधा छीनकर संविधान का उल्लंघन किया है. दूसरी तरफ मंत्री पीके शाही ने कहा कि विधानसभा के स्पीकर के फैसले पर हाईकोर्ट में भी सीमित दायरे में सुनवाई हो सकती है. ऐसे फैसलों को कोर्ट में सिर्फ प्रतिक्रियात्मक त्रुटियों के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि स्पीकर ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए चारों विधायकों को बर्खास्त किया है. इस वजह से उन्हें सिर्फ 15वीं विधानसभा के सदस्य के नाते पूर्व सदस्य वाली कोई सुविधा नहीं मिलेगी. मंत्री ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में विधायकों के आचरण से साफ था कि वे जदयू में नहीं रहना चाहते हैं. इस वजह से इन पर संविधान की 10 वीं अनुसूची लागू होती है. स्पीकर की कार्रवाई को सदन के भीतर की घटना पर हुई कार्रवाई माना जाएगा. मंत्री ने कहा कि दल के सदस्य नीतियों और सिद्धांतों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन पार्ट में आस्था व्यक्त करने पर उनके साथ नरमी की जाती है. यह पार्टी का अधिकार है कि वह किस पर कार्रवाई करती है और किसे माफ कर देती है? अदालत अब जो भी निर्णय ले पर यह तय है कि जदयू के अंदर अब आर-पार की लड़ाई शुरू हो गई है और यह लड़ाई जदयू की सेहत के लिए किसी भी हाल में अच्छी नहीं है.■

feedback@chauthiduniya.com

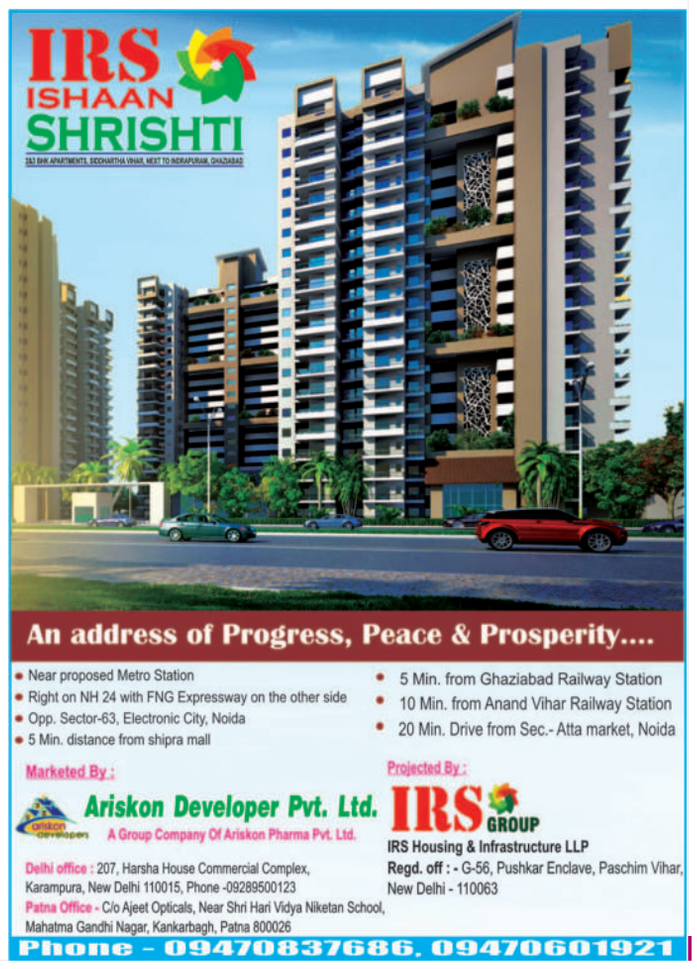

एक नज़र

स्वच्छता पर संगोष्ठि

राम लाल उच्च विद्यालय हरिपुर डाक से स्कूल चौक तक सफाई अभियान विगत दिन चलाया गया. इस अभियान में पंचायत के मुखिया प्रवीण कुमार, सरपंच महेन्द्र प्रसाद भगत, उमर अली, सदानंद मेहता, विनोद कुमार तिवारी एवं स्कूल के दर्जनों छात्र-छात्राओं ने भाग लिया. मौके पर द्विजदेनी चेतना समिति के संस्थापक श्री तिवारी ने पूज्य बापू (महात्मा गांधी) के संदेश- 'स्वच्छता ही पवित्रता है' पर बोलते हुये कहा कि हमारा घर बाहर दोनों जगह हमेशा साफ रहे, वातावरण स्वच्छ रहे तभी हमारा तन और मन भी स्वस्थ रह सकता है अर्थात स्वच्छ वातावरण में ही पवित्रता है. अन्य वक्ताओं ने कहा आज भी समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेशकीमती गाड़ी, मोबाइल, टी.वी, रखते हैं मगर स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं. ऐसे कुछ लोग हैं जो जान बूझकार सड़कों एवं प्लेटफार्मों को भी गंदा किया करते हैं. गंदगी फैलाने में उन्हें आनंद आता है जिसको कड़ाई से रोका जाना चाहिये. अत: स्वच्छ वातावरण हम सब रखें ताकि स्वस्थ तन में मन भी स्वस्थ रहें. पूज्य बापू की तरह हीं हम सबों को अपने घर और दरवाजा की सफाई खुद झाड़ू लेकर करनी चाहिये अन्यथा विभिन्न तरह की बीमारी से समाज भी अस्वस्थ हो जायेगा.

-अमित ठाकुर

याद किये गये साहित्यकार

इंद्रधनुष साहित्य परिषद फॉरबिसगंज के तत्वावधान में साहित्यकारों को स्मृति समारोह में याद किया गया. समारोह की अध्यक्षता कर्नल अजित दत्ता ने किया. सर्वप्रथम हिन्दी सेवी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉ. राम विलास शर्मा, कृसन चंदर, गौरापंत के बारे में वक्ताओं में कर्नल दत, मांगन मिश्र, हेमंत यादव, डॉ. अनुज प्रभात, विनोद कुमार तिवारी, हर्ष नारायण दास, दिलीप समदर्शी, उमाकांत दास, रणविजय यादव, रवींद्र कुमार यादव एवं प्रो. परमेश्वर प्रसाद साह ने बताया की पुरुषोत्तम दास हिन्दी विद्यापीठ हिन्दी साहित्य सम्मेलन, हिन्दी रक्षक दल हिन्दी प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे. वहीं डॉ. शर्मा ने प्रेमचंद, निराला, भारतेन्दु पर कई आलोचनात्मक पुस्तकें लिखीं.

जारी है स्वच्छता अभियान

प्रजापिता ब्रहमाकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय शाखा फारबिसगंज के तत्वावधान में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत' संकल्प के तहत सशस्त्र सीमा बल(एसएसबी) 56वीं वाहिनी बथनाहा के साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया. इसका नेतृत्व ओम शांति केंद्र की संचालिका ब्रहमाकुमारी रूकमा दीदी एवं सेनानायक बी एस डोंगरा ने किया. इस कार्य में नगर परिशद् की मुख्य पार्शद वीणा देवी एवं पार्शद राजकुमार अग्रवाल के द्वारा अपने स्तर पर भरपूर सहयोग दिया गया.

-अजातशत्रु अग्रवाल

सीतामढ़ी

रून्नीसैदपुर में बिछ गई चुनावी शतरंज की बिसात

2015 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी इस क्षेत्र से भाग्य आजमाने को कई नये चेहरे आतुर हैं. चर्चा है कि पूर्व विधायक के करीबी रिश्तेदार आलोक कुमार चौधरी उर्फ पिंटू द्वारा आयोजित प्रतिमा अनावरण समारोह अपरोक्ष रूप से चुनावी तैयारी का ही हिस्सा है. जबकि पूर्व से इस क्षेत्र के अलावा रीगा विधानसभा क्षेत्र पर पैनी राजनीतिक नजर रखने वाले अपराध जगत से जुड़े संतोष झा भी अबकी बार चुनावी समर में ताल ठोंकने को तैयार हैं. हालांकि अब तक यह बात सामने नहींआयी हैं कि वे किस दल से चुनाव में अपनी दावेदारी लेकर आयेंगे, लेकिन प्रतिमा अनावरण समारोह के मौके पर उनके समर्थकों द्वारा जगह-जगह लगाया गया तोरण द्वार व कट आउट से साफ हो गया है कि रून्नीसैदपुर सीट पर उनकी नजर आकर टिक गयी है.

वाल्मीकि कुमार

सीतामढ़ी जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान चढ़ना शुरू हो गया है. पिछले तकरीबन 6 महीने से संभावित प्रत्याशियों की चहल-कदमी से आम लोग अचंभित हो रहे हैं. सीतामढ़ी जिले का रुन्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र इन दिनों काफी चर्चा में है. इससे पूर्व के चुनावों में भी यह क्षेत्र नये लोगों के लिए राजनीति का परीक्षा का केंद्र रहा है. बताते चलें कि वर्ष 1952 से लेकर 1984 के बीच पांच बार बतौर विधायक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व विधायक स्व. विवेकानंद गिरी जिले की राजनीति में अब भी एक आदर्श के रूप में है. इस क्षेत्र से त्रिवेणी प्रसाद सिंह, भोला राय, नवल किशोर शाही सरीखे नेता को बतौर विधायक प्रतिनिधित्व का मौका मिलता रहा है. वर्तमान में जदयू की गुड्डी देवी लगातार दूसरी बार प्रतिनिधित्व कर रही हैं. 2015 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी इस क्षेत्र से भाग्य आजमाने को कई नये चेहरे आतुर है. चर्चा है कि पूर्व विधायक के करीबी रिश्तेदार आलोक कुमार चौधरी उर्फ पिंटू द्वारा आयोजित प्रतिमा अनावरण समारोह अपरोक्ष रूप से चुनावी तैयारी का ही हिस्सा है. जबकि पूर्व से इस क्षेत्र के अलावा रीगा विधानसभा क्षेत्र पर पैनी राजनीतिक नजर रखने वाले अपराध जगत से जुड़े संतोष झा भी अबकी बार चुनावी समर में ताल ठोंकने को तैयार हैं. हालांकि अब तक यह बात सामने नहीं आयी है कि वे किस दल से चुनाव में अपनी दावेदारी लेकर आयेंगे, लेकिन प्रतिमा अनावरण समारोह के मौके पर उनके समर्थकों द्वारा जगह-जगह लगाया गया तोरण द्वार व कट आउट से साफ हो गया है कि रुन्नीसैदपुर सीट पर उनकी नजर आकर टिक गयी है. वैसे चुनाव में अभी वक्त है, आने वाले समय में वे रीगा अथवा रुन्नीसैदपुर में से किस सीट को अपने लिए सुगम अखाड़ा मानते है इन पर निर्भर करता है.

अब एक नजर आयोजित कार्यक्रम पर डालने की आवश्यकता है. वैसे तो प्रतिमा अनावरण समारोह को पूर्णत: गैर राजनीतिक कार्यक्रम बताया गया, परंतु समारोह के अवसर पर स्व. महंत विजयानंद गिरी उच्च विद्यालय के प्रांगण में आयोजित सभा में लोजपा नेता चिराग पासवान ने जहां केंद्र सरकार की वाह-वाही की वही राज्य सरकार को जन विरोधी की संज्ञा देने से भी परहेज नहीं किया. परमानंद गिरी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में चिराग ने युवाओं को खास तौर पर बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए एकजुट होने की अपील की. कहा कि अब वक्त आ गया है सही प्रतिनिधि का चयन करने का जिसमें युवाओं की अहम भागीदारी से इंकार नही किया जा सकता है. चिराग ने राजद गठबंधन पर चुनावी प्रहार करते हुए कहा कि बिहार में सुशासन व विकास का दावा खोखला साबित होकर रह गया है. जाति, धर्म व मजहब के नाम पर समाज को बांटने का काम किया गया है. नतीजा है कि भाईचारा के साथ बिहार से विकास भी गायब होकर रह गया है. बलवंत शास्त्री ने लोगों से महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में भी सरकार बदलने की अपील की. पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने बिहार में विकास का ढिंढोरा पीटने के साथ ही डॉक्टरों का हाथ काट लेने जैसी बात करने वाली सरकार को बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया. केंद्र की तरह बिहार में भी नई सरकार बनाने की अपील करते हुए कहा कि किसानों के समस्या का निदान सरकार बदलने से ही संभव है. पूर्व विधायक नवल किशोर शाही ने स्व. विवेकानंद गिरी के व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला. लोजपा जिलाध्यक्ष मोहन झा, मनोज जी, गुंजन श्रीवास्तव, आनंद मधुकर, वशिष्ठ मिश्रा, शिवेष कुमार सिंह, भाजपा नेता विश्वजीत पाठक समेत अन्य के साथ लोजपा नेताओं ने पूर्व विधायक स्व. गिरी के आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया, जहां स्थानीय जदयू विधायक गुडडी देवी ने भी माल्यार्पण की.

कार्यक्रम आयोजन से साफ हा गया है कि रून्नीसैदपुर में चुनावी शतरंज की बिसात अब बिछ गई है. देखना है कि आने वाले दिनों में चुनावी अभियान को कौन कितना रेस लगा पाता है. वैसे गठबंधन की चल रही राजनीति के कारण फिलहाल यह मामला अधर में है कि जदयू के कब्जा वाले इस सीट पर विरोधी भाजपा गठबंधन किस दल के पाले में इस सीट को डालता है.

feedback@chauthiduniya.com

गठबंधन की राजनीति बिगाड़ रही खेल

भाजपा-जदयू के आपसी तालमेल को लेकर सीतामढ़ी जिले की कुल 8 विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में एनडीए ने बाजी मार ली थी. इसे राजनीतिक दलों की सफलता मानें या मतदाताओं की सूझ-बूझ कि गठबंधन के दोनों ही दलों अर्थात जदयू व भाजपा को बराबर की हिस्सेदारी मिली. यानि की कुल 8 में से 4 सीट जदयू तो 4 सीट भाजपा को हाथ लगी. इसी बीच गठबंधन के दोनों दल के बीच उत्पन्न राजनीतिक खाई ने दोनों को एक दूसरे से अलग खड़ा कर दिया. इतना ही नहीं हालात ऐसे बने कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू व भाजपा ने आमने-सामने का चुनावी मुकाबला भी किया. परंतु देश में चली नमो आंधी के कारण भाजपा को सफलता मिली तो जदयू को राजनीति के अखाड़े में एक दांव सीखने का वक्त मिला. अब बारी है विधानसभा चुनाव की. इसमें भाजपा की नैया एक बार फिर आसानी से पार लगेगी अथवा जदयू के राजनीतिक पैतरे में उलझ जाएगी, फिलहाल कहना मुश्किल प्रतीत हो रहा है. इस बीच अर्से से राजनीतिक चौखट पर दस्तक देने वाले कई दलों के संभावित प्रत्याशियों के लिए दलों का राजनीतिक गठबंधन सरदर्द साबित होने लगा है...

सूबे बिहार में विकास व सुशासन के नाम पर लालू प्रसाद की राजद सरकार की दुनिया उजाड़ कर नया आशियाना बनाने में कामयाब रहने वाली नीतीश कुमार की जदयू वर्तमान में राजनीतिक संकट के दौर को झेल रही है. अपनी मित्र पार्टी भाजपा की बदौलत शासन की कमान थामने वाली जदयू के लिए दोस्ती में कुश्ती महंगी साबित होकर रह गई है. नये गठबंधन के तहत जदयू ने अपने पुराने राजनीतिक शत्रु राजद व कांग्रेस से हाथ मिला कर सत्ता पर काबिज होने का अथक प्रयास किया, परंतु कोई खास सफलता हाथ नहीं लग सकी है. वहीं दूसरी ओर भाजपा राम विलास पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी व उपेंद्र कुशवाहा की नव गठित राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ मिल कर राजनीतिक बुलंदी पाने में कामयाबी पायी है. संपन्न लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद एक ओर जहां भाजपा गठबंधन अपनी सफलता पर फिलगुड का एहसास कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जदयू गठबंधन आगामी विधान सभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को शिकस्त देने की फिराक में लगी है. इसी कड़ी में यात्राओं का दौर चलाने वाले जदयू के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर यात्रा के जरीये आम लोगों तक पहुंचने की योजना बनायी है. नवंबर माह के दूसरे सप्ताह में सीतामढ़ी में प्रस्तावित नीतीश कुमार की संपर्क यात्रा की सफलता को लेकर जिले में पार्टी कायकर्ताओं की राजनीतिक चहल कदमी बढ़ गयी है. इसमें वर्तमान से लेकर पूर्व तक के पार्टी नेता व कार्यकर्ताओं की पलटन शहर से लेकर गांव तक के लोगों के बीच कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील भी करने लगे हैं. बताया जाता है कि लोगों के बीच बिहार के विकास के लिए एक बार पुन: नीतीश कुमार को शासन की कमान सौंपने में भागीदारी की अपील भी की जा रही है. आम जनता पर पार्टी की अपील का असर कितना पड़ सकता है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा. परंतु इतना तो जरूर है कि फिलहाल जदयू अपनी पूरी ताकत भाजपा को बिहार की राजनीति से अलग रखने में लगा रही है.

अब एक नजर सीतामढ़ी में भाजपा व जदयू पर डालने की जरूरत है. सीतामढ़ी जिले की कुल 8 विधानसभा में से 4-4 सीट पर भाजपा व जदयू का कब्जा है. इनमें सीतामढ़ी नगर से भाजपा के सुनील कुमार पिंटू, परिहार से राम नरेश प्रसाद यादव, रीगा से मोतिलाल प्रसाद तो बथनाहा सुरक्षित क्षेत्र से भाजपा के दिनकर राम बतौर विधायक हैं. वहीं जदयू से बेलसंड में सुनीता सिंह चौहान, रुन्नीसैदपुर में गुड्डी देवी, बाजपट्टी में गन्ना विकास मंत्री डॉ. रंजू गीता व सुरसंड से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शाहिद अली खान बतौर विधायक हैं. दोनों ही दलों के कब्जे वाली इन सीटों पर अबकी बार कई नये चेहरों की नजरें टिकी है. एक ओर कई नये व पुराने चेहरे अपना भाग्य आजमाने की फिराक में लगे हैं तो दूसरी ओर राजनीतिक गठबंधन की फांस से कई के अरमान पर पानी फिरता नजर आने लगा है. चल रही चुनावी चर्चाओं पर गौर करे तो भाजपा अथवा जदयू के कब्जे वाली सीटों पर हेरा-फेरी के बीच कुछ संभावित प्रत्याशी अपना भविष्य देख रहे हैं. राजनीतिक जानकारों की मानें तो दोनों ही दल अपने-अपने कब्जे वाली सीटों पर अगर हेरा-फेरी करती है तो पार्टी के अंदर कलह की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. वहीं दूसरी ओर अबकी बार होने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन की राजनीति बगैर हेरा-फेरी के संभव नहीं लग रही है. कारण कि जदयू का राजद व कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ गठबंधन है. ऐसी स्थिति में गठबंधन दल को सीट से वंचित नहीं किया जा सकता है. जदयू अपने कब्जे वाली चार सीट के अलावा भाजपा के कब्जे वाली शेष चार सीटों पर निशाना साध सकती है. इसमें एक बथनाहा सुरक्षित सीट को छोड़ भी दिया जाये तो तीन सीट ही जदयू के पास अतिरिक्त नजर आ रही है. अब इस पर सहयोगी दलों की गुंजाईश की जाती है अथवा नये तरीके से सीटों का बंटवारा किया जायेगा इस पर सभी की नजरे टिकी हैं. यही हाल कमोवेश भाजपा के साथ भी है. भाजपा भी अपने कब्जे वाली चार सीटों के अलावा जदयू के कब्जे वाले चार सीट पर सहयोगी दल लोजपा व रालोसपा की गुंजाईश कर सकता है. अगर बराबरी की नौवत आयी तो भाजपा को भी अपनी पुरानी हवेली की रिमोल्डिंग की आवश्यकता पड़ सकती है.

वैसे चुनाव में अभी करीब एक साल का वक्त है. बावजूद इसके अभी से ही संभावित प्रत्याशियों का चुनावी दौर शुरू हो गया है. गठबंधन के बावजूद तकरीबन सभी दलों से संभावित प्रत्याशियों का चुनावी बाजार सजने लगा है. सभी का मुंह फिलहाल खुल नही रहा है कि वे दल से प्रत्याशी हो सकते है. कारण कि उनकी सोच है कि अगर पार्टी गठबंधन के पाले में सीट आ गयी तो मौका मिल सकता है. अगर नहीं तो गठबंधन धर्म का पालन उनकी विवशता होगी. ऐसी स्थिति में वे खुद को उजागर करना नहीं चाह रहे हैं. सूबे की गठबंधन राजनीति के कारण कई पुराने व नये चेहरे अपनी राजनीतिक मंशा को दबाए पार्टी दफतरों से लेकर नेताओं का परिक्रमा करने में लग गये है. अब देखना है कि चुनाव तक राजनीतिक गठबंधन रहती है अथवा नये चुनावी समीकरण के तहत विधानसभा चुनाव का आगाज किया जाता है.

– वाल्मीकि कुमार

बेतिया

भारत-नेपाल सीमा पर खाद तस्करी

भारतीय किसानों का कहना है कि नेपाल में खाद पर नेपाल सरकार द्वारा सब्सिडी नहीं दी जाती है, जिस कारण नेपाल में खाद मंहगी बिकती है. नेपाल के रासायनिक खादों के अपेक्षा भारतीय खाद सस्ती बिकती है. भारतीय सीमा स्थित बाजारों में यूरिया तीन सौ सत्तर से चार सौ तक बिकती है. डीएपी बारह सौ तक बिकती है. वहीं नेपाल के बाजारों में जब यह खाद पहुंचती है ,तो यूरिया का दाम छ: सौ से आठ सौ तक, डीएपी का दाम अठारह सौ से उन्नीस सौ तक हो जाता है. जो नेपाली खाद के अपेक्षा सस्ती पड़ती है. नेपाल और भारत के व्यापारियों के लिए जहां मुनाफे का धंधा हो रहा है. वहीं भारतीय किसानों को महंगे दाम में खाद खरीदकर आर्थिक मार की सहन करनी पड़ रही है.

अरविन्दनाथ तिवारी

इन दिनों भारत-नेपाल सीमा पर भारतीय रासायनिक खादों की तस्करी परवान पर है. रासायनिक खादों की खरीददारी के लिए भारतीय किसान को जहां किल्लत के साथ टकटकी लगानी पड़ रही है. वहीं खाद तस्करी भारत-नेपाल व्यापारियों के लिए अधिकतम मुनाफे का धंधा बन गया है. व्यापारियों के आर्थिक मुनाफे के धंधे में जहां देश को राजस्व की क्षति उठानी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय किसानों की आर्थिक रीढ़ चरमरा रही है. जानकारी के मुताबिक रक्सौल के आदापुर, नरकटियागंज तक जोड़ने वाले भारत-नेपाल ग्रामीण रास्तों से दिन या रात में खादों की तस्करी की जा रही है. साइकिल, तांगे, टेम्पो से भारतीय खाद यूरिया, डीएपी लाद कर नेपाल के बाजारों तक पहुंचाया जा रहा है. भारतीय किसानों का कहना है कि नेपाल में खाद पर नेपाल सरकार द्वारा सब्सिडी नहीं दी जाती है, जिस कारण नेपाल में खाद महंगी बिकती है. नेपाल के रासायनिक खादों के अपेक्षा भारतीय खाद सस्ता बिकता है. भारतीय सीमा स्थित बाजारों में यूरिया तीन सौ सत्तर से चार सौ तक बिकता है. डीएपी बारह सौ तक बिकता है. वहीं नेपाल के बाजारों में जब यह खाद पहुंचती है ,तो यूरिया का दाम छ: सौ से आठ सौ तक, डीएपी का दाम अठारह सौ से उन्नीस सौ तक हो जाता है. जो नेपाली खाद की अपेक्षा सस्ती पड़ती है. नेपाल और भारत के व्यापारियों के लिए जहां मुनाफे का धंधा हो रहा है. वहीं भारतीय किसानों को महंगे दाम में खाद खरीदकर आर्थिक मार की सहन करनी पड़ रही है. आदापुर, लोहडिया, कनुनिया, कटगेनवा, बगही, बखतौरा आदि विभिन्न गॉवों के रास्तों के जरिए नेपाल तक भारतीय खादों की तस्करी इन दिनों की जा रही है. खादों की तस्करी होना यहां के लिए कोई नयी बात नहीं है. जब अच्छे पदाधिकारियों का आगमन होता है, तो तस्करी पर लगाम लग जाता है,वरन तस्करी जारी रहता है. किसान यहां बताते हैं कि एक दशक पूर्व बगहा के पुलिस अधीक्षक रतन संजय एक रासायनिक खाद भंडार पर छापामारी कर के नेपाल जा रहे लोड्ड ट्रक और दुकान के मालिक को जेल भेजा था. इस कार्यवाही से पुरे खाद के दुकानदारों और तस्करों में हड़कम्प मच गया था. इस कार्यवाही से बहुत दिनों तक तस्करी पर लगाम लगा था.

feedback@chauthiduniya.com

आंगनबाड़ी केन्द्र का दावा खोखला

बिहार सरकार का यह दावा है कि बिहार में आंगनबाड़ी केन्द्रों को सुसज्जित किया जायेगा, पर यह दावा पश्चिम चम्पारण जिला के रामनगर प्रखण्ड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ध्वस्त होता नजर आ रहा है. प्रखण्ड स्थित 158 केन्द्रों में आधे से अधिक केन्द्रों को अब भी भवन नसीब नहीं हो पाया है. रामनगर शहरी क्षेत्र में 32 केन्द्रों में 28 अब भी भवन विहीन है. सूत्रों का कहना है कि त्रयोदश योजना की राशि से अब तक सबका निर्माण हो जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हो सका है. सूत्रों का कहना है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए सरकार से त्रयोदश योजना से राशि की उपलब्धता करा दी गयी है. जो प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए था,जो अब तक नहीं हो सका है. आलम यह है किसी-किसी केन्द्र पर निर्माण कार्य आधा- अधूरा दिखाई पड़ रहा है. जिस कारण कई केन्द्र किराये के भवन में संचालित होते दिखाई दे रहें है.जहां पर पक्के किराये का भवन उपलब्ध नहीं है वहां पर केन्द्र झोपड़ी में चलाया जा रहा है. आधे - अधूरे निर्माण ,झोपड़ी के भवन होने के कारण बच्चों को शौच और पानी पीने का कष्ट अधिकतर केन्द्रों पर उठाना पड़ रहा है. दोनों क्षेत्र का कर महिया पंचायत सुविधा युक्त है. यह क्षेत्र भवन के मामलें में बाजी मार लिया है. आंगनबाड़ी भवन के अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के सन्दर्भ में प्रखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रतिमा वर्मा का कहना है कि भवन के सम्बन्ध में उच्चस्तरीय पदाधिकारियों के पास प्रतिवेदन भेजा गया है. कार्रवाई की दिशा प्राप्त होते ही कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी.खाद के हो रहे तस्करी पर बेतिया जिले के कृषि पदाधिकारी का कहना है कि देखिए सूचना मिलने पर धर पकड़ की जाती है. इस पर अंकुश लगाया जायेगा.

शॉर्ट न्यूज

निरक्षरता समाज का कलंक

राम लाल उच्च विद्यालय हरिपुर डाक में लोक शिक्षा समिति शाखा हरिपुर पंचायत केन्द्र एवं द्विजदेनी पुस्तकालय फॉरबिसगंज के संयुक्त तत्वावधान में 'निरक्षरता समाज का कलंक है' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता मुखिया प्रवीण कुमार ने की. सर्वप्रथम पुस्तकालय संचालक विनोद कुमार तिवारी ने समारोह में एक साक्षरता गीत -'कहे समय का इक तारा फैले शिक्षा का उजियारा, अक्षर-अक्षर दीप जले फैले शिक्षा का उजाला' पढ़ लिख बने होशियार, समझ बढ़े तो बढ़े विचार, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करे जतन प्रस्तुत किया. फिर रूबी प्रवीण, अखतरी खातून, नुसरत प्रवीण, शहनाज, नेहा, प्रवीण, चांदनी, काजल आदि ने शिक्षा पर कई कविताओं का पाठ किया. मौके पर दर्जनों छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन पुरस्कार भी अतिथियों के कर कमलों से प्रदान किया गया.

-अमित ठाकुर

लौह पुरुष की जयंती

+2 अकादमी फारबिसगंज में विद्यालय परिवार की ओर से लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एकता दिवस के रूप में मनाई गई है. सभी की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य शिवनारायण दास ने की. विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों ने लौह परुष के तैल्य चित्र पर पुष्प अर्पित किया. इस अवसर पर प्राचार्य श्री दास ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की महान हस्ती थे. वे कर्मठ, ईमानदार, आदर्शवादी व अहिंसावादी थे. हमें इनसे सीख लेनी चाहिये. शिक्षक प्रमोद कुमार दास ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया. इनके ही प्रयत्नों का परिणाम है कि आज भारत एक संघ के रूप में प्रगतिशील है. शिक्षक जयनारायण साह, हरिशंकर झा, मोहन कुमार झा, प्रवीण कुमार ने कहा कि आज का दिन पूरा देश इनके सम्मान में दौड़ रहा है.

- अजातशत्रु अग्रवाल

अंगीभूत कॉलेजों को कब मिलेगा स्थायी प्राचार्य?

सुनील सौरभ

गया

पिछले पांच वर्षों से मगध विश्वविद्यालय में अराजकता की स्थिति कायम है. पहले स्थायी कुलपति नियुक्त नहीं किए जाने से विश्वविद्यालय की स्थिति अराजक हुई थी और अब स्थायी कुलपति नियुक्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय द्वारा मगध विष्वविद्यालयों के अंगीभूत कॉलेजों के प्राचार्यो की नियुक्ति दो-दो बार रद्द कर देने से यहां की स्थिति बिगड़ गई है. मगध विष्वविद्यालय बोधगया के अंगीभूत कॉलेज जहां के पदस्थापित प्राचार्य की नियुक्ति रद्द कर दी गई है वहां पर इन्हीं से कामचलाउ प्राचार्य के रूप में काम लिया जा रहा है. नतीजा यह है कि ऐसे कॉलेज के प्राचार्य कॉलेज के विकास में कम लूट सको सो लूट की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं.

मगध विश्वविद्यालय बोधगया में अराजकता वर्षों से कायम है. फर्जी डिग्री, फर्जी नियुक्ति के लिए यह पहले से हीं चर्चित रहा है. इन दिनों विष्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज के प्राचार्यो की नियुक्ति के कई माह बाद भी यह मामला चर्चा में है. मगध विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों के प्राचार्यो की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायत पर उच्च न्यायालय पटना ने पूर्व नियुक्ति प्राचार्यो की नियुक्ति को रद्द करते हुए पुन: बहाल करने व नये प्राचार्य बहाल होने तक पुराने प्राचार्य से काम लेने का आदेश दिया है. विश्व विद्यालय प्रशासन इसी आदेश का फायदा उठा रहा है. विश्व विद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में स्थायी प्राचार्यो की नियुक्ति नहीं कर कामचलाउ प्राचार्य से हीं काम लिया जा रहा है.

बिहार में कथित जंगल राज के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार ने बिहार में बिगड़ी व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया था. इसी दौर में मगध विष्व विद्यालय बोधगया में डॉ. वीरेंद्र नाथ पाण्डेय ने कुलपति का कार्य भार संभाला था. वे मगध विष्वविद्यालय में पूर्व से व्याप्त अराजक स्थिति को देखकर थोड़ा विचलित हुए. लेकिन धीरे-धीरे वीएन पाण्डेय ने विश्वविद्यालय के बिगड़ी व्यवस्था को पटरी पर ला दिया. परंतु कार्यकाल के अंतिम समय में किए गये प्राचार्यो की बहाली में वे भी कठघरे में खड़ा हो गये. जून 2009 में मगध विश्व विद्यालय के 44 अंगीभूत कॉलेजों में 22 प्राचार्यो की नियुक्ति की गई. इस नियुक्ति में बड़े पैमाने पर अनियमितता किए जाने का आरोप लगा. साक्षात्कार के बाद प्राचार्यो की नियुक्ति की जो लिस्ट जारी की गई इसे देखकर लोगों को आष्चर्य हुआ. मूटा के महासचिव तथा मगध विष्वविद्यालय सीनेट सदस्य के लिए निर्वाचित शिक्षक डॉ. व्रजेश राय ने इस बहाली के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में रिट दायर कर दिया. हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया. प्राचार्य बहाली में गड़बड़ी पाये जाने के बाद इसे रद्द कर छह महीने के अंदर नये स्तर से प्राचार्य नियुक्ति करने का आदेश दिया. तब तक डॉ. वीएन पाण्डेय का कार्यकाल समाप्त हो चुका था. प्रभारी कुलपति के रूप में आये डा. अरूण कुमार ने इस मौके का लाभ उठाते हुए हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में 22 प्राचार्यो की नियुक्ति कर दी. इसमें नौ ऐसे प्राचार्य की नियुक्ति हुई जो पहली नियुक्ति में शामिल थे. प्राचार्य बहाली की कमेटी में कुलपति डा. अरूण कुमार के अलावा कुलाधिपति के प्रतिनिधि डॉ. शिवयतन ठाकुर, डॉ. रमेश पाण्डेय, गया कॉलेज गया के तत्कालीन प्राचार्य डॉ. श्रीकांत शर्मा, सुरेंद्र ब्रम्हचारी, विक्टर तिग्गा शामिल थे. इस बहाली में भी बड़े पैमाने पर अनियमितता की शिकायत आयी. कमेटी के तीन सदस्य डॉ. शिवयतन ठाकुर, डॉ. रमेश पाण्डेय, तथा विक्टर तिग्गा ने यहां तक कहा कि नियुक्ति लिस्ट में उनका हस्ताक्षर फर्जी है. इसी के बाद मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया. हाई कोर्ट ने पुन: इस नियुक्ति को रद्द करते हुए छह माह के अंदर नई नियुक्ति करने का आदेश दिया. हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि नये प्राचार्य की नियुक्ति होने तक वे कामचलाउ प्राचार्य के रूप में काम करेंगे. कामचलाउ प्राचार्य यह मानते हुए की अगली बार मुझे प्राचार्य के पद पर नियुक्ति होगी या नहीं यह मान कर कॉलेज के फंड को वारा-न्यारा करने में लगे हुए हैं. बताया जाता है कि प्राचार्यो की बहाली की जांच बिहार सरकार के निगरानी विभाग कर रही है. सूत्रों का कहना है कि 22 में से 12 प्राचार्यो के मैट्रिक से लेकर पीजी तक के प्राप्तांक गलत तथा शोध पत्र फर्जी पाये गये हैं. जिसमें शमसुल इस्लाम तथा आनंद कुमार प्रमुख हैं. शमसुल इस्लाम ने तो निगरानी के पदाधिकारियों के समक्ष स्नातक पास कोर्स से करने की बात भी स्वीकार की है. ऐसा सूत्रों का कहना है. बावजूद इसके मगध विश्वविद्यालय के कुलपति शमसुल इस्लाम पर कार्रवाई करने के बदले अन्य जिम्मेदारी देते जा रहे हैं.

नियमत: गलत प्राप्तांक और नकली शोध पत्र प्रस्तुत करने के आरोप में ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं किये जाने पर लोगों को आश्चर्य हो रहा है. वहीं दूसरी ओर डॉ. शिवयतन ठाकुर द्वारा इस मामले में कुलपति के साथ-साथ कुलसचिव पर भी मुकदमा करने की बात कही जा रही है. कुल सचिव डॉ. डीके यादव का कहना है कि इस मामले में कुलसचिव की कोई भूमिका नहीं रहती है. प्राचार्य बहाली के बाद जो सूची मिलती है, कुलसचिव इस सूची में शामिल लोगों को सूचना देकर योगदान कराते हैं. गौर करने की बात यह है कि इन सारी परिस्थितियों का खामियाजा यहां के छात्र-छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है. समय पर पढ़ाई, समय से परीक्षा नहीं होना, परीक्षा होने के बाद समय से रिजल्ट नहीं निकलना, रिजल्ट में गड़बड़ियां, गड़बड़ियों में सुधार के लिए विश्वविद्यालय का चक्कर लगाना, रिजल्ट ठीक रहने पर डिग्री के लिए परेषानी... मतलब हर हाल में छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ती है. अब सवाल यह है कि मगध विष्व विद्यालय बोधगया को इस माहौल से कौन इवारेगा? कब तक गड़बड़ी करते रहेंगे कुलपति? आखिर निष्पक्ष बहाली कब होगी?

feedback@chauthiduniya.com

> छात्र समागम के जिलाध्यक्ष गौरव सिंह, एआईएसएफ के अमीन हामजा, रूपक कुमार सहित छात्रा लोजपा, आइसा एवं एसएफआई के जिलाध्यक्षों ने बेगूसराय में विश्वविद्यालय स्थापना की मांग को सड़क से विधान सभा तक जारी रखने की घोषणा किया है.
> छात्रों की इस मांग को राजनेता, जनप्रतिनिधि, अधिवक्ता, सामाजिक, संगठन, राजनीतिक दलों का व्यापक समर्थन प्राप्त है.

बेगूसराय

दिनकर के नाम पर बने विश्वविद्यालय

बेगूसराय जिले के सभी अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के नियंत्रणाधीन हैं. कॉलेजों एवं छात्रों की संख्या काफी होने तथा दरभंगा की दूरी अधिक होने के कारण छात्रा-छात्राओं एवं अभिभावकों को सर्वाधिक कठिनाई हो रही है. पढ़ाई, विधि व्यवस्था, छात्रा कल्याण एवं विकास कार्यो पर युनिवर्सिटी का समुचित नियंत्रण नही रह पाने से कॉलेजो में अराजकता का माहौल कायम होते जा रहा है. युनिवर्सिटी की निगरानी के अभाव में कई कॉलेज तो सिर्फ छात्रों के नामांकन एवं परीक्षा-फॉर्म भरवाने का केन्द्र बनकर रह गए हैं. न छात्र पढ़ने को तैयार हैं और न शिक्षक पढ़ाने को. अराजकता से दोनों वर्ग प्रभावित है. छोटी-छोटी समस्याओं के निदान के लिए छात्रों को दरभंगा के चक्कर लगाना पड़ता है और अभिभावकों की गांठ ढीली होती है.

सुरेश चौहान/पंकज झा

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर बेगूसराय में विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग को लेकर छात्र संगठनों की मांग तूल पकड़ने लगी है. छात्रों की इस मांग को शिक्षाविदों, अभिभावकों, अधिवक्ताओं, जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों एवं आमजनों का व्यापक समर्थन मिलने लगा है. छात्र संगठन एनएसयूआई ने इस मांग के समर्थन में प्रदर्शन, धरना, अनशन एवं हस्ताक्षर अभियान चला रखा है तो एबीवीपी. धरना प्रदर्शन के साथ सांसद एवं विधायकों का घेराव अभियान चला रखा है. एआईएसएफ, छात्र समागम, छात्र लोजपा एवं आईसा भी धरना प्रदर्शन आयोजित कर रहा है.

बेगूसराय जिले के सभी अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के नियंत्रणाधीन हैं. कॉलेजों एवं छात्रों की संख्या काफी होने तथा दरभंगा की दूरी अधिक होने के कारण छात्रा-छात्राओं एवं अभिभावकों को सर्वाधिक कठिनाई हो रही है. पढ़ाई, विधि व्यवस्था, छात्रा कल्याण एवं विकास कार्यो पर युनिवर्सिटी का समुचित नियंत्रण नही रह पाने से कॉलेजो में अराजकता का माहौल कायम होते जा रहा है. युनिवर्सिटी की निगरानी के अभाव में कई कॉलेज तो सिर्फ छात्रों के नामांकन एवं परीक्षा-फॉर्म भरवाने का केन्द्र बनकर रह गए हैं. न छात्र पढ़ने को तैयार हैं और न शिक्षक पढ़ाने को. अराजकता से दोनों वर्ग प्रभावित है. छोटी-छोटी समस्याओं के निदान के लिए छात्रों को दरभंगा के चक्कर लगाना पड़ता है और अभिभावकों की गांठ ढीली होती है. कॉलेज तथा छात्र-छात्राओं की सुरक्षा, पेयजल, शौचालय, साइकिल स्टैंड, जर्जर वर्ग कक्ष, काउंटर पर शेड का अभाव एवं काफी संख्या में शिक्षकों की कमी आदि अराजकता के कुछ प्रमुख बिंदु हैं. वित्तीय स्थिति तो लूई 16वें की याद दिलाती है. जब गिरिजाघर की छत गिर जाने के बाद उसकी मरम्मत की स्वीकृति आती थी. जिले का ख्यातिप्राप्त जीडी कॉलेज बेगूसराय, एसके महिला कॉलेज बेगूसराय, एप-ीएसएम कालेज बरौनी, एसबीएसएस कॉपरेटिव कॉलेज बेगूसराय, आरसीएस कालेज मंझौल, सहित सभी कालेज यूनिवर्सिटी की इस नीति का शिकार हैं. उक्त समस्याओं का समाधन दरभंगा विश्वविद्यालय के पास नहीं है. उपर्युक्त कारणों से छात्रा-छात्राओं एवं अभिभावकों में रोष व्याप्त है और बेगूसराय को यूनिवर्सिटी बनाने की मांग को लेकर वे संघर्ष के रास्ते पर निकल पड़े हैं.

यों वर्षो से बेगूसराय को विश्वविद्यालय बनाने की मांग छात्र संगठन करते आ रहे हैं. लेकिन अब छात्रों के इस संघर्ष में समाज के सभी वर्ग जुड़ गए हैं. एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष निशांत कुमार बताते हैं कि 1992 में मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के तत्कालीन कुलपति ने घोषणा की थी कि छात्रों के व्यापक हित में जीडी कालेज, बेगूसराय में विश्वविद्यालय का उपकेन्द्र खोला जाएगा. लेकिन वह घोषणा हवाई घोषणा बनकर रह गई. वर्तमान में छात्रों की संख्या काफी बढ़ गई है और अब यहां विश्वविद्यालय की स्थापना अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है. विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वर्षों से एनएसयूआई ने चरणबद्ध अहिंसक आंदोलन चला रखा है. जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन, कॉलेज गेट पर अनशन का सिलसिला जारी है. वर्तमान में हस्ताक्षर अभियान जारी है. जिसे सभी कॉलेज के प्रधानाचार्य, प्राध्यापक, जनप्रतिनिधि, विधायक, विधानपार्षद, सांसद, व्यवसायिक संगठन एवं आमजनों का व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है. विधान पार्षद एमएम झा ने इस मांग को विधान परिषद में उठाने का आश्वासन दिया है. एबीवीपी के अजित चौधरी कहते हैं कि प्रदर्शन-धरने के बाद अब सांसद एवं विधायकों का घेराव अभियान प्रारंभ किया है. विधान पार्षद रजनीश कुमार ने विधान परिषद में इसे उठाने का आश्वासन दिया है. उन्होंने ने बताया कि नीतीश कुमार की प्रथम सरकार के मंत्री वृषिण पटेल ने जीडी कालेज के समारोह में घोषणा की थी कि जीडी कॉलेज में विश्वविद्यालय का उपकेन्द्र खोला जायेगा जो आज तक नहीं खुला. छात्र समागम के जिलाध्यक्ष गौरव सिंह, एआईएसएफ के अमीन हामजा, रूपक कुमार सहित छात्रा लोजपा, आइसा एवं एसएफआई के जिलाध्यक्षों ने बेगूसराय में विश्वविद्यालय स्थापना की मांग को सड़क से विधान सभा तक जारी रखने की घोषणा किया है.

छात्रों की इस मांग को राजनेता, जनप्रतिनिधि, अधिवक्ता, सामाजिक, संगठन, राजनीतिक दलों का व्यापक समर्थन प्राप्त है. सीपीआई के पूर्व सांसद एवं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्याध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, भाजपा सांसद डॉ. भोला सिंह, विधान पार्षद रजनीश कुमार एवं एमएम झा, जिले के विधायक अवधेश राय, ललन कुंवर, सुरेन्द्र मेहता, रामानन्द राम, श्री नारायण यादव, नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, मंजू वर्मा, भाकपा जिलाध्यक्ष गणेश प्रसाद सिंह, माकपा के पूर्व विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह एवं जिलाध्यक्ष सुरेश यादव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभय कुमार सिंह सार्जन एवं पार्टी नेता संजय कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय कुमार, माले नेता चंद्रदेव वर्मा, लोजपा जिलाध्यक्ष संजय पासवान, जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी, मेयर संजय कुमार, जदयू नगर अध्यक्ष भूमिपाल राय, अधिवक्ता अमीर सिंह, राजद जिलाध्यक्ष प्रो. अशोक कुमार यादव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष प्रकाश टिवड़ेवाल, व्यवसायी राजेन्द्र शर्मा ने छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधरी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग की है.■

feedback@chauthiduniya.com

शॉर्ट न्यूज

विद्यालय को मिला कंप्यूटर

भारतीय स्टेट बैंक भिरभैनी के शाखा प्रबंधक नितिन कुमार के द्वारा सामाजिक बैंकिंग के तहत +2 प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय बरदाहा को एक कंप्यूटर सेट प्रदान किया गया. इस अवसर पर श्री कुमार ने विद्यालय के छात्राओं से कहा कि आज कंप्यूटर का युग है इसलिए इस क्षेत्र में भी जानकारी हासिल करना महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि आज कम्प्यूटर की जानकारी नहीं रहने पर व्यक्ति अपने को अधूरा महसूस करते हैं इसलिए शिक्षा के हर क्षेत्र में कंप्यूटर की शिक्षा का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है. इस अवसर पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य दिनेशनाथ झा ने शाखा प्रबंधक को बधाई देते हुए कहा कि इससे पूर्व भी शाखा प्रबंधक के द्वारा विद्यालय को वाटर फिल्टर प्योरेट प्रदान किया जा चुका और अब श्री कुमार के द्वारा विद्यालय को कंप्यूटर प्रदान करने से छात्राओं में उत्सुकता बढ़ी है और हमें उम्मीद है कि बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करेंगें और व्यवसायिक पाठ्यक्रम भी सीखेंगे.■

– कुमार विशाल

व्रतियों के बीच वस्त्र वितरित

छठ पर्व के उपलक्ष्य में पूर्व की भांति इस साल भी भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विश्वजीत पाठक ने सीतामढ़ी जिले के सुप्पी, पुपरी व नानपुर प्रखंड के दर्जनों गांवों में सैकड़ों व्रतियों के बीच अंग वस्त्र व पूजन सामग्री का वितरण किया. साथ ही कई स्थानों पर घाटों की सफाई भी कराई. मौके पर विश्वजीत ने कहा कि सेवा ही जीवन का मूल है. इसी भावना के तहत समाज के गरीब तबकों के बीच जाकर ऐसा करते रहे है. कार्यक्रम में पूर्व उप प्रमुख नीतू राणा, राणा आकाशदीप, मुखिया राजेश बैठा, पुपरी उप प्रमुख मो. उजाले, मो. मुतुर्जा, अचल झा, भाजयुमो जिला महामंत्री रणवीर आनंद राहुल, जवाहर साह व शत्रुघ्न ठाकुर समेत अन्य थे.■

– वाल्मीकि

कवि सम्मेलन का आयोजन

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सीतामढ़ी गौशाला में 122 वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर अखिल भारतीय हास्य-व्यंग्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद राम कुमार शर्मा, भाजपा विधायक राम नरेश प्रसाद यादव, गौशाला के पदेन अध्यक्ष सह एसडीओ सदर संजीव कुमार, डीएसपी एमएन उपाध्याय, कवि मामा हाथरसी, नारायणी शुक्ला, विजय कुमार भारद्वाज, सोमदत्त व्यास समेत अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया. मौके पर सज्जन हिसारिया, प्रमोद हिसारिया, कैलाश हिसारिया, जनार्दन भारतीया, नीरज गोयनका, नरोत्तम व्यास समेत अन्य थे.■

– बृजेश

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

17 नवंबर–23 नवंबर 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश – उत्तराखंड

कमजोर दर्जाधारी हलाल

ताकतवर मंत्री बच गए

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के82 दर्जाधारी मंत्रियों पर चाबुक चलाने केबाद राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि सरकार केताकतवर मंत्रियों पर चाबुक टालने केलिए 82 बलि केबकरे चुने गए. ब्राह्मण समाज केवोट केठेकेदार बनकर एक ब्राह्मण मंत्री हेलीकॉप्टर से हवा में खूब उड़ते रहे, लेकिन वे ब्राह्मणों का वोट नहीं दिलवा पाए. इसी तरह सामाजिक न्याय रथ यात्रा का प्रमुख बनाकर गायत्री प्रसाद प्रजापति को 17 अति पिछड़ी जातियों का नेता बना दिया गया. 17 अतिपिछड़ी जातियों का तो दूर ये अपनी जाति का भी वोट सपा को नहीं दिलवा पाए.

पंकज शर्मा

उत्तर प्रदेश के 82 दर्जाधारी मंत्रियों पर कार्रवाई फिसड्डी फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर साबित हुई. इस कार्रवाई के जरिए भ्रष्ट व जन–विरोधी गतिविधियों में लिप्त ताकतवर मंत्री तो बचा लिए गए, पर शक्तिहीन बकरे हलाल कर दिए गए. पार्टी विरोधी और जन–विरोधी काम करने वाले भ्रष्ट मंत्रियों पर कार्रवाई का मसला अधर में ही लटका रह गया. समाजवादी पार्टी के 9 से 11 अक्टूबर तक लखनऊ केजनेश्वर मिश्र पार्क में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में नेताजी मुलायम सिंह यादव ने पार्टी की नीतियों का उल्लंघन कर जन–विरोधी गतिविधियों और भ्रष्टाचार में लगे मंत्रियों का मामला उठाया था. नेताजी ने कहा था कि ऐसे मंत्रियों की पूरी सूची और लिखित शिकायतें उनके पास हैं, लेकिन उन मंत्रियों पर कार्रवाई की बात गौण हो गई और राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव द्वारा उठाए गए गद्दारों का मुद्दा प्राथमिक हो गया. पार्टी प्रत्याशियों केखिलाफ काम करने वाले गद्दार नेताओं–कार्यकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई का मुद्दा रामगोपाल ने ही उठाया था और कहा था कि 85 गद्दारों को चिन्हित कर लिया गया है. अधिवेशन केबाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शक्तिहीन दर्जाधारी मंत्रियों को हटाकर मुलायम की उन शिकायतों को ढांकने की कोशिश की जिसमें शक्तिवान काबीना या राज्य मंत्रियों केगलत गतिविधियों में लिप्त होने की बात थी, लेकिन गद्दारों पर कार्रवाई की औपचारिकताएं जरूर तेज हो गईं.

लोकसभा चुनाव केबाद समीक्षा केसमय सरकार के दर्जनों मंत्रियों केविरुद्ध आवाज मुखर हुई थी. बलिया के सपा प्रत्याशी ने तो खेल कूद मंत्री नारद राय पर उन्हें हराने का सीधा–सीधा आरोप लगाया था. आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं ने काबीना मंत्री बलराम यादव व राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामआसरे विश्वकर्मा के खिलाफ आवाज बुलन्द करते हुए कहा था कि यदि शिवपाल यादव और प्रो. रामगोपाल यादव ने आजमगढ़ में मोर्चा न संभाला होता तो उनकी कारगुजारियों से मुलायम खुद चुनाव हार गए होते.

गाजीपुर में प्रदेश केऊर्जा राज्य मंत्री विजय मिश्रा पर भी उंगली उठी थी. बलिया लोकसभा के अन्तर्गत उनके बूथ पर सपा प्रत्याशियों को मात्र एक वोट मिला था. मनोज कुमार पांडेय, शंखलाल मांझी, राजा राजीव कुमार सिंह, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष ब्यास जी गोड़ आदि पर भी उंगली उठी थी, लेकिन अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. सूत्र बताते हैं कि मनोज पांडेय, नारद राय, विजय मिश्रा, शंखलाल मांझी, राजीव कुमार सिंह सहित दर्जनों मंत्री व विधायक भाजपा के टिकट से अगला चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. भाजपा केराष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से उनकी एक दो दौर की बात भी हो चुकी है.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 82 दर्जाधारी मंत्रियों पर चाबुक चलाने के बाद राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा है कि सरकार के ताकतवर मंत्रियों पर चाबुक टालने केलिए 82 बलि केबकरे चुने गए. ब्राह्मण समाज के वोट के ठेकेदार बनकर एक ब्राह्मण मंत्री हेलीकॉप्टर से हवा में खूब उड़ते रहे, लेकिन वे ब्राह्मणों का वोट नहीं दिलवा पाए. इसी तरह सामाजिक न्याय रथ यात्रा का प्रमुख बनाकर गायत्री प्रसाद प्रजापति को 17 अति पिछड़ी जातियों का नेता बना दिया गया. 17 अतिपिछड़ी जातियों का तो दूर ये अपनी जाति का भी वोट सपा को नहीं दिलवा पाए. राजनारायण बिन्द ने मछली शहर व जौनपुर में सपा का विरोध करते भाजपा की मदद की. उन्हें पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष से हटाया गया, लेकिन फिर जौनपुर का जिलाध्यक्ष बना दिया गया. इस तरह की हास्यास्पद कार्रवाई सपाइयों के गले नहीं उतर रही है.

खनिज उपक्रम विभाग के कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जब से मंत्री बने हैं, तभी से अपनी कारगुजारियों के कारण काफी चर्चा में हैं. लेकिन आश्चर्य है कि इन पर कार्रवाई करने के बजाय इनका ओहदा बढ़ाया ही जाता रहा है. पहली बार विधायक बनने वाले गायत्री प्रसाद प्रजापति को पहले राज्यमंत्री, फिर स्वतंत्र प्रभार देने के बाद अब कैबिनेट मंत्री बनाकर उपकृत किया गया है. लखनऊ में किसानों की 32 एकड़ जमीन हड़पने व उनके बेटे द्वारा जमीन कब्जा कर मकान बनाने के कारण

कार्रवाई केवल दिखावा है

उपचुनाव में भले ही साइकिल दौड़ गई हो पर लोकसभा चुनाव के पंचर के गहरे असर का गहरा जख्म अब भी कायम है. पार्टी की दुर्दशा में मंत्रियों की भूमिका पर बड़े सवाल दर्जाधारी मंत्रियों पर कार्रवाई के बावजूद अब भी वैसे ही खड़े हैं. ये भविष्य में भी सरकार और पार्टी दोनों केलिए मुसीबत की वजह बनते रहेंगे. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दीवाली केदो दिन बाद 82 दर्जा प्राप्त राज्यमंत्रियों को बर्खास्त कर दिया. दर्जाधारी मंत्रियों में से 16 लोगों की कुर्सी सलामत है. लेकिन सूत्र बताते हैं कि कार्रवाई के बाद भी कई दर्जाधारियों की औकात पहले जैसी ही कायम है. पार्टी सूत्रों का कहना है कि जल्द ही फिर से कई लोगों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया जा सकता है. इसमें हटाए गए लोगों केभी खासी तादाद में शामिल होने की उम्मीद है. उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के चार दिन बाद 20 मई को भी 36 दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री बर्खास्त किए गए थे. इसमें कई चेहरों को दोबारा मौका दिया गया था. यानी, पार्टी केनेताओं का लक्ष्य वह नहीं है जो दिखता है. पार्टी केनेताओं का लक्ष्य विरोधियों का मुंह बंद करना है. उसी लक्ष्य को साधने के लिए दीवाली के ठीक पहले सपा ने पार्टी के 'गद्दारों' को ढूंढ़ने केलिए कमेटी भी बना दी थी. अब उसी पर सारा ध्यान केंद्रित है. दरअसल पार्टी के खास नेताओं का टार्गेट भी वही है. ■

भस्मासुरों से घिरे अखिलेश

मनीष जगन

कोई लाख अच्छा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे भस्मासुर होता है. यह बात समाजवादी पार्टी पर बखूबी लागू हो रही है. भारतीय राजनीति में सबसे अनुभवी और जमीनी राजनीतिक व्यक्ति समाजवादी पार्टी केप्रमुख मुलायम सिंह यादव के पुत्र व देश केसबसे युवा मुख्यमंत्री होने के बावजूद अखिलेश यादव भस्मासुरों की वजह से ही आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में विवश नजर आते हैं. इधर उन्होंने थोड़ी तेजी दिखाई है, लेकिन यह तेजी भी राजनीतिक कम, उकसाऊ अधिक लगती है.

क्या करें क्या ना करें कि ये कैसी मुश्किल हाय, वाली बात इसके मूल में है. पार्टी के विधायकों, मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं की कार्यकर्ताओं से संवादहीनता और निजी स्वार्थों की प्रधानता केकारण पार्टी की विचारधारा और नेतृत्व के दिशा–निर्देशों की उपेक्षा हो रही है. सूबे की व्यवस्था संभालने वाले जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों का पार्टी नेताओं के मतभेदों में मजा लेना और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अगली सरकार के मद्देनजर विपक्षी नेताआ की गुलामी करने का प्रतिफल है. इस वजह से पार्टी और मुख्यमंत्री की विकासशील योजनाओं के बारे में सटीक जानकारी लोगों तक पहुंचने में तमाम बाधाएं खड़ी हो रही हैं. आस्ट्रेलिया से पढ़कर लौटे और साढ़े 13 वर्ष अपने अनुभवी पिता केसान्निध्य में सांसद रहकर राजनीति के गुण सीखने वाले अखिलेश ने 2012 में विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में भी संघर्ष कर 224 सीटें हासिल की और प्रदेश केमुख्यमंत्री बने. अपनी विकासशील महत्वाकांक्षी योजनाओं को परवान चढ़ाने की कोशिशों में वे लगे थे लेकिन उनकी पार्टी केकई वरिष्ठ और कनिष्ठ नेताओं ने उन्हें शर्मसार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. पिछली सरकार का अकथ्य भ्रष्टाचार, खाली खजाना और बदहाल प्रशासनिक व्यवस्था के आदी नौकरशाहों को अखिलेश का प्यार और सम्मान भरा आचरण रास नहीं आया और वे अपनी स्वार्थपूर्ति केलिए सरकार के मुखिया को भ्रमित करने में जुट गए. इसकेलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी और सरकार में मंत्रियों केआपसी मतभेदों का खूब सहारा लिया. मुलायम की झिड़कियों ने भी अखिलेश को सरकार का मुखिया स्थापित करने केबजाय अपरिपक्व और आज्ञाकारी बच्चे केरूप में शुरुआती दौर में खड़ा किया जिसका पार्टी के वरिष्ठ नेताओ और प्रदेश नौकरशाहों ने खूब बेजा फायदा उठाया. इन लोगों ने काम कम किया और काम अधिक बिगाड़ा. भ्रम ज्यादा पैदा किया, श्रम कम किया. 2014 का लोकसभा चुनाव इसी भ्रम में निकल गया. 16 मई को भ्रम टूटा मगर उपचुनावों की जीत ने फिर से भ्रम का मुलम्मा चढ़ा दिया. चाटुकार वेशधारी भस्मासुरों ने फिर अपना काम कर दिखाया. अखिलेश को इस भ्रम से बचना होगा, नहीं तो 2017 भी 2014 की तरह ही निकल जाएगा और हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा. ■

यह कैसी कार्रवाई!

दर्जा प्राप्त मंत्रियों पर कार्रवाई की इतनी जल्दबाजी थी कि निठल्ले और काम वाले या दोषी और निर्दोष का फर्क समझने की भी कोशिश नहीं की गई. सब पर एक साथ चाबुक चला दिया गया, इससे साफ लगा कि यह कार्रवाई कुछ और इरादे से की जा रही है. सपा के नेता ही बताते हैं कि दर्जा प्राप्त मंत्रियों में कई ऐसे नेता भी थे जिनकी निष्ठा पर संदेह ही नहीं किया जा सकता. कुछ लोग तो लंबे समय से संगठनात्मक भूमिका में रहे. इनमें पार्टी के गठन केसमय से ही कोषाध्यक्ष रहे राजकिशोर मिश्र, सपा युवा ब्रिगेड केसदस्य सुनील यादव साजन, लोहिया वाहिनी केडा. राजपाल कश्यप वगैरह के नाम शामिल हैं. पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और सपा के बीच नजदीकी के चलते नाराज हुए उलमा को मनाने में कारगर भूमिका निभाने वाले आशु मलिक, पूर्व सांसद रेवती रमण सिंह केपुत्र उज्जवल रमण सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे रामपूजन पटेल का हटाया जाना सपाइयों की समझ में नहीं आया. मधुकर जेटली और नावेद सिद्दीकी जैसे लोगों को हटाए जाने के पीछे की परिपक्व समझ पर भी सवालिया निशान लगा. समाजवादी पार्टी केकार्यकर्ता ही यह कहते नजर आ रहे हैं कि अपने ही नेताओं पर नासमझ कार्रवाई करने वाली यह कैसी पार्टी है. ■

पार्टी की काफी छीछालेदर हुई, लेकिन प्रदेश के मुखिया चुप्पी साधे हैं. अति पिछड़ी जातियों में लोधी, पाल, बघेल, निषाद, किसान, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, कोयरी वगैरह की आबादी प्रजापति से काफी अधिक होने के बाद भी उन्हें राजनीतिक रूप से सपा द्वारा नजरअंदाज किया जाता रहा है. जिससे इन वर्गों में काफी असंतोष है. यह 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा केलिए घाटे का सौदा हो सकता है.

अभी अवैध खनन केकारण राज्य मंत्री पंडित सिंह काफी चर्चा में हैं. बालू मौरंग खनन के क्षेत्र में गायत्री प्रसाद प्रजापति का खनन माफिया गिरोह व सिंडिकेट काफी सक्रियता से अवैध खनन कराकर मालामाल हो रहा है. स्वास्थ्य चिकित्सा राज्य मंत्री शंखलाल मांझी व गायत्री प्रसाद प्रजापति मिलकर हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, सोनभद्र, इलाहाबाद में अपना सिंडिकेट चला रहें हैं. मांझी केव्यवहार से उनकेसमाज में भी काफी नाराजगी है, उनकी गतिविधियों से कश्यप–निषाद समुदाय केलोग सपा से नाराज होते जा रहे हैं. दर्जा प्राप्त राज्यमंत्रियों पर चाबुक चलने के बाद कार्यकर्ताओं को इंतजार था कि मनोज पांडेय, नारद राय, रामआसरे विश्वकर्मा, राजा राजीव कुमार सिंह, व्यास जी गोड़, विजय मिश्रा, बलराम यादव जैसे नेताओं पर भी कार्रवाई होती, लेकिन पार्टी केनेताओं की नजर में यह प्राथमिक नहीं है. प्राथमिक यह है कि बड़े नेताओं केजन–विरोधी कार्यकलापों का विरोध करने वालों को गद्दार बता कर उन्हें पार्टी से किस तरह खदेड़ा जाए. राजनीति केविशेषज्ञ कहते हैं कि सपा नेता अपनी डाल पर जितनी ही कुल्हाड़ी चलाएंगे, भाजपा केलिए वह उतना ही फायदेमंद साबित होता जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

धान और गन्ने पर खुलेआम डाका

सीतापुर समेत यूपी के सभी जिलों के किसान बदहाल

हिमांशु कुमार

प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. रामकुमार वर्मा ने जिस किसान को अपनी कविता में ग्राम देवता कहकर उसका सम्मान बढ़ाया, वही ग्राम देवता आज धान, गन्ना की अपनी उपज की बिक्री को लेकर काफी परेशान है. अपनी परेशानी के चलते व रबी फसल की बुआई में लगने वाली लागत की वजह से धान व गन्ना औने-पौने दामों में बेचने को किसान विवश हो रहा है. जनपद में धान की फसल कटकर तैयार हो चुकी है. गन्ना भी बिक्री के लिए खेतों में खड़ा इंतजार कर रहा है कि कब चीनी मिल चले और किसान उसे बेच सकें. इसी प्रकार धान उत्पादित करने वाले किसान भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त नहीं हो रहा है. सरकारी धान खरीदने की जो एजेंसियां प्रशासन द्वारा लगाई गई हैं उन्होंने कहने सुनने के लिए कुछ क्रय केंद्र तो खोल दिया है, लेकिन गल्ला व्यापारियों और धान क्रय केंद्र संचालकों की मिलीभगत की वजह से वह धान खरीद नहीं कर रही हैं. जिससे क्रय केंद्रों पर जहां सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं गल्ला मंडी में राईस मिलर्स व्यापारी धान 800 रुपये कुंतल की दर से लेने में भी आनाकानी कर रहे हैं. बताते है कि लेवी का धान खरीदने में भी मिल मालिक व सरकारी एजेंसियों के बीच धन का खेल चलता है. यहां इस बात की जानकारी जरूरी है कि ज्यादातर सरकारी एजेंसियों की धान खरीद का ठेका राईस मिल मालिकों का ही रहता है, क्योंकि यही लोग किसान का धान सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीद कर व उसकी कुटाई कर सरकार को आपूर्ति करते हैं. जिसका निर्धारित मूल्य का भुगतान सरकार द्वारा उन्हें प्राप्त होता है. उसी का लाभ उठाकर यह मिल मालिक सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलीभगत कर लेते हैं और किसानों की खून पसीने से उपजाई गई धान की फसल को लूटने व सरकारी धन को चूना लगाने का गोरखधन्धा शुरू हो जाता है. सरकारी एजेंसियों पर जो किसान अपना धान बिक्री हेतु ले जाता है, तो धान में अनगिनत कमियां निकाल कर उसे परेशान किया जाता है. एक-दो किसानों को छोड़कर अधिकांश किसान अपना धान खुली मंडी में बेचने को विवश हो जाते हैं, क्योंकि किसान को तो अपनी अगली फसल बोने व व्यक्तिगत खर्चों सहित बैंकों का ऋण भी चुकता करना रहता है. इसलिए वह मजबूरीवश अपनी फसल को मंडी में गल्ला आढ़तियों के हाथों बेच देते हैं, किन्तु गौरतलब है कि खुली मंडी में धान फसल के खरीददार ज्यादातर वही मिल मालिक रहते हैं जिनके द्वारा उसी धान को सरकारी एजेंसियों पर रिजेक्ट करवा दिया जाता है. इन धंधेबाजों का खेल यही पर समाप्त नहीं होता है. ये जिस धान को आठ-नौ सौ रुपये कुंतल के मूल्य पर खरीदते हैं, उसी धान को सरकारी एजेंसियों पर किसान का धान 1380 रुपए व 1400 रुपये मूल्य पर सरकारी कागजों पर खरीदा हुआ दिखाते हैं. जिससे तकरीबन चार सौ से पांच सौ रुपये प्रति कुंतल का मुनाफा बिना हर्र लगे न फिटकरी के होता है. जिसका बन्दरबांट सम्बन्धित सभी कर्मचारियों व उच्चाधिकारियों तक होता है, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी यह रहती है कि किसान को उनकी फसल का सही मूल्य दिलवाकर शासन की वाहवाही करवाना. इतना बड़ा गोरखधंधा बिना सम्बन्धित अधिकारियों-कर्मचारियों के संभव ही नहीं है. गल्ला मंडी में मौजूद सैकड़ों किसानों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर चल रहे घालमेल की जानकारी अगर सम्बंधित सक्षम अधिकारियों को नहीं है, तो सरकार को ऐसे निठल्ले, खाऊ-कमाऊ व शासन की छवि खराब करने वाले अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर धन्धेबाजों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए. अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो आम जनमानस को यह समझ लेना चाहिए कि सभी भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों और व्यापारियों के साथ पूरी सरकार ही भ्रष्टाचार के हमाम में नंगी खड़ी है.

धान किसानों की तरह गन्ना किसान भी अपनी उपज को औने-पौने दामों पर बेचने को विवश हैं. जनपद में सात चीनी मिलों में से पांच चीनी मिलें गन्ना खरीद का काम करती आई हैं, लेकिन अक्टूबर माह समाप्त होने के बाद भी किसी भी चीनी मिल की चिमनी ने धुंआ उगलना शुरू नहीं किया है. रबी की फसल की बुआई व पलेवा हेतु सिंचाई का कार्य शुरू हो गया है. किसान खाद-बीज खरीदने व बैंक ऋण की अदायगी के लिए अपना गन्ना गुड़ कोल्हू बेलों पर 100 से लगाकर 120 रुपये प्रति कुंतल मूल्य पर बेचने को लाचार है. गन्ना किसानों में यह भी चर्चा है कि गन्ना गुड़ कोल्हू संचालक गन्ने की तौल में भी घटतौली करते हैं. जिले के गांजरी क्षेत्र में तो मेरठ आदि जिलों से आकर गुड़ व्यवसायी अपनी बेलें लगाते हैं. कभी-कभी तो यह व्यवसायी किसानों के गन्ना मूल्य का थोड़ा बहुत भुगतान कर बकाया भी रखते हैं. गन्ना का सीजन खत्म होने के निकट कोई-कोई बेल मालिक गन्ना मूल्य लेकर रफूचक्कर भी हो जाता है और गन्ना किसान बिना मूल्य प्राप्त किए अपने हांथ मलता रह जाता है. गन्ना खरीद में गुड़ बेल मालिक किसानों का कितना आर्थिक शोषण करते हैं इसे देखने का न तो प्रशासन को समय है और न जन प्रतिनिधियों को. किसानों के हमदर्द बनने वाले किसान संगठन भी गन्ना किसानों के आर्थिक शोषण पर चुप्पी साधे रहते हैं. कुल मिलाकर कृषि प्रधान देश में किसानों की दयनीय दशा का जिम्मेदार कभी कभार आने वाले हुदहुद जैसे दैवीय प्रकोप से ही नहीं, बल्कि वह सभी लोग हैं जिनके हाथों में किसान खुद की दशा व दिशा निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपता है. ■

गन्ने की खेती छोड़ रहा किसान

उत्तर प्रदेश में गन्ने के प्रति बने नकारात्मक माहौल का असर यह है कि उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान अब इसकी खेती छोड़ रहा है. लागत के अनुपात में गन्ने का मूल्य न तय होना, एक साल तक मिलों द्वारा भुगतान रोका जाना, हर पेराई सत्र में मिल देर से शुरू होना, तमाम कोर्ट केस आदि ऐसे कारण हैं जिनके चलते उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान इस फसल का उत्पादन करने से दूरी बना रहा है. उत्तर प्रदेश में 2014-15 में गन्ने का क्षेत्रफल 21.30 लाख हेक्टेयर है, जो कि वर्ष 2013-14 के 23.60 लाख हेक्टेयर के मुकाबले लगभग 10 प्रतिशत कम है. यह आंकड़ा सरकारी है, लिहाजा इस पर भरोसा कम ही किया जा सकता है. यानी जमीनी हालात कहीं ज्यादा खराब है. सरकार की उपेक्षा इसी तरह बनी रही तो खेती में 40-50 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है. सीतापुर जिले में तो लगभग 50 से 60 प्रतिशत किसान अन्य फसलों की तरफ मुड़ गया है. उत्तर प्रदेश का गन्ना बेल्ट कहे जाने वाले क्षेत्र के कई ज़िलों मसलन, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, शाहजहांपुर, मेरठ व बागपत में गन्ना किसानों की स्थिति यही है कि गन्ने की नीतियों में सरकार ने शीघ्र सुधार नहीं किया तो प्रदेश में इसके खेती में काफी कमी आ जाएगी. वर्ष 2013-14 के पेराई सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश की 119 चीनी मिलों ने लगभग 7,000 कुंतल गन्ना पेरा था जिससे लगभग 650 लाख कुंतल चीनी का उत्पादन हुआ था. इन मिलों में से 95 मिल निजी व 23 सहकारी हैं, जिनकी संयुक्त रूप से पेराई क्षमता लगभग 7,50,000 लाख टन प्रति दिन है. इस पेराई सत्र के लिए निजी चीनी मिले अब तक टालमटोल ही कर रही हैं ताकि किसान औने-पौने दाम में बाजार के बिचौलियों को अपनी फसल बेच दे और चीनी मिलें बिचौलियों से गन्ना खरीद लें.

उत्तराखंड

आईसीपीएस केवल कागजों पर है लागू

केंद्रीय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2009 में जो समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) लागू की थी, वह प्रदेश में आज भी महज फाइलों में लागू है. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी अपने 33 महीने के कार्यकाल के दौरान इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाया. आयोग के अध्यक्ष अजय सेतिया ने अब समाज कल्याण मंत्री सुरेंद्र राकेश को पत्र लिखकर कहा है कि आयोग के सारे प्रयास विफल रहे हैं और उत्तराखंड देश का अकेला राज्य रह गया है जहां आईसीपीएस सिर्फ फाइलों में लागू है. उत्तराखंड की प्रदेश सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए 19 जनवरी 2011 में महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर दस्तखत भी किए, मामला आगे नहीं बढ़ पाया. इस योजना के लिए 75 फीसद अनुदान केंद्र सरकार देती है. जून 2013 की आपदा के बाद 3 जुलाई को मुख्य सचिव की ओर से बुलाई गई बैठक में राज्य बाल आयोग ने प्रस्ताव रखा कि समाज कल्याण विभाग योजना को लागू करने में असमर्थ है, तो इसे महिला एवं बाल विकास विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाए. बैठक में इस पर सहमति भी बनी लेकिन योजना हस्तांतरित नहीं की गई. प्रदेश में इस योजना से जुड़ी तमाम इकाइयों के गठन के बाद राज्य सरकार को एक परियोजना रिपोर्ट बनाकर केंद्र को भेजनी चाहिए थी, ताकि केंद्र से अनुदान मिल सके, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं. केंद्र से अनुदान मिलता तो प्रदेश के हर जिले में शरणालय, बालगृह, संप्रेक्षण गृह और विशेष गृह खुल सकते थे, लेकिन चौदह वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य शुरू नहीं हो सका. पिछले साल जून की भयावह आपदा के बाद केंद्र सरकार ने खुद ही आईसीपीएस के तहत 8 करोड़ 41 लाख 56 हजार 520 रुपये की मंजूरी दी और अगस्त में ही तीन करोड़ 33 लाख 92 हजार रुपये की पहली किस्त जारी भी कर दी. उसके बावजूद न तो प्रदेश में आईसीपीएस के निदेशक की नियुक्ति हुई और न ही राज्य स्तरीय बाल संरक्षण समिति का कार्यालय खुला. जिलों में भी जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्डों के दफ्तर भी नहीं खुले. यही नहीं बाल संरक्षण योजना को लागू करने के लिए मंजूर 249 पदों पर भी भर्ती नहीं हुई. बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों के सदस्यों की चयन समिति का पुनर्गठन डेढ़ साल से लटका है. इतना ही नहीं 10 साल में राज्य में एक भी नया बाल गृह नहीं खुला. राज्य सरकार ने दत्तक ग्रहण यानी गोद लेने के लिए राज्य दत्तक ग्रहण एजेंसी (सारा) और सलाहकार एजेंसी बनाई तो जरूर, दोनों अभी महज कागज पर ही हैं. उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण में इस समय देश में अंतिम पायदान पर हैं. ■

(मैंने समाज कल्याण मंत्री से अपेक्षा की है कि प्रभारी मंत्री होने के नाते वहआईसीपीएस लागू न होने को गंभीरता से लेंगे और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक निश्चित समय सीमा के भीतर उससे संबंधित कार्य संपन्न कराएंगे- अजय सेतिया, अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग)

-चौथी दुनिया ब्यूरो

पारंपरिक पेशेवर जातियों की रोजी रोटी पर पूंजीपतियों और माफियाओं का कब्जा

ऐसे तो विलुप्त हो जाएंगी पारंपरिक जातियां

सूफी यायावर

उत्तर प्रदेश की पारम्परिक पेशेवर जातियों का अस्तित्व खतरे में है. यदि सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया तो वह दिन दूर नहीं जब ये जातियां भारतीय समाज से विलुप्त हो जाएं और अपनी सांस्कृतिक समृद्धि केवल किताबों की बात रह जाए. शासन की पूर्ण उपेक्षा के कारण पारम्परिक जातियों की दुर्गति है और उनके पारम्परिक पेशों पर पूंजीपतियों और माफियाओं का कब्जा हो गया है. जिनका काम था वे भुखमरी का शिकार हैं और जिनका कब्जा है, वे मालामाल हो रहे हैं. सरकार की सारी नीतियां पूंजीपतियों और माफियाओं का हित साधने वाली हैं, समाज के आम लोगों का हित सरकार की प्राथमिकताओं में कहीं भी नहीं है.

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वंशागत पेशा व कारोबार के कारण जातियों का नामकरण हुआ. देश में सैकड़ों जातियां है, इनका नामकरण उनके पुश्तैनी परम्परागत धंधों, व्यवसायों के कारण हुआ है. नाव चलाने वाला नाविक, केवट, मल्लाह, नदी पार उतारने वाला मांझी, तेल निकालने वाला तेली, लकड़ी का काम करने वाला काष्ठकार-बढ़ई, लोहा का काम करने वाला लोहार, मछली मारने वाला मछुआरा, हजामत बनाने वाला हज्जाम, पान का काम करने वाला पनेरी, नून-नमक बनाने वाला नोनिया, कुआं खोदने वाला व बोझ ढोने वाला बेलदार, मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार, चिड़िया फंसाने वाला बहेलिया-चिड़ीमार, नाच गाकर जीविका चलाने वाला नट या बंजारा, गाय पालने वाला ग्वाला, भेड़ पालने वाला भेड़िहार, फुल सब्जी की खेती करने वाला माली-कोयरी, चमड़े का जूता बनाने वाला मोची, खैर कत्था बनाने वाला खैरवार-खरवार-खैरहा, मदारी का खेल दिखाने वाला मदारी, घरेलू नौकर का काम करने वाला मेहरा-कहार, दाना-भूंजा भूजने वाला भुर्जी-भोजनवाल-भड़भूजा, कपड़ा धोने वाला धोबी, साप नचाकर व दिखाकर रोजी कमाने वाला सपेरा, सोना का आभूषण बनाने वाला सोनार, ताम्बे का काम करने वाला ताम्रकार, कांसे-पीतल का बर्तन बनाने वाला कसेरा आदि नाम पेशावाचक हैं. मशीनीकरण-औद्योगीकरण के कारण 80 प्रतिशत जातियों का परम्परागत पुश्तैनी पेशा छीन गया है और वे अपनी आजीविका के लिए मजबूर हैं. मशीनीकरण के कारण लोहार, तेली, बढ़ई, कुम्हार, मुसहर, बेलदार, खरवार, मल्लाह-केवट आदि का धंधा लगभग समाप्त हो चुका है. मोची का काम बाटा तो लोहार का काम टाटा, जुलाहा का काम मफतलाल, बिरला आदि के चलते छिन गया है. जब परिवहन का माध्यम जल मार्ग था तो आवागमन, व्यापार का काम जल मार्ग से होता था, जिसका संचालन केवट, मल्लाह या निषाद समाज द्वारा संचालित होता था और उन्हें देश की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ कहा जाता था. मत्स्य पालन, मत्स्याखेट, शिकारमाही, नौकाफेरी, बालू मौरंग खनन, नदियों की कछार, गंगबरार व कटरी की जमीनों में खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि जायद की खेती, सिघाड़ा, ताल मखाना, कमल गट्टा आदि का परम्परागत पेशा मछुआरा-निषाद समाज के मल्लाह, केवट, कहार, गोड़िया, तुरहा, धीवर, रायकवार, मांझी, बिन्द आदि द्वारा किया जाता था. लेकिन सरकारों की गलत नीतियों और माफिया राज के चलते इन जातियों का काम छिन गया है. नदियों पर पक्का पुल, पीपा पुल बन जाने, गंग बरार कटरी की जमीनों पर भू माफियाओं, सामन्तों के कब्जे के कारण यह समुदाय अपनी रोजी रोटी से वंचित हो भुखमरी व बेकारी की स्थिति में पहुंच कर रोटी रोटी को मोहताज हो गया है.

मछुआरों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्रीय निषाद संघ-नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमेन के राष्ट्रीय सचिव चौधरी लौटन राम निषाद ने परम्परागत पेशेवर जातियों की समस्याओं के सम्बन्ध में बताया कि नदियों पर पुल बन जाने से नावें बेकार हो गईं, ट्रक रेल आदि संसाधनों के आविष्कार से जल परिवहन का काम बन्द हो गया तथा फुलों की पक्कर वसूली व घाटों का नीलामी ठेका गोरखनाथ उपाध्याय व हरिशंकर तिवारी आदि के परिवार के नाम हो जाने से नाविक मछुआरा समाज बंधुआ मजदूर हो गया है. गंगा नदी पर फरक्का बैराज बन जाने से बंगाल की खाड़ी से गंगा में आने वाली हिलसा, झींगा, पढ़ीन, पियासी, रोहू आदि मछलियों की आमद जहां कम हो गई, वहीं कल कारखानों, चीनी मिलों, टेनरियों, शराब फैक्ट्रियों के विषाक्त प्रदूषित जल, कचरा, गंगा जमुना नदियों में गिराए जाने से जल जन्तुओं के प्रजनन व जीवन पर खतरा उत्पन्न हो गया है. जिससे नदियों में अब बहुत कम मछलियां ही रह गई हैं. सरकार की गलत मत्स्य, खनन नीति के कारण तो बचा खुचा मछुआरों का व्यवसाय, वंशागत पेशा, मत्स्य व बालू माफियाओं के हाथों में चला गया है. तालाबों, जलाशयों का मत्स्य पालन पट्टा की लगान प्रति हेक्टयेर, प्रतिवर्ष 10 हजार से अधिक करने के कारण अब पुश्तैनी पेशेवर जातियों के लिए ठेका पट्टा लेना दूर की कौड़ी हो गया है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा तो दे दिया है, लेकिन लाल फीताशाही की लीपापोती व अस्पष्ट आदेशों के न होने के कारण मछुआरों को इसका लाभ होता नहीं दिख रहा है, मछुआरों की मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के पास कोई काम नहीं रह गया है. आन्ध्र प्रदेश में मत्स्य पालन व मत्स्य व्यवसाय, पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान देने के कारण वहां का मछुआरा आत्मनिर्भर तो हुआ ही है, यह देश का मत्स्य उत्पादन में अग्रणी प्रदेश बन गया है. नीली क्रान्ति के विकास के कारण आन्ध्र प्रदेश की मछलियां देश के हर राज्य, जिले में तो आपूर्ति की ही जा रही है, विश्व के कई देशों में हैदराबाद से मछलियों का निर्यात किया जा रहा है.

झीलों, नदियों, जलाशयों, तालाबों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश काफी धनी प्रदेश है और यहां प्रचुर संख्या में जल क्षेत्र व जल संसाधन, होने के बाद भी सरकार की सही नीति न होने के कारण प्रदेश में नीली क्रान्ति का विकास नहीं हो पा रहा है. पड़ोसी राज्य बिहार में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा देने के साथ-साथ वहां मछुआरा आयोग का गठन किया गया है जो सरकार व प्रशासन को सही सलाह देता है. मत्स्य पालन पट्टा के लिए टोकन प्रणाली होने से मछुआरों व उनकी समितियों को आसानी से सस्ते दर पर जल क्षेत्र का पट्टा मिल जाता है. मत्स्य कृषि के लिए उचित दर पर ऋण व अनुदान की व्यवस्था है. ताल मखाना उत्पादन के क्षेत्र में बिहार इस समय देश में अग्रणी स्थान पर है. उत्तर प्रदेश में श्रेणी-3 के तालाबों की सिरधरी स्थानीय मछुआरों के नाम थी, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें बेदखल कर दिया गया है. अगर सरकार मत्स्य पालन पर ध्यान देकर सरल नीति बनाए तो उत्तर प्रदेश देश का मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में प्रथम स्थान आ सकता है और लाखों परिवारों का जीवन खुशहाल हो सकता है. बालू मौरंग खनन का काम मछुआरों का परम्परागत पुश्तैनी पेशा तो उनसे काफी दूर हो गया है. बालू मौरंग खनन का ठेका बड़ी-बड़ी कम्पनियों, बड़े-बड़े माफिया ठेकेदारों के हाथ में चला गया है. यहीं नहीं नदी कछार से जो केवट मछुआरे बालू निकालने का काम करते थे, अब यह काम माफिया जेसीबी व पोकलैंड मशीनों से करा रहे हैं जिसके कारण केवट, मल्लाह तो बेकार हुए ही हैं, पर्यायवरण को भी खतरा पैदा हुआ है तथा जल जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है. 27 जून, 1857 को कानपुर के सत्ती चौरा घाट पर समाधान मांझी व लोचन मल्लाह ने 40 नावों पर सवार अंग्रेजी सेना व उनके परिवारों को गंगा नदी में डूबो कर मार डाला था. निषादों की देशभक्ति से चिढ़ कर ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें जरायम पेशा जाति घोषित कर दिया था. प्रीवी काउन्सिल ऑफ लंदन के द्वारा 1878 में मछुआरों के परम्परागत पेशों को छीन कर भूखों मारने के लिए चार काले कानून बनाए और नॉर्दर्न इंडिया फेरीज ऐक्ट, नॉर्दर्न इंडिया फिशरीज ऐक्ट, नॉर्दर्न इंडिया माइनिंग एक्ट व नॉर्दर्न इंडिया फॉरेस्ट ऐक्ट बनाकर मछुआरों का पेशा छीन लिया.

मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुमिरन विश्वकर्मा ने कहा कि पहले हल, जुआठ, पटेला आदि के साथ-साथ तमाम कृषि औजार बनाने व गृह निर्माण का कार्य लोहार बढ़ई के द्वारा होता था. बैलों से खेती का काम बन्द होने से उनका गांव गिराव में कृषि औजार बनाने का काम बिल्कुल बन्द हो गया है. कोल मुसहर, बनवासी पलाश-महुआ के पत्तों का पत्तल-दोना बनाकर आजीविका चलाते थे, लेकिन कारखानों में पत्तल दोना, थाली, तश्तरी बनाए जाने से यह समाज मुसीबतों का शिकार हो गया. सरकार द्वारा इन जनजातियों के पुनर्वास वैकल्पिक प्रबन्ध न करने और विकल्प न ढूंढ़ने के कारण तमाम जातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है. कोल, मुसहर, वनवासी, गिरीवासी भुखमरी बदहाली का जीवन जी रहे हैं. जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से बिल्कुल वंचित हैं. रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य से मोहताज हो पशुवत जीवन जीने पर मजबूर हो रहे हैं. इनके कल्याण, उत्थान के लिए जो सरकारी योजनाएं संचालित हैं, उसका इन्हें रत्ती भर भी लाभ नहीं मिल पा रहा है और तथाकथित एनजीओ या स्वयं सेवी संस्थाएं इसी के नाम पर मालामाल हो रही हैं. ■

कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की नहीं होती सुनवाई

अंबिका सोनी के सामने दिखी कांग्रेस की लड़ाई

राजकुमार शर्मा

कांग्रेस में हाईकमान ही सर्वोपरी है और कांग्रेस के नेता अब भी मदमस्त, बेलगाम है इसका एक नजारा अंबिका सोनी की देवीभूमि दौरे के दौरान देखने को मिली. पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी पैरोकार रही कांग्रेस में कोई भी फैसला सर्वसम्मति से नहीं होता, पार्टी के नेताओं को पार्टी सुप्रीमो का ही फरमान मानना पड़ता है. केवल कहने के लिए पेचीदा मुद्दे पर प्रेक्षक या प्रभारी को भेजकर रायशुमारी कराई जाती है, फैसला वही माना जाता है जो हाईकमान सुनाए. ऐसे ही छद्म लोकतांत्रिक व्यवस्था की पुष्टि उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी अंबिका सोनी के इस बयान से होती है, जो उन्होंने राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर दून मीडिया में दिया है. उन्होंने माना कि राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी को लेकर प्रदेश के अधिकतर नेताओं ने स्थानीय उम्मीदवार की मांग की है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी करेगी.

मुख्यमंत्री हरीश की मुखालफत करने वाले कैबिनेट के कद्दावर बड़बोले मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने प्रदेश प्रभारी सोनी की समीक्षा बैठक से भी दूरी बनाए रखी. बैठक में सभी मंत्रियों को बुलाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत सभी मंत्री तो मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस कोटे से हरक सिंह ही जानबुझ कर पार्टी हाई कमान को ठेंगा दिखाते हुए बैठक से नदारद रहे. इसके अलावा सरकार में सहयोगी पीडीएफ के पांच मंत्रियों में से भी मात्र दो ही मंत्री पूरी मीटिंग में मौजूद रहे. हालांकि एक अन्य मंत्री प्रसाद नैथानी पहुंचे तो जरूर थे, कुछ मिनट के बाद ही वह वहां से निकल चलते बने.

दून पहुंचते ही अंबिका सोनी मुख्यमंत्री आवास के सभागार में आपदा राहत कार्य की समीक्षा के लिए पहुंची. वहां पर मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कांग्रेस के सभी मंत्री भी मौजूद थे, लेकिन हरक सिंह रावत यहां भी नहीं आए. देश भर में दुर्दशा झेल रही कांग्रेस को अब उसके नेता ही कांग्रेस के दुर्दिन शुरू होने का संकेत दे रहे है. प्रदेश की खाली हुई राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले चुनाव के अलावा राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार, दायित्व वितरण समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश कांग्रेस में मची रार को मुख्यमंत्री हरीश रावत कैबिनेट के दो मंत्रियों ने तल्ख बना दिया है. इनमे से एक मंत्री हरक सिंह रावत तो कई बार अपनी ही सरकार को खुलेआम कठघरे में खड़ा चुके हैं, इस बार एक अन्य मंत्री सुरेन्द्र सिंह नेगी ने भी राज्यसभा की उम्मीदवारी के बहाने रावत टीम पर अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधा है. दोनों मंत्रियों ने पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को राज्यसभा चुनाव के लिए उपयुक्त उम्मीदवार करार देकर बहुगुणा विरोधी अभियान को झटका देने का प्रयास किया है. गौरतलब है कि बहुगुणा भी कई बार सरकार से पीडीएफ को हटाकर मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की सलाह दे चुके हैं जबकि हरीश रावत लगातार पीडीएफ के प्रति हमदर्दी जता रहे हैं. इसी बीच राज्यसभा की खाली हुई एक सीट पर चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी तो बहुगुणा ने खुद का दावा पेश कर दिया जबकि हरीश रावत अपनी पसंद के किसी नेता को राज्यसभा भेजना चाहते हैं. इस मुद्दे को लेकर दोनो के बीच ठन गई है.

इसी क्रम में डॉ. हरक सिंह रावत ने सरकार में पीडीएफ के बहाने रावत पर निशाना साधकर नए सियासी युद्ध का संकेत दे दिया है. रावत ने कहा कि पार्टी में भी कुछ वरिष्ठ व पूर्व में मंत्री रह चुके नेता हैं जो इस समय विधायक हैं और जिन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पीडीएफ के 7 विधायकों में 4 को मंत्री बनाने से पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है. मंत्री ने कहा कि पीडीएफ से पीछा नहीं छुड़ाया गया तो 2017 के विस चुनाव में कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है. कांग्रेस में राज्यसभा सीट के लिए चल रही बयानबाजी में अब विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री हरीश के खास रिस्तेदार गोविंद सिंह कुंजवाल भी शामिल हो गए हैं. कुंजवाल ने कहा है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय बहुगुणा को राज्यसभा में भेजना प्रदेश हित में होगा, क्योंकि बहुगुणा अनुभवी हैं और इसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा. उन्होंने कहा कि बहुगुणा में प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं को संसद में पेश करने की काबलियत है, लिहाजा उन्हें राज्यसभा में भेजना प्रदेश के हित में होगा. जब विजय बहुगुणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल ने विकास कार्य को लेकर कई बार उनकी सरकार पर सवाल उठाए थे. इस दौरान कुंजवाल बहुगुणा सरकार पर विवादित बयान देकर काफी सुर्खियों में भी रहे. कांग्रेस में दिन प्रतिदिन लड़ाई बढ़ती जा रही है जो प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी के प्रदेश दौरे के दौरान भी साफ देखना को मिला. ■

हरीश के दांव से बहुगुणा चारों खाने चित्त

रेनु शर्मा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में राज्य के करीब 356 पंचायत प्रतिनिधी दस जनपथ पर पहुंचे तो पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के चेहरे खिल उठे. देश में कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं एक बार हाईकमान को लगा कि लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस के पैर उखड़ गए हों, ग्रामीण जनता में अभी भी कांग्रेस के प्रति विश्वास कायम है. विपरीत माहौल में भी प्रदेश की विधानसभा उपचुनाव में तीनों सीटें कांग्रेस की झोली में डालने वाले उत्तराखंड से इतनी भारी संख्या में कांग्रेसी पंचायत प्रतिनिधियों को आया देख दोनों शीर्ष नेताओं सोनिया-राहुल ने हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष को बधाई भी दिया और उन्हें अधिकार संपन्न व सशक्त बनाने का सुझाव भी दिया. दरअसल राज्यसभा में राज्य की एक सीट के लिए विजय बहुगुणा की सशक्त दावेदारी पर दाव खेलते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विजय बहुगुणा के नहले पर दहला रख दिया. राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पांचों सीटें गंवानी पड़ी थी और विरोधी खेमे ने इसी हार को हरीश सरकार के खिलाफ हथियार बनाकर हाईकमान को बरगलाया भी था. किसी न किसी बहाने हरीश सरकार की नीतियों व कार्यप्रणाली पर प्रहार कर, हाईकमान के पास यह संदेश भी पहुंचाता रहा कि हरीश सरकार के चलते कांग्रेस और कमजोर होती जा रही है. उधर लोकसभा चुनाव में मिली पराजय के बाद से ही हाईकमान भी इस स्थिति से मायूस था. इसी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, पंचायती राज मंत्री प्रीतम सिंह, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप व संगठन के कद्दावर नेता विजय सारस्वत ने राज्य भर के करीब 356 पंचायत प्रतिनिधियों को दिल्ली स्थित दस जनपथ परिसर में सोनिया व राहुल से मिलवाया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री हरीश ने पंचायत प्रतिनिधियों को दिल्ली बुलाने के लिए सोनिया गांधी के प्रति आभार व्यक्त किया. यह जानकारी देते हुए विजय सारस्वत ने बताया कि शिष्टमण्डल से मुलाकात के दौरान राज्य की प्रभारी अंबिका सोनी, सह प्रभारी संजय कपूर, काग्रेस सचिव प्रकाश जोशी भी मौजूद थे. हरीश के इस दाव ने अब राज्यसभा के सम्भावित प्रत्याशी के रूप में गुलाबनबी आजाद को अव्वल स्थिति पर ला दी है. बहुगुणा के मुखर दावेदारी की तो हवा ही निकल गयी है. आजाद को हरीश रावत अपनी पहली पसंद बताते है. हरीश के दाव से उछल कूद कर विजय की हवा बनाने वाले दो मंत्रीयों कि भी बोलती बन्द हो गई है. ■

यूपी राजकीय निर्माण निगम की कार्यप्रणाली से जनता में आक्रोश

उत्तराखंड सरकार के तकनीकी शिक्षा के विस्तार के प्रयासों को उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम पलीता लगा रहा है. निगम की कार्यप्रणाली के प्रति जनता में गहरा आक्रोश व्याप्त है. प्रदेश सरकार ने प्रदेश में नए इंजीनियरिंग कॉलेजों की इमारतों के निर्माण का जिम्मा उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को दिया गया है. ये सभी इंजीनियरिंग कॉलेज निगम की लेटलतीफी की भेंट चढ़ रहे हैं. राज्य के सचिव तकनीकी शिक्षा आर.के. सुधांशु ने उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के इस रवैये पर कड़ा ऐतराज जताया है. सचिवालय में प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा सुधांशु ने उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रोफेसर वी.के. जैन के साथ विश्वविद्यालय के सभी छह संगठनों के साथ संस्थानों के बैठक में निर्माण कार्य आदि की समीक्षा की. बैठक में पता चला कि महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून की इमारत का काम शुरू न होने पर सचिव तकनीकी शिक्षा ने असंतोष जताया और तत्काल निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए. यही नहीं गोपेश्वर व उत्तरकाशी स्थित प्रौद्योगिकी संस्थान व टनकपुर पिथौरागढ़ स्थित सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान का हाल भी यही मिला तो सचिव ने उप निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक से जवाब मांगा तो उन्होंने बहाना बनाया कि पिथौरागढ़ में क्योंकि साइट तक संपर्क मार्ग का निर्माण नहीं हुआ है इसलिए इमारत का काम शुरू नहीं हो पाया. इस पर सचिव ने साथ ही संस्थान निदेशक को निर्देश दिए कि पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी से तत्काल संपर्क कर संपर्क मार्ग निर्माण कार्य के लिए धनराशि जारी करवाई जाए और इस मामले में प्रगति की जानकारी शासन को भी दी जाए ताकि काम में ढिलाई न हो. बैठक में प्रौद्योगिकी संस्थान गोपेश्वर के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि प्रीइंजीनियर्ड स्ट्रक्चर को 31 जनवरी तक पूरा कर दिया जाए. यही नहीं निर्माण निगम के महाप्रबंधक को निर्देशित किया गया कि प्रीइंजीनियर्ड स्ट्रक्चर की मजबूती एवं गुणवत्ता की आईआईटी रुड़की व सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की से जांच कराकर रिपोर्ट शासन को तत्काल उपलब्ध कराएं. बैठक में नई टिहरी के टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के निर्माण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की गई. महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून, पिथौरागढ़, गोपेश्वर व उत्तरकाशी के प्रौद्योगिकी संस्थानों के भवनों का काम अब तक शुरू नहीं हुआ उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के रवैये पर सचिव तकनीकी शिक्षा ने जताया कड़ा ऐतराज जल्द निर्माण शुरू करने के निर्देश दिये. निगम का रवैया नव दिन चलै ढ़ाई कोस की कहावत को चरितार्थ कर रहा है. -रेनु शर्मा

नेताओं की शह पर बढ़ रहा है देहव्यापार

सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

देवभूमि के नाम से विख्यात उत्तराखंड में सफेदपोस नेताओं की संलिप्तता से देहव्यापार का धन्धा धड़ल्ले से पनप रहा है. उत्तराखंड के रामनगर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए संचालिका और पांच युवतियों को धर दबोचा. रैकेट की संचालिका ऊधमसिंह नगर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला महामंत्री है. उसकी दो बेटियां भी गिरोह में शामिल हैं. सभी के खिलाफ देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पकड़ी गई एक महिला के पांच वर्षीय पुत्र को पुलिस ने उसके पिता के सुपुर्द कर दिया है. गिरोह के पास से छह मोबाइल, नगदी और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई.

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के प्रभारी डीएल वर्मा ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने विजय नगर नई बस्ती काशीपुर निवासी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला महामंत्री से कुछ दिन पूर्व मोबाइल पर बात की. उन्होंने खुद को सर्राफा व्यवसायी बताते हुए कहा कि उनके दोस्त दिल्ली के 10 सर्राफा व्यवसायी दीपावली के बाद कार्बेट पार्क घूमने आ रहे हैं. उन्होंने अपने दोस्तों के लिए पांच युवतियों की डिमांड की. इस पर भाजपा नेत्री से 70 हजार रुपए में डील तय हो गई.

सेल प्रभारी वर्मा ने बताया कि जब भाजपा नेत्री से युवतियां उपलब्ध कराने की बात की गई तो उसने 25 हजार रुपये उसके बैंक अकाउंट में डालने को कहा, जिस पर उसके बैंक अकाइंट में 25 हजार रुपये जमा कराए गए. इस पर उसने काशीपुर में 31 अक्टूबर को मिलने की बात कही. काशीपुर में सर्राफा व्यवसायी बने सेल प्रभारी वर्मा ने भाजपा नेत्री और उसके साथ आई पांच अन्य युवतियों को अपनी कार में बैठाया. उसके बाद वे काशीपुर से ढ़िकुली के लिए रवाना हो गए. उन्होंने बताया कि इसी बीच आमडंडा पर पहुंचकर वहां पहले से मौजूद टीम को इशारा कर दिया. टीम ने गाड़ी को घेर लिया. उसके बाद कार में बैठी संचालिका और युवतियों को कोतवाली लाया गया. सेल प्रभारी वर्मा की तहरीर पर देह व्यापार अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 7, 9, के तहत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया. पकड़ी गई युवतियों में गिरोह संचालिका व विजय नगर नई बस्ती काशीपुर निवासी शहनाज, रुखसाना, ग्राम पूछड़ी रामनगर निवासी सोनिया, कार्बेट कालोनी निवासी शमा परवीन और फरजाना है. (सभी नाम काल्पनिक हैं) भाजपा के जो नेता पकड़ी गई महिला को गरबहिया करके घुमते थे, वे भी अब उससे पल्ला झाड रहे हैं. ■

सेल प्रभारी वर्मा ने बताया कि जब भाजपा नेत्री से युवतियां उपलब्ध कराने की बात की गई तो उसने 25 हजार रुपये उसके बैंक अकाउंट में डालने को कहा, जिस पर उसके बैंक अकाउंट में 25 हजार रुपये जमा कराए गए. इस पर उसने काशीपुर में 31 अक्टूबर को मिलने की बात कही. काशीपुर में सर्राफा व्यवसायी बने सेल प्रभारी वर्मा ने भाजपा नेत्री और उसके साथ आई पांच अन्य युवतियों को अपनी कार में बैठाया.

-चौथी दुनिया ब्यूरो

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
रजत बेरी
अवध मशीनरी स्टोर्स
ग्रीकगंज, सीतापुर

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
अतुल गुप्ता
जिला संगठक कांग्रेस सेवादल
सीतापुर

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
जैन इण्टर प्राइजेज
सीतापुर

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
राम धर्मकांटा
लखीमपुर रोड, नैपालापुर
सीतापुर

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
दिनेश अग्रवाल
प्रमुख समाजसेवी
सीतापुर

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
रामपाल यादव
सपा विधायक
विधानसभा क्षेत्र बिसवां
जनपद सीतापुर
शमीम कौसर सिद्दीकी
जिलाध्यक्ष
समाजवादी पार्टी
सीतापुर